रहा है। 23 अगस्त को भाजपा युवा

मोर्चा की मोरहाबादी में आक्रोश रैली

के दिन ट्रैफिक सिस्टम के चरमराने

से लोगों को भारी दिक्कत उठानी

पड़ी। यहां तक कि कांके रोड पर

सीएम आवास के पास हाईकोर्ट के

जस्टिस एसके द्विवेदी भी घंटों में

जाम में फंसे रहे। ट्रैफिक जाम के

इस मसले पर सुबे के डीजीपी, रांची

के डीसी, एसएसपी और ट्रैफिक

एसपी मंगलवार को जस्टिस एसके

द्विवेदी की अदालत में सशरीर

उपस्थित हुए। झारखंड हाईकोर्ट के

अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया

कि 23 अगस्त को जाम में फंसने

की वजह से न्यायाधीश एसके द्विवेदी

की अदालत ने स्वतःसंज्ञान लिया

इस दौरान कोर्ट ने

मौखिक टिप्पणी करते

हुए कहा कि कांके रोड में

कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा

था। इसके बावजब वहां

300 से ज्यादा पुलिसकर्मी

तैनात थे। ऐसा लगता है

कि सब कुछ साजिश के

तहत हो रहा था। जब

हाईकोर्ट का एक जज

Priyanka Chopra's

Brother Siddharth...

Ranchi ● Wednesday, 28 August 2024 ● Year : 02 ● Issue : 220 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com E-Paper : epaper.thephotonnews.com

कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान

सकता है. तो अंदाजा

लगाना मुश्किल नहीं है

कि आम लोगों की स्थिति

क्या रही होगी। बता दें कि

आक्रोश रैली के दिन

मोरहाबादी के चारों ओर

कंटीले तारो से फेंसिंग की

गई थी। नेताओं के भाषण

के दौरान पुलिस और

कार्यकताओं के बीच

दफोटोनन्यूज Published from Ranchi

: 81,711.76 निफ्टी 25,017.75

6,865

चांदी 93.05 (नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

जम्मू-कश्मीर में भाजपा की तीसरी लिस्ट में 29 नाम

SRINAGAR: मंगलवार को जम्म्-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 29 कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें सेकेंड फेज के 10 और थर्ड फेज के 19 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने 26 अगस्त को 5 घंटे में 3 लिस्ट जारी की थीं। सुबह 10 बजे जारी लिस्ट में 44 नाम थें, विरोध हुआ तो लिस्ट वापस ले ली। इसके दो घंटे बाद 15 नाम की नई लिस्ट जारी की। तीन घंटे बाद सिंगल नाम की एक और सूची आई। जारी तीसरी लिस्ट में पार्टी ने कल के 28 नाम रिपीट किए हैं। सिर्फ श्रीमाता वैष्णो देवी सीट से पार्टी ने रोहित दुबे की जगह बलदेव राज शर्मा को टिकट दिया है। जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। नतीजे ४ अक्टूबर २०२४ को आएंगे। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा ४६ है।

दिल्ली शराब नीति केस में के. कविता को जमानत

NEW DELHI: मंगलवार को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार औ मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्ड़े मामलों में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) लीडर के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस केस में जांच पूरी हो चुकी है। ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। के कविता 5 महीने से जेल में बंद हैं। महिला हैं और पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से अरेस्ट किया था। इसके बाद उइकने उन्हें 11 अप्रैल को कस्टडी में लिया था। इससे पहले के कविता १ जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए गई थीं। कोर्ट ने कहा था कि वो मुख्य आरोपी हैं और जांच अभी अहम मोड पर है।

केजरीवाल की न्यायिक हिरासत ३ सितंबर तक बढी

NEW DELHI: मंगलवार को दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत ३ सितंबर तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है। इसी वजह से लंच करने की इजाजत मांगी है। सीबीआई ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने एक हफ्ते ही हिरासत बढाई। इससे पहले 20 अगस्त को लोअर कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को

सिर्फ नेता-मंत्री को मिलता है स्पेशल ट्रीटमेंट

PHOTON NEWS RANCHI: जज के जाम में फंसने पर हाईकोर्ट सख्त, लगाई फटकार राजधानी रांची के ट्रैफिक सिस्टम का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा भाजयुमो की आक्रोश रैली के दिन चरमरा गई थी ट्रैफिक

• कहा- राज्य में कानून व्यवस्था फेल, सशरीर हाजिर हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता

• विस्तृत सुनवाई के लिए मामले को भेजा गया एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास

था। उन्होंने विस्तत सनवाई के लिए ने कहा कि ऐसा लगता है कि मामले को हाईकोर्ट के एक्टिंग सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मंत्रियों और चीफ जस्टिस के पास भेज दिया राजनीतिज्ञों के लिए है। जब हाईकोर्ट के जज सुरक्षित नहीं हैं

झड़प भी हुई थी। तो दुसरे कोर्ट के जज भी असरक्षित होंगे। इसपर डीजीपी की

विज्ञापनों से जुड़े केंद्र के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

NEW DELHI : मंगलवार को सुप्रीम

कोर्ट ने इग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियम 170 हटाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इससे जुड़ा आयुष मंत्रालय का नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया है। नियम १७० आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाता है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र को फटकार लगाई। कहा कि मंत्रालय का नोटिफिकेशन उसके ७ मई, २०२४ के आदेश के खिलाफ है। सरकार कोर्ट के आदेश के बावजूद नियम 170 हटाने का फैसला कैसे कर सकते हैं? दरअसल, केंद्र ने 29 अगस्त, 2023 को एक लेटर जारी किया था। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियम १७० के तहत कंपनियों पर कोई

कार्रवाई शुरू या नहीं करने को कहा

सभी गरीबों का माफ होगा बकाया बिजली बिल, हेमंत का एलान



मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम में लामुकों के बीच सीएम हेमंत सोरेन

PHOTON NEWS DUMKA: मंगलवार को संथाल परगना के

जामा प्रखंड की पांजन पहाड़ी में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करने का एलान किया। उन्होंने कहा राज्य में जो लोग आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं, उन सभी लोगों का बकाया बिजली बिल किया जाएगा। मुझे मध्यवर्गीय लोगों की चिंता है। अपने संबोधन में उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हमारे विरोधियों के पास नेता नहीं है, उन्हें दूसरे राज्यों से नेता लाना पड़ रहा है। विरोधियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान विधायकों को तोड़ा, अब विधानसभा में भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत ने कहा कि असम से लोग आ रहे हैं। इन नेताओं का काम है विधायक तोड़ो, हिंदू-मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर समाज को लड़वाते

• संथाल परगना के जामा प्रखंड की पांजन पहाड़ी में मख्यमंत्री ने लोगों को किया संबोधित

• कहा– हमारे विरोधियों के पास नेता नहीं, उन्हें दूसरे राज्यों से लाना पड रहा लीडर

• केंद्र पर १ लाख ३६ हजार करोड रुपये बकाया

रहे। लेकिन, भगवान श्रीराम ने आईना दिखा दिया। इस राज्य का एक लाख 36 हजार करोड़ केंद्र पर बकाया है। चिट्ठी भेजकर पैसा मांग रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोयला, तांबा, अभ्रक हमारे खलिहान से निकलेगा और हमें पैसा नहीं मिलेगा। अब कंपनी मुआवजा और रोजगार नहीं देगी, तै उसे यहां से जाना होगा।

विपक्ष पर निशाना बनाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिलेंडर बांटा, अब गैस का पैसा ले रही है। अफीम की तरह पहले लत लगाते हैं, फिर गरीबों की जेब पर डाका डालते हैं। केंद्र के पास गरीब जनता के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कारोबारियों का ऋण माफ करने के लिए पैसा है। सीएम ने कहा कि सेना, रेलवे, बैंक और कोल इंडिया में नौकरी नहीं है। नौकरी को लेकर सारा ठीकरा राज्य सरकार फोडा जा रहा है। हमारी सरकार ने नौकरी का लकर कानन बनाया आर हजारा की संख्या में नियुक्ति की । हम स्थानीय लोगों की नौकरी देना चाहते



हैं, लेकिन हमारे फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाती है। हेमंत सोरेन ने महिलाओं से पूछा- क्या आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चुनाव के बाद हम हर घर में एक लाख पहुंचाने का लक्ष्य रखे हैं। हमारे विपक्ष के लोग बड़े-बड़े विज्ञापन देकर बताते हैं चार साल में क्य हुआ। राज्य के ४० लाख बुजुर्गों को

आज झारखंड आने के बाद झामुमो व मंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा

चम्पाई ने किया एलान- बेटे के साथ थामेंगे भाजपा का दामन

मंगलवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने अंततः खुद एलान कर दिया कि वह अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल होंगे। भाजपा में जाने का रास्ता सोमवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद साफ हो गया था। चम्पाई 30 अगस्त को भाजपा शरणम गच्छामि होंगे। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसकी पृष्टि कर दी। बुधवार को चम्पाई झारखंड लौटेंगे। इसके बाद मंत्री पद और झामुमो से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद अपने क्षेत्र सरायकेला जाएंगे। फिर रांची लौटेंगे और भाजपा में शामिल होंगे। चम्पाई ने कहा कि इससे पहले 18 तारीख को जब यहां आए थे तो अपना विचार दे दिया था। पहले मैंने संन्यास लेने की सोची थी, लेकिन बाद में जनता और कार्यकताओं का हौसला और उनकी मांग को देखते हुए सोचा कि सक्रिय रूप से

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद भाजपा में एंट्री का साफ हो गया था रास्ता

• कहा– पहले संन्यास लेने की सोची, फिर जनता का हौसला देख शुरू किया नया अध्याय

• गुरुजी का स्वास्थ्य टीक नहीं चल रहा, इसलिए नया रास्ता चुनने का लिया फैसला

• 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व सीएम दिल्ली में मीडिया को दी जानकारी

झामुमो ने बताया आत्मघाती कदम



किसी बात को लेकर नाराजगी थी, तो उन्हें बात करनी चाहिए थी। विनोद पांडे ने तंज कसते हुए कहा का कार्यकर्ता सिर्फ सहयोग

कोई कुछ भी कहे, जवाब देना उचित नहीं समझता अध्याय शुरू करने का फैसला किया है। चम्पाई ने आगे के क्या प्लान है, के सवाल पर कहा कि 28 अगस्त झारखंड जा रहे

हैं। मेरा इतिहास आईने की तरह साफ है

देना हम उचित नहीं समझते हैं।

इसलिए कोई कुछ भी कहे, उसका जवाब

कि संगठन व्यक्ति विशेष से नहीं चलता। किसी भी स्तर

ही केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। दिल्ली से लौटते ही उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिल जाएगी। अब चम्पाई सोरेन की सुरक्षा में 33 जवान तैनात रहेंगे। मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय समय-समय पर नेताओं की सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा करता है। इसके बाद तय करता है कि किस नेता को किस श्रेणी की सुरक्षा देनी है। बता दें कि चम्पाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने को भाजपा पूरी तरह भुनाने के मूड में है। प्रदेश भाजपा के नेता इसे लेकर उत्साहित अभिनंदन व स्वागत समारोह का आयोजन करने की बात कही जा रही है।

• बीजेपी में शामिल होने से

पहले ही पूर्व सीएम को

मिली जेड प्लस श्रेणी की

मिलेगी हाई सिक्योरिटी

पूर्व मुख्यमंत्री के बीजेपी में जाने के पहले

दिल्ली से लौटते ही

सुरक्षा

ऑटो ड्राइवर ने पीने के लिए दिया था पानी

अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग स्टूडेंट से दुष्कर्म

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस के बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग कॉलेज की स्टडेंट से रेप का केस सामने आया है। यहां एक ऑटो ड्राइवर ने नशीला पदार्थ मिलाकर पीडित को बेहोश किया और जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप किया। नर्सिंग स्टूडेंट ने बताया, 25 अगस्त को छट्टी थी। मैं अपने घर देवरुख चली गई। हमेशा की तरह सोमवार (26 अगस्त) सुबह छह



चम्पई ने कहा- सोचा था कि नया संगठन

बनाएंगे, लेकिन समय की कमी और

झारखंड प्रदेश की अलग परिस्थिति को

देखते हुए मंथन करने के बाद भारतीय

जनता पार्टी में जाने का निर्णय ले लिया।

मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री

बजे की बस से देवरुख से रतागिरी पहुंची। सुबह करीब सात बजे वह रत्नागिरी के साल्वी स्टॉप पर उतरी। कॉलेज जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। रास्ते में ऑटो ड्राइवर ने पानी दिया, जिसे पीने के बाद मैं बेहोश हो गई।

बदलापुर यौन शोषण केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा

अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है।

भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा बाबुलाल

सोरेन भी शामिल होगा। चम्पाई ने कहा

कि पार्टी के बड़े नेता गरुजी का स्वास्थ्य

ठीक नहीं रहता है और वो ठीक से बोल

नहीं पाते हैं। इसलिए हमने अब एक नया

MUMBAI: महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल के अंदर 2 बिच्चयों के साथ हुए यौन शोषण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में प्रोसीजर फॉलो न करने पर पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा- पुलिस ने बच्ची और उसके परिवार को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जो असंवेदनशील और नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि स्कल में चाइल्ड हेल्पलाइन थीं या नहीं और स्कूल में काम करने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक किया गया या नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने बच्चियों की क्लास टीचर को लेकर पूछा कि टीचर ने बच्चियों को एक पुरुष के साथ वॉशरूम भेजा।

कोलकाता रेप-मर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च, ममता से मांगा इस्तीफा

विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज, दागे आंसू गैस के गोले

AGENCY KOLKATA:

मंगलवार को ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल की मख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सडकों पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने इसे 'नबन्ना अभियान' नाम दिया। इसे रोकने के लिए सरकार ने 6000 पुलिस जवान तैनात किए। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। रैली दोपहर करीब 12.45 बजे शुरू हुई, लेकिन नबन्ना तक नहीं पहुंच सकी। इसकी वजह पुलिस की बैरिकेडिंग रही। कई रास्तों को

बंद किया। ड्रोन से निगरानी की गई। छात्रों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी।

पुलिस बोली- रैली गैरकानूनी, कार्रवाई के खिलाफ भाजपा का आज बंगाल बंद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर फेंके पत्थर

रैली में शामिल कई छात्रों को हिरासत प्रदर्शनकारियों ने 'नबन्ना अभियान' के में लिया गया। नबन्ना, पश्चिम बंगाल तहत राज्य सचिवालय की ओर मार्च करने की कोशिश की। पलिस ने

सरकार का अस्थायी सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर बैठते हैं। राइटर्स बिल्डिंग स्थित सचिवालय का रेनोवेशन चल रहा है। हावड़ा मैदान इलाके में जीटी रोड पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच उस समय फिर से झड़प हुई, जब

प्रदर्शनकारियों को तितर–बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान पानी की बौछारों और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर और ईंटें फेंकी।

इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाई। पुलिस किया। भीड़ को तितर-बितर करने की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े

बीएसएफ ने वेबसाइट बनाकर जारी की है इस प्रकार की सुविधा

ऑनलाइन ई-पास से देखिए भारत-पाकिस्तान बॉर्डर

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर देखने के लिए अब विशेष सुविधा की व्यवस्था की गई है। जैसलमेर से लगती भारत-पाकिस्तान सीमा को लोगों को देखना

अब अधिक आसान हो गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने वेबसाइट बनाकर अब बॉर्डर देखने के लिए ऑनलाइन ई-पास बनाने की सुविधा जारी कर दी है। अब भारतीयों को सरहद जाना आसान हो सकेगा और वे जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर को देख सकेंगे। ऑनलाइन ई-पास की जानकारी देते हुए बीएसएफ डीआईजी नॉर्थ सेक्टर योगेंद्र सिंह राठौड ने बताया कि अगर आप जैसलमेर घूमने का प्लान कर रहे हैं,तो भारत-

पाकिस्तान सीमा आसानी से देख सकते हैं। अब बॉर्डर देखने के लिए आवश्यक पास लेने के लिए तनोट माता मंदिर में लाइन में खडे होने की जरूरत नहीं हैं।

पास लेने के लिए तनोट माता मंदिर में लाइन में खड़े होने की अब जरूरत नहीं



बीएसएफ डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सरहद पर तनोट क्षेत्र में तनोट और बबलियान वाला पोस्ट आकर्षण का केंद्र है, वहीं बॉर्डर पर जाने के लिए लंबी-लंबी कतारों से अब राहत मिलेगी। सीमा पर बीएसएफ की प्राथमिकता है कि सरहद पर आने वाले पर्यटकों का स्वागत से लेकर सीमा दर्शन करवाने का उद्देश्य रहता है, ताकि वह अच्छी यादें लेकर जाए।

पर्यटन सीजन का हो चुका है आगाज

दरअसल जैसलमेर में इन दिनों पर्यटन सीजन का आगाज हो चुका है। आने वाले दिनों में सैलानियों की भीड़ जैसलमेर में उमडेगी। फिलहाल सामान्य रूप से पर्यटकों की आवक शुरू हो गई है। ऐसे में यहां आनेवाला हर सैलानी बॉर्डर देखने की इच्छा रखता है। ऐसे में अब भारत-पाक बॉर्डर देखने वाले सैलानियों को तनोट में सीमा सुरक्षा बल की चौकी पर लाइन लगाकर पास बनवाने से छुट्टी मिल जाएगी। इसके लिएअब सैलानी ऑनलाइन ही आवेदन कर ई-पास जारी करवा सकते हैं।

आईडी कार्ड के साथ भरना होगा फॉर्म

इसमें सैलानियों को इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसमें पर्यटक को अपनी पूरी जानकारी अपने आईडी कार्ड के साथ भरकर सबमिट करनी होगी। इसके बाद ही ई-पास जारी होगा। फिलहाल जैसलमेर भ्रमण पर आए सैलानियों को बॉर्डर घुमने के लिए तनोट जाने के बाद ही बीएसएफ के काउंटर पर जाकर पास बनवाना पड़ता है। इसमें तनोट जाने के बाद वहां भीड़ होने पर सैलानियों को लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे में सुविधा देने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई हैं।

जम्मू-कश्मीर की डोरू सीट से किस्मत आजमाएंगे गुलाम अहमद मीर

RANCHI : झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर जम्मू-कश्मीर के डोरू विधानसभा सींट से किरमत आजमाएंगे। उन्होंने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मीर ने मंगलवार को परचा दाखिल किया। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। ट्वीट में कहा है कि मैंने डोरू विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मैं सभी कार्यकताओं और समर्थकों के अपार समर्थन के लिए उनका ऋणी हूं। बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में काँग्रेस और फारूक अबदुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मीर जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के शाहबाद-बाला तहसील के रहने वाले हैं। 2019 में उन्होंने डोरू संसदीय सीट से चुनाव लंडा था। 2015 में जम्मू–कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए मीर ने वर्ष 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल वे झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं।

3.9 मापी गई तीव्रता, पाकुड़ में रहा केंद्र

कई जिलों में महसूस किए गए भुकंप के झटके

PHOTON NEWS RANCHI: सोमवार देर रात झारखंड के कई

जिलों में भूंकप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार ये झटके संताल परगना वाले इलाकों पाकुड़, दुमका, देवघर, साहिबगंज के कई इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता की गति 3.9 मापी गई, जिसका केंद्र पाकुड़ बताया जा रहा है। हालांकि इन झटकों से किसी प्रकार की नुकसान की सूचना नहीं मिली है। झारखंड में भूकंप का असर बिहार के भागलपुर में महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने एक्स पर इस बात की जानकारी



देते हुए खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 12 बजकर 39 मिनट पर पाकुड़ के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किये गये हैं। जो कि केंद्र की जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। इस दौरान कई लोग सो रहे थे इसलिए बहुतों को इसके बारे में जानकारी नहीं हुई। सुबह जब लोग जागे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली।

गुमला के बसिया में लेवी की मांग को लेकर दिया घटना को अंजाम सड़क निर्माण के लिए बने कैंप पर

मानव तस्करी की शिकार सात लड़कियों को किया गया रेस्क्यू

BRIEF NEWS

KHUTI: जिले की छह नाबालिग और एक बालिग लड़िकयां जल्द ही अपने घर लौटेंगी और परिजनों से मिल पाएंगी। मानव तस्करों ने इन नाबालिग लड़िकयों को दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बेच दिया था, जिन्हें एएचटीयू की युनिट ने रेस्क्यू किया है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और यपी के विभिन्न जिलों की पुलिस और अन्य रिसोर्स के जरिए बेची गई नाबालिग लड़िकयों को रेस्कयू किया है। बताया जाता है कि खुंटी की इन नाबालिग लड़िकयों को दूसरे प्रदेशों में बड़े-बड़े सेठ के घरों में नौकरानी का काम कराया जाता था। खुंटी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बच्चियों के लापता का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने बाल कल्याण समिति और एएचटीयू (एंटी ह्यूमन टैफिकिंग यनिट) के नेतत्व में एक टीम को देश की राजधानी दिल्ली समेत पंजाब के लुधियाना, यूपी और राजस्थान भेजा है। गठित टीम में बाल कल्याण समिति पदाधिकारी समिमदीन अंसारी, महिला थाना सह एएचटीयू प्रभारी फुलमनी टोप्पो और एएसआई रमजानुल हक शामिल हैं।

गिरिडीह पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार कर भेजा जेल

GIRIDIH: जिले के डमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्हाबार में वर्ष 2020 में निमार्णाधीन डिग्री कॉलेज में लगे वाहनों को फुंकने के मामले में पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि भाकपा माओवादियों ने लेवी मांग करने फिर लेवी की रकम नहीं मिलने पर डिग्री कॉलेज में निर्माण कार्य में प्रयोग में लाये जा रहे जेसीबी एवं मिक्सर वाहन में आग लगा दिया था। इस घटना में नक्सली सोनाराम हेम्ब्रम आरोपित था। गिरफ्तार आरोपित का कई नक्सली कांडों में आपराधिक इतिहास रहा है। काफी दिनों से पुलिस उसे तलाश रही थी।

मुहर्रम की चालीसवीं पर निकला जुलूस

PALAMU: मंगलवार को मुहर्रम की चालीसवीं को लेकर डालटनगंज शहर में जुलूस निकाला गया। जुलूस पहाड़ी मुहल्ला के कर्बला के मैदान से निकला। नेतृत्व मुहर्रम इंतेजामियां कमिटी के जेनरल खलीफा जीशान खान कर रहे थे। उनके साथ अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमिन के पलामू सदर मुस्तफा कमाल, पर्व जेनरल खलीफा इसराईल आजाद उर्फ मिन्टू आदि थे। गोल के दौरान लाठी खेली गयी। सम्मान समारोह भी हुआ, जिसमें हिन्दू एवं मुस्लिम समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। बेहतर खिलाडियों को परस्कत किया गया। गोल निकालने वाली कमिटियों कर्बला हुसैन, ब्रदर्श क्लब कनी राम, नौजवान हुसैन कमिटी सब्जी मार्केट समेत अन्य को भी शिल्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुहर्रम इंतेजामियां कमिटी के साथ केन्द्रीय रामनवमी समिति महावीर नवयुवक दल जेनरल के पदाधिकारी भी शामिल हुए।

किया। कई गाडियों के शीशे तोड

डाले और कैंप में सो रहे

कर्मचारियों को भी मारा-पीटा।

बताया जाता रहा कि अहले सुबह

10 से 12 की संख्या में

व बसिया सड़क का निर्माण कार्य

बंद करने की धमकी दी और कैंप में

खड़ी गाड़ियों पर हमला कर दिया।

उस वक्त कई कर्मचारी सो रहे थे।

उग्रवादियों के पहुंचने के बाद सभी

की नींद टूट गयी। इसके बाद

उग्रवादी सभी कर्मचारियों को घेरकर

पीटने लगे। छह कर्मचारियों को चोट

लगी है। बाकी कर्मचारी कैंप से भाग

लेवी की मांग को लेकर सिसई

हथियारबंद उग्रवादी आये थे।

उग्रवादी हमला, कर्मियों को पीटा **PHOTON NEWS GUMLA:** मंगलवार की सुबह करीब चार बजे जिले के बसिया में उग्रवादियों ने बसिया व सिसई प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क निर्माण के लिए बनाए गए कैंप पर हमला

कंस्ट्रक्शन द्वारा पुल बनवाया जा रहा

है। सडक की लागत 60 करोड

रुपये से अधिक की है। पुल का

काम अधुरा है। उग्रवादियों ने 40

लाख रुपये लेवी की मांग की थी।

लेवी नहीं मिलने के बाद मंगलवार

सड़क निर्माण के लिए बना कैंप, जहां हुई घटना • फोटोन न्यूज खड़े हुए। अभी तक कई फरार की सुबह नारेकेला जंगल की ओर कर्मचारी कैंप में वापस नहीं लौटे हैं। से उग्रवादी पुल निर्माण स्थल के गुमला जिले के बसिया प्रखंड के समीप बने कैंप पर पहुंचे और हमला पोकटा गांव के समीप विनोद जैन कर दिया। इधर, घटना की सूचना

पर बसिया अनुमंडल के एसडीपीओ मो. नजीर, इंस्पेक्टर व थानेदार घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल, घायल कर्मचारियों से पछताछ की जा रही है। सड़क निर्माण में लगे

चेतमा में तीन जेजेएमपी नक्सली गिरफ्तार

PHOTON NEWS PALAMU: झारखंड पुलिस ने नक्सल आपरेशंस में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस के जवानों ने तीन नक्सल उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। जेजेएमपी के तीन सदस्य उस वक्त पलाम् पुलिस के हत्थे चढ़े, जब वो लेवी वसूली कर रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी उग्रवादी हथियार से लैस होकर ब्लू रंग की अपाची बाइक से लेवी वसूलने व धमकी देने के उद्देश्य से तुंबागड़ा की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पलिस एक्शन में आयी। थाना क्षेत्र के चेतमा गांव की मुख्य सड़क पर जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान अपाची बाइक पर बैठे

संदिग्ध स्थिति में कुएं में मिले मां-बेटे के



दिशा बदल दी। इसके बाद पलिस जवानों ने तीनों का पीछा कर हथियार के साथ गिरफ्तार कर पास से एक राइफल, एक देसी कट्टा, छह गोली, तीन मोबाइल और अपाची बाइक बरामद की गयी है। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान विजय पासवान, अशोक यादव और अखिलेश कुमार के रूप में की गयी है। इन तीनों के पास से हथियार बरामद हुए हैं।

में आप सबों की समस्याओं को जानने आया हूं : गवर्नर

लोहरदगा में राज्यपाल ने ग्रामीणों से किया संवाद



अभिवादन स्वीकार करते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार । 🔹 फोटोन न्यूज

मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) चीरी, लोहरदगा में ग्रामीणों से संवाद किया। संवाद के दौरान राज्यपाल ने कहा कि देश की आजादी के इतने वर्षों के उपरांत भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर विभिन्न समस्याओं की जानकारी देखने को मिलती है। देश के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। एक समय था कि केंद्र से लोगों के विकास के लिए भेजे गये राशि का लाभ लाभुकों तक पूरा नहीं पहुंचता था। वर्तमान में प्रधानमंत्री लाभुकों के मध्य विभिन्न योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री सम्मान योजनाह्न संचालित है। ऐसा कोई परिवार तो नहीं है, जो निःशुल्क अनाज के लाभ की उपलब्धता से वंचित है और वे इस योजना के पात्र हैं। ग्रामीणों से कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे कभी पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे और लोगों के मध्य एलपीजी गैस की उपलब्धता के लिए पूर्णतः सक्रिय रहे हैं। वर्तमान में प्रत्येक

PHOTON NEWS LOHARDAGA:

केंद्र ८० करोड़ लोगों को उपलब्ध करा रहा है नि:शुल्क अनाज

राज्यपाल ने कहा कि देश के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भूख से न हो, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा ८० करोड़ लोगों को निः शूल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आप सभी के बीच यह जानने आया हूं कि आपको केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं, आपकी विभिन्न समस्याएं जान सकूं, ताकि इससे सरकार को अवगत कराकर इसका निदान किया जा सके। मैं आप सबका विकास देखना चाहता हं।

उपलब्धता हो, इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा हमारी माताओं-उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्यपाल ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि स्वच्छ पेयजल नितांत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल के समक्ष सखी मंडल के सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि सखी मंडल से जुड़ने से पूर्व उनलोगों की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन अब इससे जुड़ने के उपरांत आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

परिवार तक एलपीजी गैस की

४६ लाख की परिसंपत्तियों का किया वितरण

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चीरी कौशल विकास केंद्र में लगभग 46 लाख रुपये की परिसंपतियों का वितरण किया। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि मैं नेता की तरह भाषण देने नहीं आपकी समस्या सुनने तथ केन्द्र सरकार से संचालित विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेने आया हूं। केंद्र सरकार जो पैसा विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए भेजती है वह आमजनों तक पूरा पहुंचे यह सुनिश्चित करने का मेरा काम है इससे पहले राज्यपाल का कुडू पहुँचने पर उपायुक्त डॉ बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने स्वागत किया। नावाटोली में संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमां, उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावतँ, एसडीओ अमित कुमार, एसडीपीओ श्रद्धा टोप्पो और सीओ मधुश्री मिश्रा सहित जिले के वरीय अधिकारियों तथा अन्य मौजूद थे।

संदिग्ध आतंकी इश्तियाक से जुड़ी अल्ट्रासाउंड यूनिट सील

PHOTON NEWS HAZARIBAGH: स्वास्थ्य विभाग ने आइंडियल पैथोलॉजी के अल्टासाउंड यनिट को सील कर दिया है। दरअसल सिविल सर्जन कार्यालय के दस्तावेज में आइडियल पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड के रेडियोलॉजिस्ट के रूप में डॉ। इश्तियाक का नाम रजिस्टर्ड है। डॉक्टर इश्तियाक को झारखंड एटीएस ने रांची से अलकायदा इन सब-कांटिनेंट (एक्युआईएस) के

आतंकी के रूप में पकड़ा है। डॉक्टर इश्तियाक हजारीबाग आइंडियल पैथोलॉजी प्रत्येक दिन रविवार को छोड़कर आता था। दोपहर के 12:00 से 3:30 तक काम करने के बाद वह वापस रांची लौट जाता था। 5 दिसंबर आना-जाना लगातार बना हुआ था। हजारीबाग स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिली थी कि दो स्वास्थ्य कर्मी जो हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई IDEAL PATHOLOGY



सेवा दे रहे हैं, वे डॉक्टर इश्तियाक का नाम बदलकर दूसरे डॉक्टर का नाम एंट्री करने की फिराक में हैं। वर्तमान में भी सेवा दे रहे हैं। यह भी जानकारी मिल रही है कि जो कर्मी नाम हटाने के फिराक में थे उनकी ही पैरवी से डॉक्टर इश्तियाक को लाइसेंस निर्गत किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि आइडियल पैथोलॉजी के संचालक का पहले से ही इन दो कर्मियों से संदिग्ध आतंकवादी डॉक्टर इश्तियाक से संबंध था।

शव, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप **PHOTON NEWS KODERMA:** जिले के जयनगर थाना क्षेत्र

अंतर्गत तरवन गांव में मंगलवार को संदिग्ध हालात में एक कएं से 38 वर्षीर्या महिला और उसके 8 वर्षीय पुत्र के शव मिले। इस बाबत मृतका के पिता टीपन महतो ने पुत्री के ससुराल वालों पर हत्या कर शव को कुएं में डालने का आरोप लगाया है। थाने को दिए आवेदन में कटिया निवासी टीपन महतो ने कहा है कि पुत्री सुमन देवी की शादी 18 वर्ष पूर्व तरवन के उपेन्द्र यादव के साथ की थी।

ससुराल के लोग बराबर मारपीट और प्रताडित किया करते थे। उसकी बेटी का पति उपेन्द्र यादव, देवर राजेश यादव, ससुर दिलीप यादव, सास जसवा देवी, गोतनी सरिता देवी और ननद कंचन देवी जगह जमीन हडपने की नीयत से समन को प्रताडित करने लगे। विगत एक सप्ताह से



कुएं में शवों को देखते लोग।

जानकारी उसकी पुत्री ने फोन पर दिया था। इस बीच फोन से सूचना मिली कि उसकी पुत्री सुमन देवी और नाती प्रेम कुमार (08) की हत्या कर शव को छुपाने की नियत से कआं में डाल दिया गया है जबिक 12 वषीर्या नतनी प्रियांशु

चैंपियनशिप में मचाया धमाल

के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर जांच-डंबल जिम के 10 प्रतिभागियों ने डब्ल्यूपीसी ओपेन स्टेट

RAMGARH : डब्ल्यूपीसी झारखंड ओपेन स्टेट चैंपियनशिप 2024 पावरलिफ्टिंग बेंच डेडलिफ्ट में रामगढ के प्रतिभागियों ने धमाल मचाया। गिरिडीह में आयोजित दो दिवसीय स्टेट लेवल चैंपियनशिप में रामगढ़ के पहलवानों का जलवा रहा। रामगढ़ से 10 प्रतिभागी ने भाग लिया जिसमें छह लड़िकयां और चार लडके शामिल है। अंजली सिंह चौहान ने जुनियर कैटेगरी में फल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल ,बेंच प्रेस में सेकंड पोजीशन गोल्ड मेडल एवं डेडलिफ्ट फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडल जीता। सृष्टि सिंह चौहान ने जनियर कैटेगरी में फुल पावर लिफ्टिंग में सेकंड पोजीशन, बेंच प्रेस में फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडल, डेडलिफ्ट में फर्स्ट पोजीशन गोल्ड

पांकी को विकास के नए आयाम पर करूंगा खड़ा : विनोद सिन्हा



PHOTON NEWS PALAMU: पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के करीबी कुशवाहा विनोद सिन्हा ने पांकी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। मंगलवार को मेदिनीनगर के बाइपास रोड में पत्रकारों से बात करते हुए कुशवाहा विनोद सिन्हा ने कहा कि पांकी विधानसभा क्षेत्र को विकास के नये आयाम पर खडा करके दिखाउंगा। पांकी के लोग जातपात में उलझे हुए हैं। वोट को लेकर यहां इस तरह की

भी गायब है। मामले की सूचना

पाकर थाना प्रभारी विकास कुमार

घटनास्थल पर पहुंचे और मां-पुत्र

पासवान दलबल

राजनीति होते आई है, लेकिन वे सभी वर्गों का ख्याल करते हुए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। विनोद ने कहा कि वर्ष 2013-14 में उन्होंने पांकी क्षेत्र का दौरा किया था। उस समय भी चुनाव लड़ने की तैयारी थी, लेकिन पूर्व सीएम मध कोडा के केस में उनका भी नाम रहने के कारण वे चुनाव नहीं लड़ पाए थे। लेकिन वर्ष 2024 में परिस्थितियों बदली हुई है। राजनीतिक साजिश के तहत मधु कोड़ा को फंसाया गया था।

कुल 180 युवाओं, जिसमें प्रत्येक

प्रखंड से 30-30 युवाओं का

चयन किया जाएगा। उपायुक्त ने

इस परियोजना के तहत कुल 77

लाख 27 हजार 400 रुपये की

स्वीकृति दी है। इसमें 75 फीसदी

यानी 57 लाख 95 हजार 550

रुपये की राशि डीएमएफटी के

माध्यम से दी जाएगी। शेष 25

फीसदी यानी 19 लाख 31 हजार 850 रुपये योजना से जुड़ने वाले

युवाओं को देना होगा। अमीन

प्रशिक्षण के तहत प्रत्येक युवा पर

42 हजार 930 रुपये का खर्च

सिरप की खरीद-बिक्री में शामिल तीन गिरफ्तार PALAMU: नशे के लिए प्रतिबंधित सिरप की खरीद बिक्री में शामिल तीन आरोपितों को गिरफ्तार

नशे के लिए प्रतिबंधित

किया गया है। ख़ुदरा सिरप बेचने के आरोप में तरहसी के शाहिद अफरोज (27) , नागेन्द्र प्रसाद (28) एवं मेदिनीनगर के आबादगंज नामधारी कॉलोनी के गौतम कुमार (27) को गिरफ्तार किया गया है। कुल 61 डब्बा (100 एमएल) सिरप बरामद किया गया है। तरहसी मुख्यालय सहित प्रखंड क्षेत्र में प्रतिबंधित सिरप की बिक्री धड़ल्ले से की जाती है। युवा इस सिरप से नशा करते हैं। पहले भी इस तरह की सिरप बरामद की जा चुकी है। तरहसी के थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निदेशींनुसार टीम गठन कर

जीवन को विस्तार देते हुए कई आयाम खोलता है खेल : प्राचार्या

ध्यानचंद की जयंती पर बिरसा कॉलेज, खुंटी में खेल दिवस मनाया गया और अंतर विभागीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कॉलेज की प्रभारी प्राचार्या प्रो जे किड़ो ने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए मेजर ध्यानचंद की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि उनके खेल में जाद था। सही मायने में वे हॉकी कें जादुगर ही थे। एक बार उनके पास गंद आ जाए, तो लगता था कि उनकी हॉकी स्टीक में जादु है। प्राचार्या ने कहा कि खेल जीवन को न केवल विस्तार देता है, बल्कि विभिन्न आयामों को भी खोलता है। उन्होंने सभी को खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। बिरसा कॉलेज के खेंल



प्रभारी राज कुमार गुप्ता ने बताया कि मैदान में 26 से 31 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी, शतरंज, क्रिकेट, हॉकी, बोरी रेस, कैरम बोर्ड जैसे विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता कें पहले दिन कबड़ी का आयोंजन किया गया, जिसमें बिरसा कॉलेज की टीम बी(महिला वर्ग) तथा पुरुष वर्ग के

भी टीम बी ने जीत हासिल की। इसके साथ ही वॉलीबॉल तथा हॉकी प्रतियोगिता की भी शुरूआत हुई। समारोह में प्रो चंद्र किशोर भगत, प्रो. जया भारती कुजूर, पूनम माई तिऊ, डॉ. अभिषेक, डॉ. मंजूषा पूर्ति, डॉ. अनंत राम, डाॅ. सी मिंज, वासुदेव हस्सा, डॉ. शीला, डॉ. नुपुर, काली मुंडू, डॉ. शिल्पी, सुशीला कुजूर, डॉ. रेशमा सहितकई विद्यार्थी मौजूद थे।

मेडल, हासिल की।

पंचायत में किया जाता है समस्याओं का समाधान, पीड़िता की होती है मनोवैज्ञानिक काउसलिग

अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ रही महिलाओं की टोली

PHOTON NEWS PALAMU: महिलाओं की एक ऐसी टोली जो अपराध और घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। महिलाओं की यह टोली कानूनी मदद के साथ-साथ महिला अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। घरेलू विवाद जैसी समस्या को पंचायत में ही समाधान किया जा रहा है। जबकि संगीन मामलों में पीड़ता को थानों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी ने राज्य भर में आजीविका न्याय सलाह केंद्र की स्थापना की है, जो पंचायत स्तर पर कार्य कर रही है। इस टोली में कानूनी जानकार के साथ-साथ कई सदस्य शामिल है। यह टोली महिलाओं से जुड़े, घरेलू हिंसा समेत अन्य अपराध के बारे में जागरूक करती है

कैसे काम करती है टोली

दरअसल, झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने क्लस्टर लेवल फेंडरेशन (सीएलएफ) का गढन किया है। एक सीएलएफ में 250 से 300 तक महिलाओं का एक समूह होता है और एक समूह में 15 से 25 महिलाएं होती है। प्रत्येक समूह में एक-एक बदलाव दीदी का चयन कियां जाता है, जो प्रत्येक बैठक में महिलाओं की समस्याओं को सुनती है और बाद में इस समस्या को ऑजीविका न्याय सलाह केंद्र के पास रखा जाता है। आजीविका समिति मामले को रजिस्टर्ड करती है और कानूनी पहलुओं को देखती है। पीड़ित महिला बदलाव दीदी या खुद से न्याय समिति के पास पहुंच सकती है।



और पंचायत के माध्यम से उसे केंद्र में 65 मामले पहुंचे। जिनमें सुलझाने का काम करती है। झारखंड के नक्सल हीट पलाम् से 61 मामलों का समाधान कर में पहले चरण में चार लिया गया है। जबकि एक मामला पुलिस को रेफर किया आजीविका न्याय सलाह केंद्र की स्थापना की गई है। पलामू के गया है। वहीं, अन्य मामलों में चैनपुर थाना क्षेत्र के बूढ़ीबीर में सुनवाई जारी है। न्याय सलाह केंद्र के बीआरपी अर्चना कुमारी महिलाओं की टोली ने न्याय सलाह केंद्र बनाया। जहां पिछले बताती हैं कि उनके पास घरेलू

हिंसा, डायन प्रताड़ना जैसे मामले पहुंचते हैं। वैसे मामले जो पंचायत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, उसपर पहल की जाती है। लेकिन जिन मामलों में कानुनी कार्रवाई की जरूरत होती है उन मामलों में पीड़िता को पुलिस और कानुनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

घरेलू हिंसा से निपटना चुनौती

झारखंड में घरेलू हिंसा और महिला अपराध से निपटना एक बड़ी चुनौती है। राज्य के कई इलाके अंधविश्वास से जुझ रहा है। झारखंड में 2018 से 2023 तक 14162 दुष्कर्म के मामले को रिकॉर्ड किया गया था। राज्य के विभिन्न महिला थाना में प्रतिदिन चार से पांच मामले घरेलू हिंसा से जुड़े हुए पहुंचते हैं। राज्य में प्रतिवर्ष करीब 35 हत्याप अंधविश्वास में होती है। पलामू के इलाके में घरेलू हिंसा के आंकड़े प्रतिवर्ष 1200 सबसे अधिक रिकॉर्ड किया जाता है। पलामू में 2023 के बाद से 115 से अधिक दुष्कर्म की घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है।

> आजीविका नया सलाह केंद्र से जुड़ी अनिता देवी बताती हैं कि पीड़ित महिला का पहला मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग किया जाता है। अगर मामला पंचायत के माध्यम से समाधान किया जा सकता है तो उस दिशा में पहल किया जाता है। पंचायत में मुखिया एवं अन्य प्रतिनिधि भी

शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि पीड़िता बदलाव दीदी के माध्यम से पहुंचती है या खुद केंद्र के पास पहुंचती है। इधर, पलाम् के एसपी रीष्मा रमेशन का कहना है कि जेएसएलपीएस की पहुंच गांव-गांव तक है। महिलाएं पुलिस की सहायता भी कर सकती है। लेकिन यह देखना होगा कि ऐसे मामले सीधे पुलिस के पास पहुंची है या नहीं। वहीं, गंभीर अपराध, डायन, बिसाही मारपीट के मामले पर पुलिस संज्ञान लेती है और कार्रवाई भी करती है। वहीं, पलामू के जेएसएलपीएस, डीपीएम शांति मार्डी का कहना है कि पंचायत में महिलाओं को कानुनी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है और उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। उनके समस्याओं का समाधान भी हो रहा है।

अमीन के लिए 15 दिनों में शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया : डीसी PHOTON NEWS RAMGARH:



रुपये का भुगतान डीएमएफटी मद से किया जाएगा। वहीं, 10 हजार 732.50 रुपये प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा को देने होंगे। परियोजना को स्वीकृति दिए जाने के उपरांत अगले 15 दिनों के अंदर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। परियोजना से जुड़ने वाले युवाओं को अमीन द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को लेकर कुल 810 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 200 घंटे की थ्योरी एवं 610 घंटे का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण शामिल होगा।













THE PH©TON NEWS www.thephotonnews.com

Wednesday, 28 August 2024

O BRIEF NEWS

आठ आईपीएस का तबादला दो को मिली पोस्टिंग

RANCHI: सरकार ने राज्य के आठ आईपीएस रैंक के अधिकारी का तबादला किया है। पोस्टिंग के लिए प्रतीक्षारत दो आईपीएस को भी प्रोन्नित मिली है। साहिबगंज एसपी के पद पर पदस्थापित कुमार गौरव को जहां लातेहार का एसपी बनाया गया है, वहीं होमगार्ड एसपी के पद पर पदस्थापित अमित कमार सिंह को साहिबगंज का एसपी बनाया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार की रात गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। कुमार गौरव को लातेहार एसपी के पद पर पदस्थापित किया गया। अंजनी कुमार झा को झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग एसपी के पद पर पदस्थापित किया गया। निधि द्विवेदी को एसपी जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया। लातेहार एसपी अंजनी अंजन को एसीबी रांची एसपी के पद पर पदस्थापित किया गया।

एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद

RANCHI: राजधानी की चान्हों थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान बोलेरो पिकअप वाहन से इंपीरियल गोल्ड कम्पनी का 2080 बोतल अंगेजी शराब बरामद किया है। डीएसपी अमर कुमार पांडेय ने मंगलवार को बताया कि चान्हों थाना क्षेत्र के एनएच-75 मुख्य मार्ग में पादुक पुल के समीप एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक बोलेरो पिकअप वाहन (जेएच01 बीई 5815) को रोका गया, जिसपर उक्त वाहन के चालक और एक अन्य व्यक्ति उक्त वाहन से उतरकर भागने लगे। उन्हें पकड़ने का फाफी प्रयास किया गया लेकिन दोनों व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए।

प्रधानमंत्री मोदी से मिले पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी



RANCHI: झारखंड के भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मलाकात की। दोनों के बीच झारखंड के वर्तमान हालातों पर चर्चा हुई।

निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन

RANCHI: मंगलवार को सामाजिक संस्था शारदा फाउंडेशन की ओर से ज्ञानोदय उच्च विद्यालय में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डेंटावीटा डेंटल क्लिनिक कांके रोड की डॉ सौम्या सिन्हा ने 200 से अधिक छात्राओ की दांतों की जांच कर उसकी देखभाल के लिए भी जागरूक किया। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शारदा फाउंडेशन ने डेंटावीटा डेंटल क्लिनिक के साथ मिलकर यह दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया।

बाजरा इलाके की घटना, गुस्साए ग्रामीणों ने माफिया को खदेड़ा

जमीन पर कब्जा को लेकर फायरिंग, जमकर बवाल

राजधानी रांची में जमीन माफिया के द्वारा कब्जे को लेकर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाजरा इलाके में जमीन कब्जा करने के नीयत से आए माफिया के द्वारा फायरिंग की गई है।

जमीन माफिया रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित एक कीमती जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। अवैध कब्जे को लेकर जमीन माफिया के द्वारा लगातार असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर काम किया जा रहा था। जबिक ग्रामीण लगातार जमीन माफिया का विरोध कर रहे हैं।

कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता।

PHOTON NEWS RANCHI:

मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

केशव महतो कमलेश ने संवाद

आपके साथ कार्यक्रम के तहत चतरा

और लातेहार जिलों में कार्यकताओं

के साथ संवाद किया। इसके पूर्व

इटखोरी भद्रकाली मंदिर में उन्होंने

पूजा-अर्चना की। चतरा में आयोजित

कार्यक्रम में भाजपा छोड़ सुभाष दास

ने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस की

सदस्यता ग्रहण की। कार्यकताओं के

साथ संवाद करते हुए केशव महतो

कमलेश ने कहा कि कांग्रेस

कार्यकताओं को स्पष्ट संदेश है कि

आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी

काग्रेस की नीति से युवाओं को

कराना होगा अवगत : केशव



जमीन माफिया को खदेड़ते ग्रामीण।

अधिक की संख्या में जमीन की गई। फायरिंग से आक्रोशित माफिया के पक्ष में कुछ महिलाएं होकर ग्रामीणों ने जमीन माफिया और असामाजिक तत्व बाजरा के पक्ष में आए लोगों को खदेड़ा स्थित जमीन पर कब्जा करने के और जमकर पीटा भी। ग्रामीणों के लिए पहुंचे थे। जब ग्रामीणों ने आक्रोश को देखते हुए जमीन जमीन माफिया का विरोध किया, माफिया के पक्ष में आए लोग मौके से फरार हो गए। इस मामले को इसके बाद जमीन माफिया की लेकर रांची के कोतवाली डीएसपी

शिश् सुरक्षा अधिनियम के महत्वपूर्ण कदमों को लागू करने पर हुई चर्चा

RANCHI: झारखंड पालोना की ओर से आयोजित नौवीं वर्चुअल मीटिंग में देश में शिशु सुरक्षा अधिनियम के महत्वपूर्ण कदमों को लाग करने पर गहन चर्चा की गई। भारत में शिशु हत्या, परित्याग और शिश् सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की चर्चा करते हुए समस्याओं की उच्च दर, अपर्याप्त रिपोर्टिंग और डेटा संग्रह, समर्थन सेवाओं तक सीमित पहुंच और सार्वजनिक जागरूकता की कमी पर प्रकाश डाला गया। मोनिका आर्य ने 2015 से पालोना के व्यापक रिपोर्टिंग और डेटा संग्रह कार्य पर जोर दिया। बताया कि झारखंड से शुरू होकर यह पहल अब हरियाणा, बिहार, पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और अन्य राज्यों तक पहुंच गई है। बेंगलुरु से ज्योति पांडे ने हर बैठक का दस्तावेज बनाने और रुचि रखने वाले व्यक्तियों के डेटा को इकट्ठा

उम्मीदवार होगा वह कांग्रेस का होगा। उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं। राज्य सरकार ने झारखंड के बहुमूल्य

• फोटोन न्यूज

किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा।

कार्यकताओं के मन में नहीं रहना

चाहिए। कांग्रेस की नीति, कार्यक्रम,

त्याग, बलिदान और गौरवशाली

इतिहास से युवाओं को अवगत

कराना होगा। कमलेश ने कहा कि

हमारी महागठबंधन की सरकार

जनता की सरकार है। भाजपा की

तरह अडानी और अंबानी जैसे

पूंजीपतियों की सरकार नहीं है।

झारखंड में किसानों का दो लाख का

ऋण माफ किया गया जबकि केंद्र की

भाजपा सरकार बड़े पुंजीपतियों का

औद्योगिक ऋण माफ कर रही है.

PHOTON NEWS RANCHI:

एलईडी स्क्रीन से युक्त वैन अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले जनजागरण पदयात्रा में लोगों को वीडियो के माध्यम से सरकार के वादों और हकीकत से रूबरू कराएंगे। मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड के बहुमूल्य पांच वर्षों को बर्बाद किया है। विकास की राह पर अग्रसर झारखंड को इन्होंने अपनी गलत कार्यशैली से पीछे धकेल दिया है। झूठे वादे कर सत्ता में बैठे लोगों से हम पूछना चाहते हैं

जनजागरण रथ को रवाना करते सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व अन्य। 🛭 फोटोन न्यूज

गांव वालों ने जारी किया वीडियो

वहीं ग्रामीणों के द्वारा जमीन माफिया जारी किया गया है। वीडियो में भगदड़ की जैसी स्थिति दिख रही है और रुक–रुककर गोलियां भी चल रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन माफिया के द्वारा उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसका वह विरोध कर रहे हैं।

प्रकाश सोय ने बताया कि ग्रामीणों की तरफ से लिखित शिकायत दी जा रही है। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा जारी किए गये वीडियो फुटेज की भी पड़ताल की जा रही है ताकि भू माफिया की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सके।

जांच-पड़ताल कर की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दीवार तोड़ने के विवाद को लेकर ऑटो परमिट के नियमों में बदलाव के खिलाफ उठाया कदम

बेमियादी हड़ताल पर गए १२,५०० ऑटो

दीवार तोड़ने के विवाद

में अधिवक्ता से मारपीट

RANCHI: राजधानी के अरगोडा

कॉलोनी निवासी और रांची

सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गौरेश

चंद्र झा से सोमवार को मारपीट की

गई। उन्होंने मारपीट करने वालों के

खिलाफ मंगलवार को अरगोड़ा

थाने में प्राथमिक दर्ज कराने के

लिए आवेदन दिया है। इस घटना

से रांची सिविल कोर्ट के वकीलों

में भी आक्रोश है। झा का मोहल्ले

के पड़ोसी से दीवार तोड़ने को

लेकर हुए विवाद हो गया। झा के

दीवार तोड़ने का विरोध करने पर

उनके पड़ोसी ने उनके साथ

मारपीट की। मारपीट में झा गंभीर

रूप से घायल हो गये। गौरेश चंद्र

झा को प्राथमिक उपचार के बाद

अस्पताल से छोड़ दिया गया है।

इस बाबत इंस्पेक्टर आनंद कुमार

मिश्रा ने बताया कि पूरे मामले की

क्षेत्र अंतर्गत हाउसिंग

व ई-रिक्शा चालक, परेशान दिखे यात्री

मंगलवार से राजधानी रांची में ऑटो परमिट के नियमों में बदलाव के विरोध में ऑटो चालकों ने आंदोलन शुरू कर दिया। 12,500 ऑटो और ई- रिक्शा चालक बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। इस कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, राजधानी में 20 किलोमीटर की परिधि में ऑटो चलाने के नियम में बदलाव के विरोध में चालकों की हड़ताल शुरू हो गई है। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के 20 किलोमीटर की परिधि में ऑटो चलाने के नियम में बदलाव करते हुए 4 जोन में ऑटो परिचालन का रूट बांट कर 3-3 किलोमीटर का दायरा बनाया है। इस कारण मंगलवार से 10 हजार से अधिक ऑटो और 2500 ई-रिक्शा चालक हडताल पर चले गए हैं। इस संबंध में



कानुन हाथ में लेने वालों पर होगी कार्रवाई: एसपी

दुसरी तरफ रांची के सिटी एसपी राजकमार मेहता ने ऑटो चालकों को स्पष्ट कर र्दिया है कि अगर वह बेवजह किसी चलते ऑटो में तोडफोड करेंगे या उन्हें रोकेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो ऑटो चालक शहर में परिचालन करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी तरह की किंदनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया कि ऑटो चालक खुद सड़कों पर उतरे हैं। चालक महासंघ के अनुसार पहले 17 किलोमीटर के दायरे में ऑटो

नियम में मात्र 3 किलोमीटर के दायरे में चलाने की इजाजत दी गई है, जो किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है। चालकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक किसी भी रूट पर ऑटो और ई-

रांची की सड़कों को शीघ्र दुरुस्त

राज्य सरकार से मांगा जवाब

झालसा के नए भवन निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट नाराज

मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट की सरक्षा से संबंधित कई जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) की हाईकोर्ट के निकट बनने वाले भवन के निर्माण में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई।

खंडपीठ ने सनवाई के दौरान मौखिक कहा कि वर्ष 2018 में इस भवन के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये की टेक्निकल स्वीकृति दी गई थी, जो वर्ष 2024 में 57 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह झालसा के नए भवन को बनाने के लिए में देरी क्यों कर रही है जबकि इसके लिए जमीन भी सरकार की ओर आवंटित कर दी गई है और जमीन की घेराबंदी भी हो चकी है। निर्माण में देरी करने से लागत राशि में बढ़ोतरी होती है। कोर्ट ने कहा कि झालसा के नए भवन बनने में छह वर्षों की देरी हो चुकी है,



जो पैसे खर्च होंगे जनता की कमाई के पैसे हैं। साथ ही कहा कि यदि राज्य सरकार की ओर से कारण स्पष्ट नहीं किया गया तो मुख्य सचिव को भी कोर्ट में बुलाया जा सकता है। झालसा के पुराने भवन में मेडिएशन सेंटर, ऑडिटोरियम जैसे कई आधारभूत संरचना की कमी है। राज्य के सिविल कोर्ट सुरक्षा एवं आधारभृत संरचना के संबंध में खंडपीठ ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने काउंसिल से पूछा है कि जिलों के बार भवन में सुरक्षा की क्या-क्या कमी है और कहां-कहां भवन बनाने की जरूरत है, इन सारे विषयों पर जवाब

संथाल परगना के छह जिलों के उपायुक्तों ने हाईकोर्ट को किया गुमराह : बाबूलाल

RANCHI: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबलाल मरांडी ने घसपैठ मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर मंगलवार को पोस्ट कर कहा कि संताल परगना के छह जिलों के उपायुक्तों ने हाई कोर्ट को गुमराह करने का काम किया है। मरांडी ने लिखा कि झारखंड में आदिवासियों की घटती आबादी एक कड़वी सच्चाई है। हालिया कुछ सालों के दौरान बांग्लादेशी मुसलमानों के अप्रत्याशित घुसपैठ के कारण आदिवासी समाज की आबादी में निरंतर गिरावट आयी है, जिस पर चिंता व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट ने संथाल परगना के उपायुक्तों से जवाब मांगा था लेकिन हेमंत सोरेन के इशारे पर संताल परगना के छह जिलों के उपायुक्तों ने आदिवासियों की घटती आबादी की हकीकत को छुपाकर हाई कोर्ट को गुमराह करने का काम किया है। आखिर हेमंत सोरेन इस सच्चाई को आदिवासी समाज से छपाकर उन्हें अंधेरे में

पांच वर्षों को किया बर्बाद : चंद्र प्रकाश

मंगलवार को आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष सह गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने जनजागरण रथ को हरमू स्थित आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।



कि उनके द्वारा किए गए कितने वादे पूरे हुए। पांच साल तक की जाती रही जनता के साथ धोखाधडी का यह मूल्यांकन का समय है। जनजागरण पद यात्रा के माध्यम से हम राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरकार की नाकामियों के बारे में लोगों को बताएंगे। इस मौके पर केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत, रांची जिला परिषद अध्यक्ष

सह केंद्रीय महासचिव निर्मला भगत, जिला परिषद सदस्य सह केंद्रीय सचिव राजेंद्र शाही मुंडा, बनमाली मंडल, हरीश सिंह, परवाज खान, डॉ. पार्थ पारितोष, सुनील यादव, दया शंकर झा, अब्दुल जब्बार अंसारी, अमित कमार, अभिषेक शुक्ला, प्रियांशु शर्मा, रोहित चौधरी समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मुख्य

पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश को एटीएस कोर्ट ने दी दो साल की सजा

RANCHI : एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को पीपल्स **PHOTON NEWS RANCHI:** लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के सुप्रीमो दिनेश गोप को दोषी करार करते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। मौत का भय दिखाकर लेवी वसूलने से जुड़े मामले में एटीएस कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया है। साथ ही अदालत ने उस पर बीस हजार का जुमार्ना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुमार्ना की राशि नहीं देने पर दिनेश गोप को अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी। एटीएस ने कोर्ट में छह गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तत किये. जिनके आधार पर कोर्ट ने दिनेश गोप को दोषी करार कर रहे थे।

करे नगर निगम : सनील कमार

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने रांची नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राजधानी की सड़कों की हालत सुधारें। जल्द से जल्द मरम्मत करने की दिशा में काम शुरू कर दें। इसके साथ सुनिश्चित करें कि सड़कों पर जल जमाव न हो। सचिव ने यह भी कहा कि मास्टर प्लान 2015 के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र और आईटी पार्क विकसित करने का प्रयास हो। वह मंगलवार को राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में रांची निगम क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा



समीक्षा बैठक करते नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार।

समीक्षा बैठक में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

• शहर की सड़कों में दिख रहे गड्ढों का तुरंत मरम्मत हो। • स्ट्रीट लाइट हर क्षेत्र में जले, यह

सुनिश्चित हो। यदि खराब है तो तुरंत बदलें और जहां लाइट नहीं है, वहां लाइट लगाएं। • इंटरसिटी बसों के लिए शहर में

है तो वहां नागरिक सुविधाएं

बेहतर किया जाए। • शहर में मास्टर प्लान 2015 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र और आईटी पार्क विकसित किए जाएं। • सड़कों के किनारे फुटपाथ का

प्रावधान जरूर रखें और निर्माण कराएं ताकि पैदल चलनेवाले भी बस टर्मिनल होना चाहिए। यदि लोग सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

पीवीटीजीएस ग्रुप व 85+ आयु वर्ग के वोटरों को जोड़ने के लिए चलाया गया स्पेशल कैंपेन

झारखंड में वोटरों की संख्या बढ़ी, नई लिस्ट जारी

राज्य में जारी मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का आंकड़ा मंगलवार (27 अगस्त) को जारी कर दिया गया है। निर्वाचन सदन, रांची में इससे संबंधित जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के आधार पर अभी राज्य की अनुमानित जनसंख्या 4,00,06,288 है। इसमें मतदाताओं की संख्या 2,57,78,149 है। अंतिम मतदाता सूची में पुरुष वोटरों की संख्या 1,30,65,449 जबिक महिला की 1,27,12,266 है। इसके अलावा थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 434 है। 22 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची की तुलना में 27 अगस्त को प्रकाशित सूची में



वोटरों की संख्या में 1।54% की वृद्धि दर्ज की गयी है। अंतिम मतदाता सूची में 18-19 आयु वर्ग में पुरुष वोटर्स की संख्या 4,80,760, महिला 5,93,959 और थर्ड जेंडर की 13 है। वर्तमान मतदाता सूची में मतदाताओं का फोटो कवरेज और एपीक कवरेज शत प्रतिशत है। मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा भी मौजूद थीं। वोटर्स की सुविधा के लिहाज से अलग अलग जिलों में कुल 53 नये मतदान केंद्र बनाये गये हैं। साहेबगंज, रामगढ, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, रांची, सिमडेगा जैसे जिले शामिल हैं

चलाया गया समावेशी सप्ताह अभियान

सीइओ ने बताया कि आयोग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वच्छ, त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने को सभी वर्ग के पात्र नागरिकों विशेषकर ट्रांसजेंडर, आदिम जनजाति समूह (पीवीटीजी), सेक्स वर्कर्स, 80+ आयु वर्ग, दिव्यांगजन और अन्य के लिए 29 जुलाई से 2 अगस्त तक समावेशी सप्ताह का आयोजन किया गया। २९ जुलाई को पीवीटीजी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वालों को मतदाता सूची में निबंधन करने को अभियान चलाया गया। 30 जुलाई को सभी रैन बसेरों, आश्रय गृहों में आवासित पात्र नागरिकों तथा सभी होमलेस (गृह विहीन) लोगों के लिए भी कैपेन चला। 31 जुलाई को दिव्यांगजनों तथा 1 अगस्त को 85+ आयु वर्ग के लोगों के लिए अभियान चलाया गया। 2 अगस्त को सभी पात्र ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर्स के लिए इसे चलाया गया।

जहां नये केंद्र बनाए गये। धनबाद के झरिया और रांची के हटिया में 6-6 मतदान केन्द्र में वोटरों की कमी के चलते उसे नजदीकी पोलिंग स्टेशन के साथ मर्ज कर दिया गया है। इस तरह से मतदान केंद्रों के मर्ज किए जाने, विलय- विलोपन तथा नये मतदान केन्द्रों के गठन के बाद राज्य में आयोग द्वारा

पूर्व में अनुमोदित 29,521 मतदान केन्द्र के स्थान पर अब मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 29562 हो गयी है। संतालपरगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और वोटरों की बढी संख्या पर सीइओ ने कहा कि इससे संबंधित मामला हाईकोर्ट में है। इस पर टिप्पणी देना उचित नहीं। आगे जैसा निर्देश आएगा,

पुरानी पेंशन योजना लागू करे केंद्र सरकार : सीदू

RANCHI: एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के उचित अधिकारों के खिलाफ एक धोखाधड़ी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों से छल किया है। ये बातें सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियंस के प्रतिक मिश्रा ने कहीं। उन्होंने कहा कि सीटू पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करता है। मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत थी। गैर योगदान आधारित और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की। तब से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्रीय ट्रेड यूनियन इसके खिलाफ संघर्षरत हैं और ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे है। सीटू ने एकीकृत पेंशन योजना की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की है।

आकर्षक अंदाज में मनाया गया कान्हा का जन्मोत्सव

PHOTON NEWS RANCHI: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर रांची के महात्मा गांधी मार्ग पर

आधी रात में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर दिखा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति द्वारा अल्बर्ट एक्का चौक पर आयोजित इस दो दिवसीय आयोजन में रांची के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह भी शरीक हुए। विधायक सीपी ने बताया कि 13 वर्ष पहले शुरू हुआ यह आयोजन आज भव्य रूप ले चुका है। अब राजधानी में जगह जगह उत्साह के साथ अलग अलग समूह भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को उत्साह से मनाते हैं। यह सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बेहद शुभ संकेत है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को सोमवार की तुलना में और भी ज्यादा भक्त मेन रोड में दिखेंगे और दही हांडी प्रतियोगिता भी होगी। उन्होंने बताया कि दही हांडी



मटकी फोड़ प्रतियोगिता में कई टीमें हिस्सा लेंगी और जीतने वाले को एक लाख रुपये का पुरस्कार इनाम स्वरूप दिया जाएगा।

वहीं कांके रोड स्थित इस्कॉन टेंपल में शाम से ही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम शुरू हो गया था। रात 12 बजते ही भगवान विष्णु के प्रभु श्रीकृष्ण के रूप में जन्म लेते ही पूरा परिसर कान्हा के आगमन की खुशियों से झूम उठा और भक्त भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगाते दिखे।

उत्क्रमित मध्य विद्यालय

एमबीएनएस के छात्र-

छात्राओं के नेतृत्व में

विद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए चित्रकला, संगीत,

समय से है। यहां हर क्षेत्र में

बारिश का पानी घरों में घुस

जाता है। इसे लेकर सांसद

बिद्युत बरण महतो के निर्देश

पर भाजपा उलीडीह मंडल

ने गुडरूबासा का दौरा

किया। कार्यकताओं ने पानी

स्थित तालाब में डबकर एक

व्यक्ति की मौत हो गई। बताया

फिसलने से गहरे पानी में चला गया. जिससे डबकर

समाचार सार एमबीएनएस के छात्रों ने मनाया सद्भावना दिवस JAMSHEDPUR : शहर स्थित एमबीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशन्स की एनएसएस इकाई की ओर से मंगलवार को चांडिल प्रखंड स्थित

क्विज समेत अन्य प्रतियोताओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर

प्राचार्या पिंकी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर दीपिका भारती, भवतारण भकत,

गुडरूबासा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखा हाल

JAMSHEDPUR: मानगो के उलीडीह में जलजमाव की समस्या लंबे

निकासी की समस्या का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष

रवींद्र सिंह सिसोदिया, संध्या नंदी, अनिमेष सिन्हा, राहुल कुमार, राकेश

कमल फूल तोड़ने गए व्यक्ति की डूबने से मौत

CHAKRADHARPUR: पश्चिमी सिंहभम जिले के चक्रधरपर में पोटका

मौत हो गई। मतक की पहचान हरि पडिया के रूप में की गई है, जो मल

रूप से ओडिशा के बालेश्वर का रहने वाला था। वह अपने रिश्तेदार के

घर पोटका में रहता था। वह रोज तालाब से कमल फूल तोड़ कर बाजार

में बेचता था। अब तक तालाब में तीन लोगों की मौत हो चुकी है।

प्रसाद, प्रसन्नजीत महापात्रा, जीतू गुप्ता, आकाश बोदरा आदि थे।

डॉली सिंह, मिली कुमारी, मधुसूदन महतो आदि उपस्थित थे।

पूर्वी सिंहभूम जिले में करीब 18 लाख ५४ हजार मतदाता

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की जानकारी

• जिले में लिंगानुपात 999 • 9 लाख 27 हजार 747 पुरुष, 9 लाख 26 हजार ८८३ महिला एवं १३७

थर्ड जेंडर मतदाता

• विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 15825

PHOTON NEWS JSR:

समाहरणालय सभागार मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा जानकारी दी गई कि द्वितीय संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसएसआर-2024) के तहत मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। मतदाता सूची का अवलोकन

JAMSHEDPUR : साकची से

मानगो जाने के लिए ऑटो में बैठी

12 वर्षीय किशोरी के साथ ऑटो

चालक ने छेड़खानी की। विरोध

करने पर ऑटो चालक ने किशोरी

को रास्ते में ही उतार दिया। इसके

बाद किशोरी ने अपने परिजनों को

घटना की जानकारी दी। इधर,

स्थानीय लोगों ने ऑटो चालक का

पीछा किया और उसे पकड़कर

उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने

आरोपी को पुलिस के हवाले कर

दिया। मामले को लेकर साकची

पुलिस ने किशोरी के परिजनों के

बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर

आरोपी मोहम्मद तैयब को जेल

भेज दिया है। पुलिस ने किशोरी

टेल्को से मानगो जा रही थी

किशोरी: किशोरी के पिता ने

बताया कि वे लोग नीलडीह में

रहते हैं। बेटी मानगो स्थित एक

चांडिल डैम से विमान का मलबा

निकालने वाली नौसेना की टीम

को जिला प्रशासन ने सम्मानित

किया। मंगलवार को आदित्यपुर

स्थित होटल क्रूज में उपायुक्त

रविशंकर शुक्ला एवं एसपी मुकेश

कुमार लुणायत ने टीम को प्रशस्ति

पत्र, गुलदस्ता और मेमेंटो देकर

ऑपरेशन में नेवी के सीडीआर

वरुण गुप्ता, जेजे सिंह, लेफ्टिनेंट

आरके पटेल, एमसीपी आरके

सैनी, एलएस सीडी आकाश, पीके

खरियावा, शुभम थांगे, अभिनव

सिंह, रिंक चाहर, अमरदीप,

गुरदीप सिंह, ओंकार, मुकुल,

शिवम केवट, युवराज, रोहित

कुमार, सोनू कुमार, सागर, रोहित

और ए रमेश शामिल थे। इस मौके

पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पूर्व

सम्मानित किया।

का मेडिकल भी कराया।



उपायुक्त के साथ पहचान पत्र दिखातीं बीएलओ

सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें 9

लाख 27 हजार 747 पुरूष, 9

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

मदरसा में पढ़ने के लिए जाती है।

वह हर सुबह ऑटो से साकची

और फिर साकची से मानगो जाती

है। आज वह साकची के एक

ऑटो पर अकेली बैठी थी। ऑटो

चालक ने उसे आगे बैठा लिया

और रास्ते में उसके साथ गलत

हरकत करने लगा। बेटी ने विरोध

करते हुए ऑटो चालक को रुकने

के लिए कहा और मानगो पुल के

पास ऑटो से उतर गई। इस दौरान

उसे दूसरे ऑटो वाले ने बिठाया,

विमान का मलबा निकालने वाली नौसेना

की टीम को डीसी-एसपी ने किया सम्मानित

प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार सिंह

भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने

ऑपरेशन में शामिल नेवी के

अधिकारियों एवं जवानों के कार्यों

की सराहना करते हुए कहा कि

बेहद ही चुनौती भरा कार्य था,

मगर जांबाज अधिकारियों के

निर्देशन में नेवी के जवानों ने

अभृतपूर्व काम किया। बता दें कि

20 अगस्त को सोनारी स्थित

जमशेदपुर एयरपोर्ट से उड़ा

अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनी

एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होकर

जिसे बेटी ने पूरी घटना बताई।

ऑटो चालक ने किशोरी से की

छेड़छाड़, किया पुलिस के हवाले

लाख 26 हजार 883 महिला एवं ईआरओ कार्यालय तथा जिला 137 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल सकते हैं। इसके साथ ही हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के ऑनलाइन माध्यम से भी मतदाता दौरान 20,748 मतदाताओं का नाम विलोपित किया गया है। अपने नाम की जांच कर सकते हैं। विधानसभावार बात करें तो उन्होने बताया कि मतदाता सूची बहरागोडा में कल 2 लाख 38 के फाइनल प्रकाशन में कुल 18 हजार 49, घाटशिला में 2 लाख लाख 54 हजार 767 मतदाता

48 हजार 753, पोटका में 3

लाख 8 हजार 74, जुगसलाई में

डायन के संदेह में

भतीजा ने चाची की गला

रेत कर दी हत्या, फरार

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम

जिले के गुवा थाना क्षेत्र में डायन

के संदेह में एक महिला की गला

रेत कर हत्या कर दी गई हैं। यह

घटना रविवार का है । जानकारी

के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले

के गुवा थाना क्षेत्र के बुरुसाई गांव

में डायन होने के संदेह में रिश्ते में

भतीजा लगने वाला कांडे पूर्ति ने

अपनी चाची 40 वर्षीय महिला

सुरु कुई की हत्या रविवार की

शाम धारदार हथियार से गला

रेतकर कर दी। मृतका गांव के

समीप उलीगोड़ा स्थित खेत में

काम कर रही थी। तभी इस घटना

को अंजाम दिया। घटना को

अंजाम देने के बाद आरोपी युवक

कांडे पूर्ति फरार हो गया था। घटना

की सूचना मिलने के बाद गुवा

थाना की पुलिस ने घटनास्थल से

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम

के लिये चाईबासा सदर अस्पताल

चांडिल डैम में गिर गया था। इस

घटना में कैप्टन जीत शत्रु आजाद

और प्रशिक्षु पायलट शुभ्रदीप दत्ता

की मौत हो गई थी। घटना के बाद

एनडीआरएफ और नौसेना ने

मिलकर दोनों शव को डैम से

निकाला और विमान को ढुंढ

निकालने के लिए सर्च अभियान

चलाया। विशाखापद्रनम से आई

नौसेना की टीम ने सातवें दिन

चांडिल डैम में गिरे दुर्घटनाग्रस्त

एयरक्राफ्ट को 12 घंटे के

मशक्कत के बाद बाहर निकाला।

जमशेदपुर पूर्वी में 3 लाख 33 हजार 227 तथा जमशेदपुर पश्चिमी में 3 लाख 78 हजार 166 मतदाता सूचीबद्ध हैं। इलेक्टोरल रोल अपडेशन के दौरान मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। जारी मतदाता सूची में जिले में लिंगानुपात 999 है, वहीं विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 15825 है। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ को पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया। 47-जुगसलाई के बुथ नंबर 164 की बीएलओ सुल्ताना खातून एवं बूथ नंबर 165 की बीएलओ पिरदौस खातन को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पहचान पत्र दिया। प्रेस वार्ता में उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह व जिला जनसंपर्क पदाधिकारी

पुराने विवाद को ले आदित्यपुर में थापा गैंग के सदस्य पर फायरिंग

SARAIKELA: सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सालडीह बस्ती में मंगलवार सुबह स्थानीय निवासी सभाष प्रमाणिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस घटना में सुभाष गंभीर रुप से घायल हो गया। घटना के बाद सुभाष की पत्नी भारती प्रमाणिक ने स्थानीय लोगों की मदद से सुभाष को तत्काल टीएमएच पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि गोली गले में लगी और बाईं ओर छाती में फंस गई है। वहीं दूसरी गोली बाएं कंधे को छुकर निकल गई। परिजन सुभाष को बेहतर इलाज के लिए कोलकाता ले गए। इधर, आदित्यपुर पुलिस ने पत्नी भारती के बयान पर सिट्ट,

ट्रिपल मर्डर का आरोपी है सुभाष

घटना में घायल सुभाष प्रमाणिक आदित्यपुर सतबोहनी में 7 जून 2022 को हुए आशीष गोराई, सुबीर चटर्जी और राजू गोराई हत्याकांड का नामजद आरोपी है। वह आदित्यपुर के संतोष थापा गिरोह का सदस्य है। इसके अलावा सुभाष कृष्णा गोप हत्याकांड का गवाह भी है।

रवि और टकलू समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं कई लोगों को पूछताछ के लिए

सारंडा के जंगल में आईईडी बरामद, पुलिस ने किया नष्ट

CHAKRADHARPUR

पश्चिमी सिंहभम जिले में नक्सलियों

हिरासत में भी लिया है। जा रहा है कि व्यक्ति कमल फूल तोड़ने के लिए तालाब में गया था। इसी दौरान पैर

के विरूद्ध अभियान के दौरान रविवार को सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना के सीमावर्ती पाटातोरब और चिड़ियाबेड़ा गांव के आसपास जंगलों में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए 5 और 3 किलो के 2 आईईडी बरामद कर उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर दिया गया। ज्ञात हो कि गत वर्ष अक्टूबर से संयुक्त अभियान गोईलकेरा और टोंटो थानान्तर्गत ग्राम कुईड़ा, छोटा कुईड़ा, मारादिरी, मेरालगड़ा, हाथीबुरु, तिलायबेड़ा, बोयपाईससांग, कटम्बा, बायहातु, बोरोय, लेमसाडीह के सीमावर्ती क्षेत्र तथा टोंटो थानांतर्गत ग्राम हसिपी, राजाबासा, तम्बाहाका, रेगडा, पाटातोरब, गोबरू, लईया के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रारंभ किया गया।

बंद माइंस खोलने की मांग पर आज जनसभा CHAIBASA : पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने मंगलवार को नोवामुंडी प्रखंड नोवागांव, पांड्राशाली सहित दर्जन भर गांवों का दौरा

जगाओं' को लेकर गीता कोड़ा ने कहा कि बंद माइंस खोलने को लेकर बुधवार को बड़ाजामदा में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इन मुद्दों को प्रमुख रूप से रखा जाएगा।

टाटानगर स्टेशन पर धराए 70 बेटिकट यात्री

मंगलवार दोपहर को औचक चलाया गया। इस दौरान लेकर उन्हें छोड़ दिया गया।

किया। भाजपा के बैनर तले



टिकट यात्रा करने के आरोप में पकड़ा गया। बेटिकट यात्रियों से जुर्माना

आरजेडीई निर्मला बरेलिया को दी श्रद्धांजलि

JAMSHEDPUR: धतकीडीह स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय

परिसर में मंगलवार को आरजेडीई निर्मला कुमारी बरेलिया को श्रद्धांजलि दी गई। 🖟 इस मौके पर झारखंड गैरसरकारी विद्यालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष मो. ताहिर हुसैन



के नेतृत्व में अयोध्या राम, डॉ अफरोज शकील, उदय शंकर अखिलेश सिंह, यशवंत सिंह पिंटू, सलीम गौशी, रफत आरा, राशिद इकबाल, जे शांता समेत कई शिक्षक-शिक्षिका व कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखा।

वर्तमान में बेरोजगारी बडी समस्या : अंबा प्रसाद

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर वीमेंस युनिवर्सिटी के बिष्टुपुर स्थित परिसर में मंगलवार को कैंपस सेलेक्शन था। इसमें मुख्य अतिथि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद उपस्थित थीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। युवा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, तभी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। महिला को भी सशक्त करने की आवश्यकता है। समाज में परिवर्तन लाने में इनकी भी अहम भूमिका है।

कल टाटानगर नहीं आएगी अहमदाबाद-हावडा

JAMSHEDPUR: गुजरात में अत्यधिक बारिश होने के कारण टाटानगर से होकर चलने वाली अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस 27 अगस्त को रद रहेगी। इसके कारण अहमदाबाद-हावडा एक्सप्रेस 29 अगस्त को टाटानगर नहीं आएगी। वहीं सांतरागाछी पोरबंदर एक्सप्रेस भी बदले मार्ग से चलेगी।

नेट की परीक्षा में परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही काफी कम

परीक्षा केंद्र पर जुटे परीक्षार्थी

• फोटोन न्यूज JAMSHEDPUR: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित यूजीसी-नेट की परीक्षा मंगवार को शहर के हाईवे स्थित इयान डिजिटल केंद्र में हुई। परीक्षा में परीक्षार्थियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत काफी कम रही। जानकारी के अनुसार जून में परीक्षा स्थगित करने के पश्चात अब तक एनटीए की ओर से परीक्षा से संबंधित सूचना जारी नहीं की गयी है। इस वजह कई परीक्षार्थियों को परीक्षा की तिथि व आयोजन की जानकारी नहीं है और वे इसमें शामिल नहीं हो सके हैं। जिन परीक्षार्थयों को यू-ट्यूब अथवा यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट देखी उन्हें परीक्षा की जानकारी मिली और वे इसमें शामिल हुए। बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से 21 से 30 अगस्त तक आयोजित इस परीक्षा का एडिमट कार्ड अपनी वेबसाइट पर जारी किया गया है। अतः आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करनेवाले परीक्षार्थियों को इसकी जानकारी मिली और वे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आएंगे सरायकेला

SARAIKELA : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को सरायकेला-खरसावां जिला आ रहे हैं, जिसमें वे गम्हरिया के रपचा फुटबॉल मैदान में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' के लाभुकों को स्वीकृति पत्र व सम्मान राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री रांची से सीधे कार्यक्रम स्थल पर हेलीकॉप्टर से दोपहर 12 बजे उतरेंगे। वहीं कार्यक्रम के बाद वे शाम 4 बजे वहीं से रांची रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के डीसी-एसपी सहित अन्य पदाधिकारी सक्रिय हैं, वहीं झामुमो कार्यकर्ता भी आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी सहित कोल्हान के सभी विधायक कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर



रहे हैं। मंगलवार को मंत्री दीपक बिरुवा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुवा ने जिला प्रशासन के पदाधिकारियों समेत पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर सांसद के अलावा विधायक निरल पूर्ति (मझगांव), सुखराम उरांव (चक्रधरपुर), दशरथ गागराई (खरसावां), संजीव सरदार (पोटका), रामदास (घाटशिला) व सविता महतो (ईचागढ़) आदि उपस्थित रहे।

विजय नदी में स्नान कर रहा युवक बहा तलाश जारी

CHAKRADHARPUR

पश्चिमी सिंहभूम जिले में मंगलवार को चक्रधरपर थाना क्षेत्र के बंगलाटांड़ स्थित विजय नदी में दोस्तों के साथ नहाने के दौरान 22 साल का युवक नदी की तेज धार में बह गया। घटना के बाद देर शाम तक खोजबीन जारी है। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर के बंगलाटांड़ निवासी अयुब मिस्त्री का 22 वर्षीय पुत्र अशरफ मंगलवार को अपने कुछ दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। इसी दौरान वह नदी की तेज धार में बहने लगा। कुछ दोस्तों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी खोजबीन शरू की। कई स्थानों और नदी घाट पर जाकर लोगों ने अशरफ की खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं

गोपाल मैदान में ब्रांड इंडिया ट्रेड फेयर ३० से, हुआ मूमिपूजन



भूमि पूजन के दौरान उपस्थित आयोजक

JAMSHEDPUR : आरएमएस आउटडोर की ओर से बिष्टुपुर स्थित गोपाल (रीगल) मैदान में 30 अगस्त से 8 सितंबर तक ब्रांड इंडिया ट्रेड फेयर लगाया जा रहा है। आयोजक मनोज नायक ने बताया कि इसमें एक ही स्थान पर उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। दिनेश भोल ने कहा कि मेले में लोग

वस्तुओं की गुणवत्ता संबंधित व्यवसायी से जान सकेंगे। भूमिपूजन के दौरान रवि मिश्रा, आदर्श कुमार, आमोद मिश्रा, मुकेश कुमार, अभिषेक बजाज, संजीत प्रमाणिक, अजय झा, देव कुमार, रवि कुमार, सुजीत गुप्ता, सुजीत सिंह, विशाल कुमार, अशोक कुमार, मदन दास, बिजय साह समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

केबुल टाउन क्षेत्र में हर घर बिजली के लिए कल झारखंड हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

आदित्यपुर स्थित होटल में नौसेना की टीम को प्रशस्ति पत्र देते डीसी व एसपी

जुस्को के उपभोक्ताओं को भी २०० यूनिट तक मिले मुफ्त बिजली : सरयू

PHOTON NEWS JSR:

जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मांग रखी है कि जैसे जेवीबीएनएल के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली पर सब्सिडी मिलती है, वैसे ही जुस्को क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट तक सब्सिडी मिले। जेबीवीएनएल महाप्रबंधक के कार्यालय में हुई बैठक में सरयू राय ने टेल्को आजाद मार्केट में जुस्को की बिजली का भी मुद्दा उठाया। इस पर ज़ुस्को के जीएम वीपी सिंह ने कहा कि जुस्को बिजली देने के लिए तैयार है। उपयुक्त फिजिबिलिटी के आधार पर जल्द ही नेटवर्क बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। बैठक में जुस्को के जीएम वीपी सिंह ने बताया कि केबुल टाउन क्षेत्र में हर घर बिजली के लिए 29 अगस्त को



विद्युत महाप्रबंधक के कार्यालय में बैठक करते सरयू राय

हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस सब-स्टेशन काम करना शुरू कर संबंध में आरपी को भी नोटिस

देगा। सितंबर के अंतिम हफ्ते तक दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोहरदा क्षेत्र के लिए सब-स्टेशन जुस्को बिजली देने के लिए तैयार का निर्माण एवं बिजली के खंभे है। एक हफ्ते के भीतर छायानगर लगाने का कार्य पूर्ण हो जाएगा। बर्मामाइंस के भक्तिनगर में सब-स्टेशन का उद्घाटन हो जाएगा और 15 सितंबर तक बागुनहातू नेटवर्क पूरा : सरयू राय द्वारा बिजली कनेक्शन के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि जुस्को नेटवर्क का काम पूरा हो गया है। अब वहां के निवासी जुस्को की बिजली के लिए आवेदन कर सकते हैं। जुस्को बिजली देने के लिए तैयार है। सिंह ने बताया कि नामदा बस्ती के आनंदनगर, विकास कालोनी आदि क्षेत्रों में जुस्को की बिजली के लिए सब-स्टेशन स्थल का सत्यापन कर लिया गया है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने विधायक सरयू राय को बताया कि भुइयांडीह, ग्वालाबस्ती, बाबुडीह, लालभद्रा, शांतिनगर, कानूभट्ठा, छाई बस्ती आदि क्षेत्रों के लिए नेटवर्क बिछाने का काम शुरू होगा। फिजिबिलिटी के लिए सर्वे किया जा रहा है।

बर्मामाइंस के भक्तिनगर क्षेत्र में

बारीडीह में सब-स्टेशन का स्थल चयन हुआ

वीपी सिंह ने विधायक सरयू राय को बताया कि बारीडीह बस्ती, बागुननगर डी ब्लॉक, टीओपी मैदान क्षेत्र के लिए सब-स्टेशन स्थल का चयन कर लिया गया है। अक्टूबर में एलटी नेटवर्क के लिए फिजिबिलिटी का सर्वे शुरू किया जाएगा. लक्ष्मीनगर, बजरंगीबागान, झगडू बागान, जेम्को, मिश्रा बागान आदि क्षेत्रों के लिए सब स्टेशन का स्थान फाइनल कर लिया गया है. बिरसानगर के लिए कंसल्टेंट बहाल करने हेतु चयन की प्रक्रिया जारी है।

बास की जगह लगाए जाएं कंक्रीट के खंभे

विधायक सरयू राय ने जेवीएनएल के जीएम से घरों के ऊपर से गुजर रहे तार और बांस के माध्यम से की जा रही बिजली आपूर्ति को ठीक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कई स्थानों पर नए ट्रांसफर्मर लगाने के लिए भी निर्देश दिया। इस पर जेवीएनएल के जीएम ने कहा कि अक्टूबर तक नए ट्रांसफर्मर लगा दिए जाएंगे। घरों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों को आरडीएसएस स्कीम के तहत ठीक कर लिया जाएगा। बैठक में विधायक के निजी सचिव सुधीर सिंह समेत जेबीवीएनएल के कार्यपालक अभियंता और कई पदाधिकारी मौजूद रहे।



क्या आप तैयार हैं फर्स्ट इंप्रेशन के लिए?

आज के समय में सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेना ही काफी नहीं है। जॉब पाने के लिए प्रोफेशनल एटिकेट्स की समझ– बूझ होना भी बहुत जरूरी है । इसी से आपकी एक इमेज भी बनती है। जब आप इंटरच्यूअर के साथ बैठते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन बनने में महज कुछ सेकंड का समय ही लगता है । इतने ही वक्त में आपके बारे में एक राय बन जाती है । भले ही इस दौरान आप एक भी शब्द न बोलें, लेकिन इंटरव्यूअर आपकी ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज को देखकर बहुत कुछ समझ जाते हैं।ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अच्छा इंप्रेशन बनाने को लेकर चौकस रहें।

'हाथ' देता है संदेश

एक – दूसरे से हाथ मिलाने के स्टाइल से भी आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को आंका जा सकता है । इसलिए हैंडशेक को कृतई हल्के में न लें । किसी व्यक्ति से मुलाकात के दौरान चेहरे पर मुस्कान रखना और आंख मिलाकर बात करना जितना जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है मजबूती और गर्मजोशी से हाथ मिलाना। इतना ही नहीं, हाथ मिलाते समय आप सामने वाले कों उत्साही भी दिखें। यह हैंडशेक सही ढंग से होना चाहिए, यानी न तो सामने वाले का हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ना चाहिए और न ही इसे ढीला छोड़ना चाहिए।आम तौर पर हैं डशेक के दौरान हाथ को दो-तीन बार हिलाना सही माना जाता है।

ड्रेसिंग-ग्रूमिंग पर ध्यान

प्रोफेशनल ड्रेसिंग और सोशल ड्रेसिंग मौके के हिसाब से उपयुक्त होना चाहिए। अगर आप पहली बार जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको यह फर्क समझना होगा। इंटरव्यू के लिए जाने हेतु पुरुषों के लिए डार्क कलर का ट्राउजर और लाइट कलर की फॉर्मल शर्ट ही श्रेष्ठ होती है । हल्की – फुल्की धारीदार शर्ट भी पहन सकते हैं । ऐसे मौके पर पैटर्न या डिजाइन वाले कपड़े पहनने से बचें। महिलाएं स्ट्रेट-कट कुर्ता पहन सकती हैं। चाहें, तो साड़ी भी पहन सकती हैं। मगर ध्यान रहे, इसमें ज्यादा तड़क-भड़क न हो। अगर वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहें, तो स्ट्रेट-कट, वेल फिटिंग ट्राउजर पहन सकती हैं।ऐसे मौकों पर एक्सेसरी व मेकअप के मामले में जितना सिंपल रहें, उतना बेहतर होता है।

रेज्यूमे में कॉपी-पेस्ट नहीं!

रेज्यूमे आपकी प्रोफेशनल लाइफ का आईना होता है। इसलिए इसको लेकर हमेशा गंभीरता बरतेँ। कई युवा अपना रेज्यूमे बनाते समय किसी दोस्त के रेज्यूमे को लगभग जस-का-तस कॉपी–पेस्ट कर देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। कारण यह कि हर व्यक्ति की शख्सियत और खासियत अलग होती है और इसी प्रकार हर जॉब के लिए अलग तरह के रेज्यूमे की जरूरत होती है। अगर कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसके रेज्यूमे को कॉपी-पेस्ट करके आप आईटी सेक्टर में जॉब के लिए आवेदन नहीं कर सकते। रेज्युमे में आपकी अपनी शख्सियत झलकनी चाहिए । इसमें आपके अनुभव, काम, हॉबी, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स आदि का उल्लेख हो । कोशिश करें कि इसमें स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियां बिल्कुल न हों।ऐसी गलतियों से आपके बारे में नकारात्मक इंप्रेशन बनता है।रेज्यूमे बनाने के बाद इसे किसी सीनियर या जानकार को एक बार जरूर दिखा दें ताकि उसमें कोई कमी रह जाने पर उसे दूर किया जा सके।

जॉब पाने के बाद

अगर आपको जॉब मिल जाती है. तो वर्कप्लेस पर विनम्र और मिलनसार बने रहना कर्ड मायनों में फायदेमंद होता है । शुरूआती दिनों में कोई शिकायत या दूसरों की आलोचना करने से बचें । अपना ध्यान सिर्फे काम पर लगाएं । जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसे बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करें। काम के प्रति प्रो-एक्टिव रवैया दिखाकर आप बॉस की नजर में अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं । सोशल मीडिया पर आजकल लगभग सभी सक्रिय हैं। मगर ध्यान रहे, अपनी ऑनलाइन इमेज साफ-सुथरी रखना जरूरी है क्योंकि आपके बारे में इंप्रेशन बनाने में इसका भी योगदान होता है।



कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते मार्केट रिसर्च बड़े उद्योग के रूप में उमर रहा है। यहां आपके लिए जॉब के कई अवसर है।



बाजार में किसी भी उत्पाद की लॉन्चिंग से पहले कंपनियों के जेहन में एक बात जरूर होती है कि लोगों को उनका उत्पाद पसंद आएगा या नहीं।लोग क्या पसंद करते हैं? उत्पाद की बिक्री कैसी रहेगी,? इन सवालों के जवाब पाने के लिए कंपनियां बाकायदा मार्केट रिसर्च कराती हैं। फिर मार्केटिंग की रणनीति बनाती हैं । ऐसा कमोबेश सभी कंपनियां करती हैं । यही वजह है कि बीते कुछ वर्षों में मार्केट रिसर्च की अहमियत बढ़ी है क्योंकि बाजार का मिजाज रोज बदल रहा है। किसी भी उत्पाद की लॉन्चिंग में कंपनियों के करोड़ों रुपए दांव पर लगे होते हैं। इसलिए कंपनियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहतीं। किसी प्रोडक्ट या सर्विंस की लॉन्चिंग/ रीलॉन्चिंग से पहले वे मार्केट सर्वे का सहारा जरूरी लेती हैं । मार्केट रिसर्च सोसायटी ऑफ इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में रिसर्च इंडस्ट्री की वर्तमान विकास दर करीब 10 प्रतिशत है। इसमें आगे और विस्तार की उम्मीद बनी हुई है क्योंकि देश में कंज्यूमर

कॉन्फिडेंस लगातार बढ रहाँ है। सर्वे का बढ़ता स्कोप मार्केट रिसर्च कंपनियों की सेवाएं निजी कंपनियों के साथ अब राजनीतिक दल भी खूब लेने लगे हैं। आम तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी व्यूह रचना और घोषणापत्र तक मार्केट रिसर्च के आधार पर ही तैयार करती हैं। चुनाव पूर्व सर्वे के जरिये जनता का मूड जानने की कोशिश भी की जाती हैं।टीवी चैनल्स और अखबारों में छपने वाले ओपिनियन पोल और एक्जिट पोल की लोकप्रियता से तो सभी वाकिफ हैं।

कैसे होती है मार्केट रिसर्च?

मार्केट रिसर्चर या एनालिस्ट का कार्य मुख्य रूप से सर्वे और रिसर्च से जुड़ा है। अपने तरीकों से ये प्रोफेशनल बाजार का मुड़ टटोलने की कोशिश करते हैं। दरअसल, यह भी एक मार्केटिंग रणनीति है। उत्पाद की लॉन्चिंग से पहले सर्वे कराने से यह पता चलता है कि प्रतिस्पर्धा में कौन-कौन-से उत्पाद हैं, उनकी कीमत क्या है, बिक्री क्या है? कंपनी की मार्केटिंग रणनीति क्या है ? बाजार में नए उत्पान की बिक्री का स्कोप क्या है ? साथ ही, कंपनियां यह भी जानना चाहती हैं कि लोग क्या पसंद करते हैं, उन्हें क्या नया पसद आएगा आदि । इन सभी सवाली का फीडबैक जुटाने के लिए मार्केट रिसर्चर एक क्वैश्चनेयर नुमा फॉर्म तैयार करते हैं । फिर कंज्यूमर सर्वे कराते हैं । ये सर्वे कई तरह से किए जाते हैं, जैसे टेलिफोन या इंटरनेट के जरिये या फिर ग्राउंड सर्वे । बाद में रिसर्च कंपनियां क्लाइंट कंपनी के लिए एक रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन तैयार करती हैं।मार्केट रिसर्चर के इन्हीं सुझावों के आधार पर आखिरकार कंपनियां अपने उत्पाद

या सेवा की लॉन्चिंग करती हैं।

बाजार के बदलते मिजाज पर रखिए नजर

पर्सनल स्किल

मार्केट रिसर्च के क्षेत्र में काम करने के लिए आपको डाटा एनालिसिस का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश पर अच्छी पकड़ भी होना जरूरी है । बेहतर सेल्समैनशिप और क्रिएटिव क्वॉलिटी भी रखनी होगी । साथ ही, अगर आप टीमवर्क की भावना और काम के प्रति लगन रखते हैं, तो बेझिझक मार्केट रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं।

जॉब प्रोफाइल

मार्केट रिसर्च का कार्य मुख्य तौर पर दो हिस्सों में बंटा है : फील्ड वर्क और रिसर्चे वर्क । इसलिए यहां अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के लिए जॉब के अवसर भी खूब हैं । रिसर्च एजेंसीज में आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग रेंसर्च, रिसर्च डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डाटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट, एनालिस्ट, फील्ड वर्क डायरेक्टर, फील्ड सुपरवाइजर आदि पदों पर जॉब पा सकते हैं।

कहा है जॉब्स?

मौजूदा समय में कई देशी – विदेशी कंपनियां आपको इस फील्ड में जॉंब दे सकती हैं। बड़ी कंपनियों में आपको विदेश में भी काम करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा केंद्र व राज्य

सरकारों के तमाम विभागों में भी मार्केट रिसर्चर की काफी मांग है। टेलीकॉम कंपनियों में भी जॉब की संभावनाएं हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंसल्टेंसी का विकल्प भी खुला है । अगर चाहें, तो एंटरप्रेन्योर बनकर खुद की रिसर्च एजेंसी भी खोल सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यताए

मार्केट रिसर्च के क्षेत्र में काम की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है । अगर करियर बनाना चाहते हैं, तो बीबीए या मार्केटिंग में एमबीए करके यहां एंट्री लें। साइकोलॉजी, सोश्योलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएट भी यहां करियर बना सकते हैं । कम्प्यूटर साइंस में ग्रेजुएट के लिए भी यहां करियर स्कोप है । कई संस्थान मार्केट रिसर्च के लिए डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं। वहीं, फील्ड वर्क के लिए न्यूनतम योग्यता १२वीं पास है।

रिसर्च कंपनियों में हर तरह के प्रोफेशनल्स को काफी आकर्षक सैलरी मिलती है। रिसर्चर या एनालिस्ट लेवल पर शुरूआत में ही 30 से 40 हजार रुपए महीना आसानी से मिल जाते हैं। अनुभव बढ़ने पर यह सैलरी 70 हजार से 1 लाख रुपए के आसपास भी पहुंच सकती है। फील्ड वर्क से जुड़े लोग भी शुरूआत में 10 से 15 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं।



बैंकों में नियुवित के लिए परीक्षाएं कराने वाली प्रमुख एजेंसियां, जैसे आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई भी कम्प्यूटराइन्ड ऑनलाइन फॉर्मेट में परीक्षा लेना या तो शुरू कर चुकी हैं या ऐसा करने की तैयारी में हैं। ऑनलाइन फॉर्मेट अपनाने पर परीक्षार्थियों और अकादमिक विशेषज्ञों दोनों की ओर से मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि कम्प्यूराइज्ड एग्जाम के कई फायदे हैं मगर कई लोगों ने इस आधार पर इसका विरोध भी किया है कि इससे कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी तक पहुच और उसमें सिद्धहस्तता के आधार पर विभिन्न परीक्षार्थियों में भेद किया जाता है।

जो युवा इस टेक्नोलॉजी से कम परिचित हैं, वे अन्य मामलों में योग्य होने हुए भी पिछड़ सकते हैं। कई ऐसे युवा भी हो सकते हैं, जो यूं तो कम्प्यूटर का प्रयोग खूब करते हैं लेकिन परीक्षा ऑनलाइन देने के नाम पर असहज हो जाते हैं। यदि आप भी उन लोगों में से हैं, जो ऑनलाइन बैंकिंग एग्जाम को लेकर चिंतित हैं, तो हम आपके लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं, जिनसे आपको निश्चित ही लाभ होगा। ऑनलाइन परीक्षा की तकनीक पर चर्चा करने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर क्यों बैंकिंग परीक्षाओं को ऑनलाइन करने का फैसला किया

ऑनलाइन एग्जाम से डरें नहीं, अपनाएं ये टिप्स

ऑनलाइन का है भविष्य

जो भी हो, ऑनलाइन परीक्षाओं के लाभ इसकी हानियों से ज्यादा हैं और भविष्य तो कम्प्यूटराइज्ड परीक्षाओं का ही है।आगे चलकर तमाम परीक्षाएं इसी फॉर्मेट में होने वाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी तक पेपर-पेन वाली परीक्षाएं देते आए परीक्षार्थियों को शुरू – शुरू में ऑनलाइन परीक्षा थोड़ी असहज लग सकती है लेकिन यह कोई हिमालय लांघने जैसा काम भी नहीं है।वैसे भी, सभी बैंकिंग प्रोफेशनल्स से यह अपेक्षा तो की ही जाती है कि उन्हें कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान हो।तो फिर परीक्षा भी कम्प्यूटर पर ही देने में हिचक कैसी?

परीक्षा के माहौल से परिचित हों

कम्प्यूटराइज्ड बैंक परीक्षाओं की आलोचना का एक आधार यह रहा है कि परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर देने में सहज नहीं हो पाते और समय पर पेपर पूरा नहीं कर पाते । इस समस्या का समाधान खुद परीक्षार्थी के पास ही है।जो युवा बैंकिंग एग्जाम देने का इरादा रखते हैं, वे परीक्षा के इस नए माहौल से खुद को अभ्यस्त करना शुरू कर दें। इससे आप एग्जाम फॉर्मेट, स्टाइल और प्रश्नों की शैली से परिचित

टेक्नोलॉजी का लाभ उटाएं

टेक्नोलॉजी हमेशा से भविष्य का रास्ता बताती आई है।ऑनलाइन बैंक पीओ एग्जाम भी इससे अलग नहीं है।टेक्नोलॉजी से समय और मेहनत की बचत होती है, यह तो सब जानते हैं। सो आप भी इस बात पर फोकस करें कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं और कैसे कम समय व कम मेहनत के साथ पेपर हल कर सकते हैं।

अपनी ताकत और कमजोरी पहचानें

एक बार आप ऑनलाइन परीक्षा की टेक्नोलॉजी और फॉर्मेट से परिचित हो जाएं, तो आप अपनी ताकत और कमजोरी को पहचान सकते हैं। फिर आप अपनी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मसलन, हो सकता है कि आप कम्प्यूटर पर मैथ्स के प्रश्न तो आसानी से हल कर लें लेकिन स्क्रीन पर इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न पढ़ने और उनके उत्तर देने में आपको दिक्कत हो रही हो । ऐसे में आप मैथ्स के मुकाबले इंग्लिश की तैयारी पर अधिक ध्यान दे सकते हैं ।

ऑनलाइन मॉक टेस्ट

कम्प्यूटराइज्ड आरबीआई बैंक एग्जाम्स के आने के बाद से कई कोचिंग सेंटर्स तथा टेस्ट प्रेप वेबसाइट्स ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराती हैं।ये मॉक टेस्ट बैंकिंग एग्जाम के सिलेबस, फॉर्मेट तथा प्रश्नों की शैली को अच्छी तरह समझने के बाद तैयार की जाती हैं। इसलिए इन्हें हल करने पर आप वास्तविक परीक्षा के अनुभव से अवगत हो सकते हैं। इससे नियत समय में पूरा पेपर हल करने में भी आपको मदद मिलेगी।

शॉर्टकट और ट्रिक्स

बैंकिंग एग्जाम में बैठने वाले परीक्षार्थी मैथ्स और क्वॉन्टिटेटिव एबिलिटी के प्रश्न हल करने के लिए कई तरह के शॉर्टकट तथा ट्रिक्स का इस्तेमाल करते आए हैं।ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड टेस्ट में भी आप ऐसा कर सकते हैं। संच तो यह है कि ऑनलाइन टेस्ट दे चुके कई परीक्षार्थियों का कहना है कि उन्हें इस फॉर्मेट में पहले से कहीं ज्यादा शॉर्टकट और ट्रिक्स हाथ लगी हैं! आप भी इन शॉर्टकट्स और ट्रिक्स को जानें और इन्हें आजमाएं।

Wednesday, 28 August 2024

पानी पाताल और हम आसमान में

आज पानी पाताल में जा रहा है और हम आसमान में। दुनिया पानी-पानी चिल्ला रही है और हम पानी की बबार्दी कर रहे हैं। नतीजा सामने है। अब तो गले ही नहीं सुखे, धरती तक प्यासी है। वह चाहे बुंदेलखंड का कोई क्षेत्र हो या महाराष्ट्र का दुर्गम इलाका, बंजर खेत हकीकत बयां कर रहे हैं। एक समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के अधिकतर किसानों के खेत में कुआं होता था। किसान कुओं से सिंचाई करते थे। कुओं में पारंपरिक सिंचाई की विधि रेहट होती थी। इस रेहट को बैल खींचते थे। रेहट से निलकता पानी नालियों के माध्यम से खेतों को सींच देता था। आज अब न तो उस तरह के जीवट किसान रहे और न ही पुराने संसाधन। करीब चार दशक पहले रेहट में काफी बदलाव किए गए। लकड़ी की जगह लोहे के रेहट बाजार में आ गए। यहीं गच्चा खा गए लोग। सिंचाई के नवीन विज्ञान के ज्ञान ने श्रम की जलशक्ति को यंत्र की शक्ति ने मात दे दी है। पहले के रेहट में एक भी लोहे की कील नहीं लगती थी। मिट्टी के घड़े तथा जामुन की लकड़ी, छिवल (छियुल) की रस्सी का प्रयोग होता था। इसमें एक पैसे का खर्च नहीं था। सब प्राकृतिक था। अफसोस नवीन ज्ञान ने कुआं, तालाब, गांव के सामृहिक परंपरा जल स्रोत खत्म कर दिए। बाकी जो बचे हैं, वो भी खत्म होने वाले हैं। अगर हम अभी नहीं चेते तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जल चर्चा, विचार गोष्ठी, पानी की पाठशाला. तालाब पजन जैसे तमाम उपक्रमों के बावजद सखा जैसी विभीषिका का सामना करना चिंतानजक है। दरअसल जलक्रांति बिना जनांदोलन के असंभव है। आम आदमी चिंतित तो है, पर वह भी क्या करे। शाम की दाल-रोटी का इंतजाम करने में ही सारा दिन खप जाता है। अगली सुबह यही सब फिर उसकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर लड़े जाने की भविष्यवाणी तक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जल संकट से संभावित जिलों में जलकोष यात्रा शुरू कर नेक काम किया है। यह सबसे बड़ा अकाट्य सत्य है कि सब कुछ बनाया जा सकता है, पर पानी बनाया नहीं जा सकता। उसे केवल बचाया जा सकता है। और हम वहीं नहीं कर पा रहे। जल के बिना सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना टूटता नजर आता है। जल का बाजारीकरण जल समस्या का समाधान नहीं है। अन्नदाता किसान ने यदि पानी के अभाव में खेती करना छोड़ दिया तो क्या होगा, यह सोचकर आत्मा रोने लगती है। आत्मनिर्भरता स्वावलंबी बने, इस दिशा में जमीनी प्रयास होने चाहिए। सामुदायिक प्रयास भी जरूरी हैं। जिस तरह हम साल भर के लिए अपने घर का बजट बनाते हैं, उसी प्रकार पानी का बजट भी बनाएं तो जल संकट से काफी हद तक बचा जा सकता है। जल में सिद्धि होती है। जल में समृद्धि है। जल में अमृत है। जल में ऊर्जा है। निदयों को तप से पृथ्वी पर लाया गया। जलाशय हमारे लिए सदैव पूजनीय हैं। इसलिए जल संरक्षण रचनात्मक और सामाजिक दायित्व है। ये कार्य अकेले नहीं होते। इसमें पूरे समुदाय और समाज का वर्षों का श्रम अनुभव समाहित होता है। सब कहते हैं- जल जीवन का आधार है। जल ही जीवन है। जल अनमोल है। जल विलक्षण है। जल सर्वव्यापी है। जल असाधारण है। जल राष्ट्रीय संपदा है। जल परमेश्वर है। जल शिव है। जल शंकर है। जल अमृत है। जल शक्ति है। जल ऊर्जा है। धर्म के आधार पर केवल पानी ही पवित्र करता है। भारतीय संस्कृति पूजा प्रधान है। पूजा पवित्रता के लिए जल आवश्यक है। जल में आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। दुनिया की सभी पुरानी सभ्यताओं का जन्म जल के समीप अर्थात निदयों के किनारे हुआ है। दुनिया के जितने पराने नगर हैं, वे सब निदयों के किनारे बसे हैं। जल पाने के मुख्यतः चार स्रोत हैं- निदयां, झीलें, तालाब, कुआं। हर मर्ज की दवा पानी है। दुनिया के सामने जल संकट है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए। क्या रणनीति बने। सबको सोचना होगा। मनुष्य को प्रतिदिन तीन लीटर पानी पीने के लिए चाहिए। जीव, जीवन और जल तीनों का आपस में अंतरंग गहरा संबंध है। जल चक्र को बनाए रखने के लिए कोहरे (ओला, बर्फ और पाला) की भूमिका महत्वपर्ण है। पानी में यदि भाप बनने का गण न होता तो दुनिया को पानी ही ना मिलता। पानी को छोडकर दुनिया की सभी चीजें सर्दी में सिकड़ती हैं, लेकिन सर्दी में पानी फैलता है। दुनिया की हर चीज का तापमान पानी के तापमान के मानक से नापा जाता है। दनिया की अर्थव्यवस्था में जल का बहुत बड़ा योगदान है। पानी सदैव नीचे की ओर बहता है। वह अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। हमारे वेदों और धर्म शास्त्रों में जल संरक्षण के बारे में पहले ही सचेत किया जा चुका है। पृथ्वी में जितने भी जीव हैं उनका जीवन जल पर निर्भर है। पेड़ में, फलों में, अनाजों में, पत्तों में और जड़ों में जो स्वाद और रस है, वह सब जल के कारण है। यानी पानी के बिना सब सुन है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है-क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पांच तत्व मिल रचा शरीरा।। कबीर ने कहा है- पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात।। रहीम कह गए हैं- रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सन।। वेदों में कहा गया है कि जल देवता की भक्ति और सेवा से सभी मनोरथ पर्ण होते हैं। प्राचीन काल से हम स्तुति प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। जल को स्वच्छ बनाए रखना भी जल देवता की पूजा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक पानी का हमारे जीवन में सबसे बड़ा स्थान है।

यूसीसी और जाति व्यवस्था पर भ्रामक आख्यानों का जवाब



🗷 पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

अब समय आ गया है कि भारत बनाने वाली ताकतें इन झूटे आख्यानों का मुकाबला करें और सभी के लाभ के लिए हिंदुओं को एकजुट करें। आइए, हम दो झूटे आख्यानों की जांच करें, जो एससी और एसटी जातियों के दिमाग में जहर भर रहे हैं- 1. समान नागरिक संहिता आरक्षण को खत्म कर देगी। 2. उच्च जाति के हिंदुओं ने जाति और जाति भेदभाव की व्यवस्था तैयार की। समान नागरिक संहिता की अवधारणा सभी धर्मों और सामाजिक समूहों के लिए एक समान नागरिक संहिता (विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, तलाक, इत्यादि) की स्थापना को संदर्भित करती है। भारत में अब कई पारिवारिक कानून हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने से कानूनों में सामंजस्य आएगा, जिसके परिणामस्वरूप दक्षता और पारदर्शिता आएगी। एक मानक नागरिक संहिता होने के कई फायदे हैं।

लिए काम करती हैं, ताकि वे अपने लाभ के लिए राजनीतिक और नौकरशाही सत्ता का इस्तेमाल कर सकें। राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से नष्ट कर सकें और प्रत्येक भारतीय में दासता पैदा कर सकें। वे जिस नियमित रणनीति का उपयोग करते हैं, वह है हिंदुओं को जाति के आधार पर विभाजित करना। वे एससी, एसटी और ओबीसी लोगों के दिमाग में जहर भरने के लिए झुठे विमर्श विकसित करते हैं, जिससे वे हिंदुओं और हिंदुत्व से नफरत करने लगते हैं। वे आंशिक रूप से सफल रहे, फिर भी उन्होंने देश के ताने-बाने को काफी हद तक नुकसान पहुचा दिया। अब समय आ गया है कि भारत बनाने वाली ताकतें इन झूठे आख्यानों का मुकाबला करें और सभी के लाभ के लिए हिंदुओं को एकजुट करें। आइए, हम दो झुठे आख्यानों की जांच करें. जो एससी और एसटी जातियों के दिमाग में जहर भर रहे हैं- 1. समान नागरिक संहिता आरक्षण को खत्म कर देगी। 2. उच्च जाति के हिंदुओं ने जाति और जाति भेदभाव की व्यवस्था तैयार की। समान नागरिक संहिता की अवधारणा सभी धर्मों और सामाजिक समुहों के लिए एक समान नागरिक संहिता (विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, तलाक, इत्यादि) की स्थापना को संदर्भित करती है। भारत में अब कई पारिवारिक कानून हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने से कानुनों में सामंजस्य आएगा, जिसके परिणामस्वरूप दक्षता और पारदर्शिता आएगी। एक मानक नागरिक संहिता होने के कई फायदे

मुस्लिम सदस्यों ने प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन प्रस्तावित सकारात्मक कार्यवाही है। आरक्षण किएक्षअर्थात बशर्ते कि कोई भी का समान नागरिक संहिता से कोई समूह,वर्ग, समुदाय या लोग अपने संबंध नहीं है। समान नागरिक व्यक्तिगत कानून को छोड़ने के संहिता धर्म के बारे में है, जबकि लिए बाध्य नहीं होंगे, यदि उनके आरक्षण सामाजिक समानता के पास ऐसा कोई कानून है और बारे में है। जरा विचार करें. बशर्ते कि किसी भी समदाय का इस्लामी धर्म में वे चार पत्नियां नहीं व्यक्तिगत कानून जिसकी गारंटी रख पाएंगे। वे मुस्लिम महिलाओं कानून द्वारा दी गई है, समुदाय की के साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगे। पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बदला जाएगा। इन संशोधनों पर चर्चा परे इस्लामी कानून अब विवाह जैसे व्यक्तिगत मामलों में लागू नहीं दिन चली। डॉ. अंबेडकर ने अपने होगा। एक मुस्लिम लड़की पंद्रह जवाब में कहा- मुझे डर है कि मैं वर्ष की आयु में विवाह नहीं कर इस अनुच्छेद में पेश किए गए पाएगी। वे तीन तलाक और संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता मेरे मित्र, श्री हुसैन इमाम ने निकाह हलाला को लाद नहीं पाएंगे। मुस्लिम महिलाओं को भी संशोधनों का समर्थन करते हुए गोद लेने का अधिकार होगा। उन्हें पूछा कि क्या इतने विशाल देश के संपत्ति पर समान अधिकार होगा। लिए एक समान कानून संहिता मुल्ला न्यायाधीश के रूप में अपनी होना संभव और वांछनीय है। अब शक्ति खो देंगे। सभी मामलों का मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं उस कथन से बहुत फैसला अदालत में होगा। ये सभी सकारात्मक बातें हैं। हालांकि कुछ आश्चर्यचिकत था। इसका सीधा-मुसलमान इन नियमों को इस्लाम सा कारण यह है कि हमारे देश में विरोधी मान सकते हैं और इनका मानवीय संबंधों के लगभग हर विरोध कर सकते हैं। वे पहलू को कवर करने वाली एक प्रागैतिहासिक काल में रहना चाहते समान कानून संहिता है। हमारे हैं। कछ लोगों की आलोचना के पास पूरे देश में एक समान और बावजूद यूसीसी का मुस्लिम पूर्ण आपराधिक संहिता है, जो दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया समाज पर सकारात्मक प्रभाव संहिता में निहित है। हमारे पास पड़ेगा। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता-राज्य नागरिकों के संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है, लिए पूरे भारत में समान नागरिक जो संपत्ति संबंधों से संबंधित है संहिता सनिश्चित करने का प्रयास और जो पूरे देश में लागू है और मैं करेगा। यह अनच्छेद 44 में कहा ऐसे असंख्य अधिनियमों का गया है, जो राज्य नीति के निर्देशक हवाला दे सकता हूं, जो साबित सिद्धांतों के तहत हमारे संविधान करेंगे कि इस देश में व्यावहारिक के भाग 4 में निहित 16 अनुच्छेदों रूप से एक नागरिक संहिता है, जो (अनुच्छेद 36 से 51 तक) में से अपनी सामग्री में एक समान है एक है। अनुच्छेद 44 को 23 और पूरे देश में लागू है। यह नवंबर 1948 को संविधान सभा में तथ्यात्मक सामग्री स्पष्ट रूप से डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा दशार्ती है कि डॉ. बाबासाहेब अनुच्छेद 35 के प्रारूप के रूप में अंबेडकर सभी के लिए नागरिक पेश किया गया था और उसी दिन आचरण में एकरूपता सुनिश्चित सर्वसम्मति से पारित किया गया करने के लिए एक समान नागरिक

समर्पित थे। उनका नागरिक संहिता को आरक्षण से जोड़ने का कोई इरादा नहीं था। हालांकिज्ञउन्हें लगातार सत्ता में बैठे लोगों और संसद के कई सदस्यों द्वारा चुनौती दी गई और दबाया गया, जिन्होंने या तो संविधान का सम्मान करने से इनकार कर दिया या हिंदुओं को विभाजित करने के अवसर तलाशे। कोई राय बनाने से पहले. एससी और एसटी समुदायों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने यूसीसी के बारे में क्या कहा था। वर्तमान जाति व्यवस्था, जिसमें जाति को जन्म से परिभाषित किया जाता है, वैदिक साहित्य में वर्णित नहीं है। वैदिक सामाजिक श्रम विभाजन को मूल रूप से वर्णाश्रम के रूप में जाना जाता था। भगवद-गीता (4.13) में कहा गया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था जन्म के बजाय गुण और कर्म या आधुनिक बोलचाल की भाषा में कहें तो दृष्टिकोण और योग्यता पर आधारित है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, गौतम ऋषि ने दासी के पत्र सत्यकाम जाबालि को ब्राह्मण घोषित किया क्योंकि वह अडिग सत्यवादी था, जो एक सच्चे ब्राह्मण की पहचान है। सूत गोस्वामी, कनक, कांचीपुरम, तुकाराम, तिरुवल्लूवर, सुरदास और हरिदास ठाकुर सभी को हाशिए के परिवार में जन्म लेने के बावजद संतों के रूप में सम्मानित किया गया। हर कोई शुद्र के रूप में जन्म लेता है, जिसका अर्थ है कि वे अयोग्य हैं। आध्यात्मिक दीक्षा व्यक्ति को नवजात में बदल देती है, जिसका अर्थ है कि वह अपना आध्यात्मिक अस्तित्व शुरू करता है। वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करकेक्षव्यक्ति विद्वान बन सकता है। केवल पूर्ण सत्य को समझकर ही व्यक्ति ब्राह्मण बन अपनी पुस्तक, द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ हिंदू में संदर्भों के साथ लिखा है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा थोपी गई जाति व्यवस्था के अलावा कोई जाति व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपको यह समझने के लिए ब्रिटिश अभिलेखों को पढ़ने की आवश्यकता है कि उन्होंने इस प्रक्रिया को क्यों और कैसे अपनाया, जिसकी शरूआत 1871 की पहली औपनिवेशिक जनगणना से हुई। [रिसले 1891]। अधिकतर भारतीय अभी भी सोचते हैं कि यह शब्द प्राचीन भारतीय जनजातियों/समदायों को संदर्भित करता है और समुदाय के स्थान पर जाति शब्द का उपयोग करते हैं। जाति पूर्तगाली भाषा में नस्ल के लिए है, जो एकल-नस्ल भारत में एक अर्थहीन अवधारणा है। अंग्रेजों ने वेद में जाति के लिए झुठी शास्त्रीय स्वीकृति भी पाई। यहां श्लोक दिया गया है और बताया गया है कि अंग्रेजों ने इसकी गलत व्याख्या कैसे की। साथ ही हिंदू परंपराओं में इसका वास्तव में क्या अर्थ है। पदानुक्रम के शीर्ष पर ब्राह्मण थे जो मख्य रूप से शिक्षक और बुद्धिजीवी थे और माना जाता है कि वे ब्रह्मा के सिर से आए थे। फिर क्षत्रिय या योद्धा और शासक आए. जो कथित तौर पर उनकी भजाओं से बने थे। तीसरा स्थान वैश्यों या व्यापारियों को मिला, जो उनकी जांघों से बने थे। ढेर के सबसे निचले हिस्से में शद्र थे. जो ब्रह्मा के पैरों से आए थे और सभी नीच काम करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के समय से ही हिंदु समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जमीनी स्तर पर किए

किशोर साहू के 'कुंआरा बाप' बनने की कहानी

पचास के दशक के निर्देशक, अभिनेता और लेखक थे। बॉम्बे टॉकीज की 'जीवन प्रभात' (1937) फिल्म से नायक के रूप में उनका करियर शुरू हुआ था। अपनी दूसरी फिल्म 'बहूरानी' से वे निर्माता, निर्देशक, पटकथा एवं संवाद लेखन भी बन गए थे। 2 जून 1940 को रिलीज हुई यह एक सफल फिल्म थी। निर्देशन में उनके सहयोगी के रूप में दो नाम जन्नरकर एवं मुबारक के भी दिए गए थे, जबकि निर्देशन स्वयं उन्होंने ही किया था। उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्देशित पहली फिल्म थी 'कुंआरा बाप'। हालांकि पहले वे इसके सहनिर्देशक थे, लेकिन नियति ने ऐसे रंग बदले कि वह इसके निर्देशक, पटकथा लेखक भी बन गए। हुआ यह कि बॉम्बे टॉकीज की 'पुनर्मिलन' फिल्म जिसमें वे नायक थे, की सफलता के बाद प्रसिद्ध फिल्म निर्माता कीकभाई देसाई उनसे मिलने आए। उनके पास एक सामाजिक फिल्म

'कंआरा बाप' की कहानी थी और वह चाहते थे कि साह उसमें नायक का रोल करें। किशोर साह ने यह रोल दो शर्तों पर स्वीकार किया कि फिल्म की पटकथा वह लिखेंगे और निर्देशन भी वही करेंगे। कीकृभाई देसाई पहले ही जेपी अडवानी को उसका निर्देशक नियुक्त कर चुके थे। इसलिए बात उनके सहनिर्देशक बनने पर तय हुई। पटकथा लिखने की शर्त पर उन्हें कोई ऐतराज न था। किशोर साहू की सलाह से अन्य पात्र चने जाने लगे। फिल्म की नायिका के लिए प्रतिमा दासगुप्ता को चुना गया, जो वाडिया मुवीटोन की फिल्म 'कोर्ट डांसर' में नायिका साधना बोस की सहेली का रोल करके लोगों की पसंद बनी हुई थीं। प्रतिमा दासगुप्ता बंगालिन थी, सांवली थीं, आकर्षक थीं और उनकी शरीर-रचना और स्वभाव में कुछ मर्दानगी और तेजी थी। उनके पास उस समय बेबी ऑस्टिन की रेसिंग कार थी, जो वह खुद चलाती थीं। इस गाड़ी की आवाज रेसर कार जैसी हुआ करती थी। शादीशुदा प्रतिमा की अपने पति मंजूर उल हक से बनती न थी। प्रतिमा की कई लोगों से मित्रता को मंजर शक और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते और कई बार रूठकर बीकानेर, दिल्ली चले जाते तो महीनों नहीं आते। प्रतिमा उनसे तलाक चाहती थीं। प्रतिमा किशोर साह को अपने जीवन की हर एक बात बता देती थीं। समझ-बझ की नींव पर रखी दोनों की मित्रता घनिष्ठ टिकी रही। प्रतिमा से उनकी निकटता उन दिनों फिल्म जगत में चर्चा का विषय बन गई। पत्र-पत्रिकाओं में तरह-तरह के लेख छपने लगे। फिल्मी दुनिया में ऐसे 'गुप्त प्रणय' की प्रसिद्धि से नायक-नायिका को विशेष ख्याति मिलती है और उनका मल्य अधिक बढ जाता है। प्रतिमा और किशोर साह के साथ भी यही हो रहा था। दोनों ने इन टीका-टिप्पणियों का खंडन कभी नहीं किया। इस फिल्म में ई.बिली मोरिया को खलनायक के रूप में लिया गया था। लेकिन, पहले दिन की शूटिंग से ही दोनों निर्देशकों में वाद-विवाद शुरू हो गया। दोनों में रोज लडाई होती और दिन में कम फिल्म के निर्माता कीकुभाई के पास जाते, क्योंकि अडवानी सीनियर थे और चालीस फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे। इसलिए अमुमन वे उनका ही पक्ष लेते और कभी-कभी उनका भी। ऐसे हालात में टीम में फूट पड़ गई। कुछ सीनियर लोग अडवानी की तरफ थे, तो प्रतिमा एवं नई पीढ़ी के कलाकार किशोर साहु की तरफ। लेकिन, शृटिंग के नौवें दिन ही कीकृभाई देसाई अपेंडिक्स के कारण अचानक बीमार हुए और उनका देहांत हो गया। 'कुंआरा बाप' की शूटिंग रोक दी गई। इस बीच एनआर आचार्य जो बॉम्बे टॉकीज में निर्माण प्रबंधक हुआ करते थे और बाद में निर्देशक भी हुए, ने अपनी फिल्म निर्माण संस्था आचार्य आर्ट प्रोडक्शंस बनाई और किशोर साहू को भी उसमें शामिल होने के लिए बुलाया। दो फिल्में बनाने की बात हुई। तब किशोर साह ने श्रीमती कीकुभाई से 'कुंआरा बाप' के अधिकार खरीद लिये और आचार्य की कंपनी के साथ इस फिल्म का निर्माण शुरू

थे। उन्होंने इस फिल्म के संवाद लिखने के लिए प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर को अनुबंधित किया। वे उन दिनों बंबई में ही फिल्मों में काम करने के विचार से आए हुए थे और शिवाजी पार्क में साह के फ्लैट के नीचे ही शेरा विला में फ्लैट लेकर ले रहे थे और अपने परिवार को लखनऊ से बंबई बुला लिया था। शूटिंग के पहले दिन के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अपने दिग्दर्शन का पहला दिन, कभी न भूल्रंगा। मैं सुबह से ही उत्तेजित था। स्टूडियो में पूजा समाप्त हुई थी और लाइटिंग (प्रकाश व्यवस्था) हो रही थी। मुहुर्त में पधारे हुए अतिथियों की खासी भीड़ थी। सबकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं, क्योंकि मैं दिग्दर्शक था और वह मेरा प्रथम दिग्दर्शन था। मुझसे अपेक्षा की जा रही थी कि मैं साउंड (ध्विन) चालू करवाऊं। शॉट प्रतिमा दासगुप्ता पर लिया जाने वाला था। मैंने आज्ञा दीः 'साउंड स्टार्ट।' लाउडस्पीकर में साउंड रेकार्डिस्ट की आवाज गुंज

!' और कैमरा चलने लगा।' एक्शन !' मैंने कहा और शूटिंग शुरू हो गई। जब मैंने थोड़ी देर बाद 'कट' कहा, तो उपस्थित जनों की तालियों से स्ट्रियो गुंज उठा। शॉट ओके था। मैं दिग्दर्शक बन चुका था। सबसे पहले बधाई प्रतिमा ने दी। इस मेहनत का पारितोषिक मिलने में विलंब न हुआ। 'कुंआरा बाप' मेरा पहला दिग्दर्शित चित्र बॉक्स ऑफिस पर अति सफल रहा। यह लगभग हिंदी में पहला हास्य चित्र था, जिसने इतनी सफलता प्राप्त की थी। मैं दिग्दर्शक ही नहीं, सफल दिग्दर्शक बन गया। फिल्म का यह मुहूर्त शॉट प्रतिमा पर फिल्माया गया था और उन्होंने इस पर ऐसी शरारत की कि किशोर साह् हक्के-बक्के रह गए। उस दिन प्रतिमा ने नीली रेशमी साड़ी पहनी थी। जैसे ही किशोर साहू ने 'कैमरा' कहा कि अचानक प्रतिमा ने उनकी तरफ देख कर आंख मार दी। किशोर साह् ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पता नहीं, मैं चक्कर खाकर गिर क्यों न पड़ा।

Social Media Corner

सच के हक में.

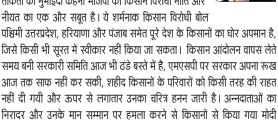
राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई। विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। रूस-यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा पर मेरी अंतर्दृष्टि पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।



किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल



सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर लें

इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। (राहुल गांधी का 'एक्स' पर पोस्ट)

आंसू बहाते 'विशाखा' दिशा-निर्देश

श के सर्वोच्च न्यायालय की चिंता और लगभग पूरे देश के रोष के बाद भी राजनीति पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों का कवच बनी हुई है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की यौन हिंसा के बाद हुई हत्या ने एक बार फिर साबित किया है कि समुचे देश में कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर परिस्थितियां कितनी असुरक्षित हैं। वह भी इतनी भयावह कि कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ यह सब वीभत्स घट जाता है। निश्चित रूप से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मानव अधिकारों का सरासर उल्लंघन ही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षा अनुकूल वातावरण बनाने के मद्देनजर विशाखा दिशा-निर्देश जारी करने के 27 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को डॉक्टरों की सुरक्षा को संस्थागत बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने

के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर महिला सुरक्षा को लेकर मौजूदा देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश के अनुपालन के लिए गठित एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स को चिकित्सा पेशवरों की सुरक्षा, महिला चिकित्सकों के लिए अनुकूल कामकाजी परिस्थितियां बनाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए प्रभावी सिफारिशें तैयार करने का काम सौंपा गया है। विश्वास किया जाना चाहिए कि ये सिफारिशें यदि जमीनी स्तर पर भी प्रभावी साबित हुईं तो किसी भी पेशे में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए असरकारी साबित होंगी। लेकिन, यह तभी संभव है,ज्ञजब सभी हितधारक एक स्तर पर एकजुट होकर इस दिशा में काम करेंगे। निस्संदेहक्षिकसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के वक्त तमाम तरह के उपक्रम होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और यही वजह है कि नई कार्ययोजना बनाते समय इस बात का आकलन करने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है कि

कानून और दिशा-निर्देश जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में कितने सफल रहे हैं। सही मायनों में कानून बनाने और दिशा-निर्देश जारी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका अनुपालन कितने पारदर्शी व संवेदनशील दृष्टि से किया जाता है। साथ ही विगत के अनुभवों से भी सबक लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि वर्ष 2012 के निर्भया कांड के बाद देश में कोलकाता कांड में भी उसी तरह की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई है। इसके बाद आवश्यकता महसुस की गई कि ऐसे क्रूर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने वाले कानून लाए जाएं। कालांतर में देश में यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम अस्तित्व में आया। दरअसल महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ही विशाखा दिशा-निदेशों के विस्तार के रूप में इसे अधिनियमित किया

गया। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले साल देश की शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया था। साथ ही इससे जुड़ी अनिश्चितताओं की ओर भी संकेत दिया था। इसके उदाहरण के रूप में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निर्भया फंड अक्सर नकारात्मक कारणों से सुर्खियों में रहा है। इसमें आवंटित धन का पर्याप्त रूप में उपयोग न करना या फिर इस आवंटित धन का दुरुपयोग होना शामिल है। करीब एक दशक में देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए महिला सुरक्षा से जुड़ीं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिएक्षआवंटित धनराशि का लगभग 76 प्रतिशत धन ही खर्च हो पाया है। निश्चित रूप से महिला सुरक्षा की ऐसी चुनौतियों के बीच कम धन का खर्च होना एक विडंबना ही कही

मकीपॉक्स का खतरा

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकीपॉक्स बीमारी को लेकर विश्व स्तर पर स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। दो साल में दसरी बार यह स्थिति पैदा हुई है और खासतौर पर अफ्रीका में मंकीपॉक्स की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। चिंता की बात है कि वैज्ञानिकों ने विषमलैंगिक अंतरंग या यौन संपर्क से जुडे. संचरण समूहों का दस्तावेजीकरण किया है, जबिक 2022 के बहुद्देशीय प्रकोप के दौरान ऐसा नहीं था। जेएएमए जर्नल के एक शोध पत्र के अनुसार, इन संक्रमणों के पीछे मंकीपॉक्स वायरस के क्लैड 1बी संस्करण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा, ऐसे चार देश हैं, जहां संक्रमण ज्यादा है। खास बात है कि पिछली बार इन देशों में मंकीपॉक्स के मामले सामने नहीं आए थे। इस बार स्वीडन में भी संक्रमण का एक मामला दर्ज किया गया है, जिससे यूरोप में चिंता की लहर है। क्लैड1बी वायरस वास्तव में क्लैड1 वायरस की नई शाखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यह पहली बार 2023 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। कहा जाता है कि लोगों के बीच यह यौन संपर्क से फैल रहा है। हालांकि इसके फैलने के दूसरे माध्यम भी हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि वायरस का नया संस्करण गंभीर बीमारी और उच्च मृत्यु दर की वजह बन सकता है। वैज्ञानिक जोखिम का अध्ययन कर रहे हैं। शुरूआती अध्ययन से पता चलता है कि वायरस के नए संस्करण से वयस्कों में पांच प्रतिशत और बच्चों में 10 प्रतिशत तक जोखिम है। मतलब बच्चों को विशेष रूप से संभालने की जरूरत है। वास्तव में यह मानव की बिगड़ती जीवन शैली के साथ ही बिगड़ते आचरण का भी मामला है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो अपने आचरण को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। उनके लिए भोग-उपभोग ही सब कुछ है। इसके लिए वे किसी भी संयम या सीमा को नहीं मानते हैं।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail: thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Layered & complex world of translation

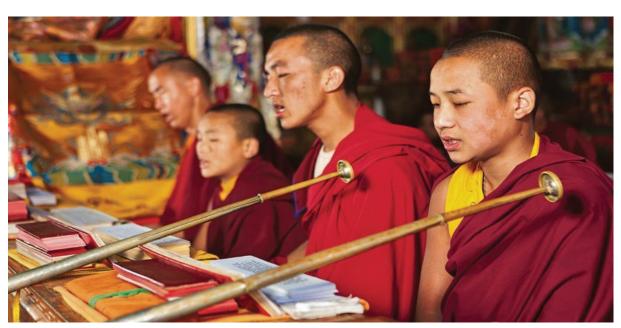
Earlier this month, I found myself in Colombo, Sri Lanka, a place where languages seem to hang in the air like humidity, pressing down on the city in a palpable, almost tactile, way. I had come as a Punjabi translator for the inaugural SALT (South Asian Literature in Translation, a multi-year project at the University of Chicago) Summer School, an opportunity that promised to be remarkable.As I stepped into my role as a translator of Punjabi into English, surrounded by other translators — each of us tethered to our own languages like lifelines — I couldn't help but feel that the air there was thick with the echoes of Sinhala, Tamil, Bengali, Urdu and Hindi, a cacophony of tongues that felt at once foreign and familiar. Even English seemed out of place here, as though it, too, was trying to assert itself in a landscape that resisted any kind of easy categorisation.

I felt this resistance in me as I moved through my days there, listening, observing, translating, and yet never quite arriving at a full understanding of where I was, or who I was within it. In Punjabi, the language of my home and my translation, I've often felt a sense of alienation. This feeling likely stems from the underlying tension I've always been exposed to - that Punjabi is the other language, not just another language. So, returning to Punjabi after I've established alternate careers in alternate languages isn't merely wishful thinking.In one of my favourite podcasts, Indy and Dr, the host, Indy, speaks with a representative from Naujawani, an online media platform. Indy poses a question: "If Punjabi is the seventh largest language in the world and still growing, why is there such a fixation among my generation, or the generation above us, on the idea that Punjabi is dying?" Naujawani responds reasonably, "I'd guess there are a number of reasons. Probably, the most prominent is that we are a very negative community because of all we've faced over the last 50 to 75 years, including numerous defeats. All these negative experiences lead us down a road where we start to believe we're constantly under attack, that we're besieged, and so we resort to tropes like the Punjabi language is dying."However, many millennials and Gen Z individuals aren't anywhere close to believing that the Punjabi language is dying. We have our ways of staying connected to it — through music, literature, films, and translation. In a translation workshop, translation felt less like a mechanical process and more like meditation. We found ourselves deeply immersed in our texts, feeling the weight of each word, the flow of each line, and the silences between them. I realised that my role was not just to translate the words, but to convey the essence of them — to allow the audience to feel what the writer felt, even if the words themselves were different. This was not a task I could accomplish alone; it required me to draw upon my own experiences, my own understanding of both languages, and the shared history of our cultures — all this accompanied by the companionship of other translators. While I was a part of the multilingual prose workshop, working on translating some Punjabi short stories into English, there were separate strands of workshops for Bangla, Hindi/Urdu, Tamil and multilingual poetry. In the workshops that solely focused on translating from a single language, the authors whose works were being translated were present in the seminar room. We heard many anecdotes, but the most fascinating reflections came from the Hindi/Urdu translators, who were translating a two-page short story by Asghar Wajahat, which we had the opportunity to hear him read at the inaugural event. Our co-translators from the Hindi workshop told us that since their group was working on translating the same story, sometimes their days were so rigorous that by the end of it.

China's quest to replace 'Tibet' with 'Xizang' is destined to fail

China's gradual military conquest of eastern territories

THE term 'South Tibet' frequently pops up in Indian media, uncritically disseminating misinformation from Chinese news outlets. A recent report claimed that China has renamed 30 more places in Arunachal Pradesh, which Beijing asserts are part of 'South Tibet'. In common parlance, Tibetans may refer to the eastern, western, central or northeastern regions of Tibet, but there is no term 'South Tibet' as a geographic proper noun in the Tibetan lexicon – a fact easily verified by consulting any Tibetan dictionary or encyclopaedia. This term is an entirely new Chinese construct.Beijing truly deserves recognition for its exceptional mastery in the politics of names. Their prowess in manipulating names — whether of people, places or concepts — as strategic political tools to assert power, control narratives, shape identities and influence public perception is a masterclass in propaganda. A classic example of China's dominance in shaping the narrative on the Sino-Tibetan conflict is evident from their definition of 'Tibet' itself. The 'Tibet' referred to by China is geographically distinct from the Tibet that exists in the hearts and minds of the Tibetan people. The People's Republic of China, established in 1949, considers only the 'Tibet Autonomous Region' (TAR), created in 1965, as Tibet — an ancient nation with a rich history spanning thousands of years! Traditionally, Tibet consisted of three regions: U-tsang, Kham and Amdo. When Tibetans speak of 'Tibet', they mean all three regions, encompassing approximately 2.5 million square km.In line with the classic colonial divide-andrule policy, the so-called TAR includes only U-tsang and parts of Kham, with the remaining areas fragmented as autonomous prefectures and counties, and incorporated into the neighbouring Chinese provinces of Qinghai, Sichuan, Yunnan and Gansu. Qinghai, for example, is composed entirely of the traditional Amdo and parts of Kham. The composition of the current democratically elected leadership of the exile Tibetan polity highlights the stark incongruity of China's definition of Tibet. For example, both the current and former Sikyong (President) of the Central Tibetan Administration belong to areas outside the so-called TAR. The current Sikyong, Penpa Tsering, belongs to Amdo Chentsa, now part of Qinghai province, while former Sikyong Lobsang Sangay belongs to Kham Lithang, which is currently within Sichuan province. In previous Sino-Tibetan talks, a key demand from the Tibetan side was the establishment of a single autonomous Tibetan administration encompassing all Tibetan autonomous areas. This is crucial for the genuine implementation of China's constitutional provisions regarding national regional autonomy.Between 2002 and 2010, nine rounds of formal talks took place between representatives of His Holiness the Dalai Lama and the Chinese Government.



Beijing, however, rejected our entire proposal, including our request for a single Tibetan administrative unit. They claimed that the proposed autonomous region would be too large and that Tibetans have historically never been governed under a single administration. This claim is a clear distortion of historical facts. I quote an excerpt from China's gradual military conquest of eastern territories of a speech by former Kalon Tripa, Prof Samdhong Rinpoche: "Tibetans were under one administration until the mid-ninth century. Later, Tibetans were again reintegrated into one administration in 1260 under Drogon Choegyal Phakpa. This was offered to him by emperor Kublai Khan and this offering explicitly refers to the three Cholkas with a clear demarcation of its borders. Such unified administration remained until the 1730s."

China further distorted the definition of 'Tibet' by introducing the notion of 'Greater Tibet'. While Tibetans, like people from any other nation, proudly refer to their homeland as great, Beijing has very deftly rephrased this as 'Greater Tibet'. This is a vicious distortion of Tibetan territorial identity. For Tibetans, there is no concept of 'Greater' and 'Smaller' Tibet; there is simply Tibet, as understood in our collective consciousness.

Beijing has now gone a step too far by attempting to supplant the term 'Tibet' with 'Xizang'. It is important to note that Beijing's definition of even 'Xizang' differed both before and after the invasion of Tibet in 1949-50.

In ancient times, such as in the Sino-Tibetan treaty of 821-822, the terms 'Great Tibet' and 'Great China' were used. Before 1949, the Republic of China employed the terms 'Inner Tibet' and 'Outer Tibet' to differentiate regions within Tibet, similar to the use of 'Inner Mongolia' and

'Outer Mongolia' for Mongolia. 'Inner Tibet' referred to the areas under Chinese control at that time, while 'Outer Tibet' denoted independent Tibet. These terms also appeared in the Simla Convention (1913-14), which involved Great Britain, China and Tibet.

Tibet was swiftly followed by the renaming of the newly annexed places. For example, Ziling was renamed Xining, Dhartsedo became Kanding, Bathang (my homeland) was changed to Ba an, and Chamdo was renamed Changdu. China then developed and promoted its own narrative, claiming that only the territories under the effective control of the Government of Tibet at that time constituted Xizang.

They believe that by renaming places annexed through military conquests and forging new identities and historical narratives, they can gradually root out and erase the deep, centuries-old bond between the people of these areas and historic Tibet. The current reality, however, is quite the opposite. Since the disintegration of the mighty Tibetan Empire in the ninth century and the eventual inception of the Dalai Lama's Gaden Phodrang Government in Tibet in 1642, what is ubiquitous across the Tibetan plateau today is a strong, deep sense of common territorial and national identity.

Beijing's quest to replace 'Tibet' with 'Xizang' is, therefore, destined to fail. If history is any guide, the imposition of Chinese identity through the distortion of historical and cultural narratives will only further alienate the Tibetan people and strengthen their sense of distinct national identity.

New pension scheme

Staff welfare, fiscal prudence equally important

THE Centre has unveiled broader benefits for its employees in the new guaranteed pension scheme. The Unified Pension Scheme (UPS) is surely a political response to the growing nationwide demand to revert to the pre-2004 Old Pension Scheme (OPS). The Centre claims the UPS, to be implemented from April next year, will benefit 23 lakh employees. Those covered under the current National Pension System will have a chance to shift to the UPS. The move is aimed at resolving the debate on the OPS, a cause championed by many Opposition-ruled states, including Himachal Pradesh and Punjab, on the ground that its benefits are more favourable to employees. With an eye on the upcoming Assembly elections, the BJP-ruled states are expected to adopt the UPS. The tweaking of the pension scheme presents a chance to the stakeholders in all states to have an informed discussion,



keeping an open mind. A summary dismissal without an in-depth study of the provisions or offering insightful suggestions will be an opportunity lost.

The Reserve Bank of India had last year flagged concerns about the strain on government finances and accumulation of liabilities for the states opting for OPS. The Centre's contention is that the UPS is fiscally more prudent as it is a funded, contributory scheme, unlike the OPS. The likely additional strain on the Centre and the states now has official sanction. Striking a balance between employee welfare as well as their aspirations and fiscal prudence must be the guiding principle. Both are equally important.

The mixed response by the employees' unions is on the expected lines. Sticking to a hard stance is an unreasonable approach. As for employees in the private sector, their hopes for any enhanced pension and retirement benefits do not seem a priority for the

Charge of the Indian-American brigade

Kamala Harris' presidential nomination is in sync with Howard Dean's 2008 prophecy

FOR a country with a relatively short history by the standards of humankind, the United States, which does not live even by the brevity of its history, is seeing a difference in its ongoing presidential election cycle. The just-concluded Democratic National Convention (DNC), which broke glass ceilings, was replete with history. It was appropriate that Hillary Clinton, former Secretary of State, First Lady, Senator and 2016 presidential candidate, was the prime-time DNC speaker who reminded the American people, more than anyone else by implication, of the George Santayana adage — "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." She did not quote the Spanish philosopher at the Chicago convention, though. The biggest setback in her career, a defeat at the hands of newbie politician Donald Trump eight years ago, was partly the result of not remembering history. Specifically, the history of US elections.

Last week, Hillary recalled that women in the US got the right to vote only 104 years ago — on the day before she spoke — in 1920. The first time a Black woman bid for a presidential nomination — unsuccessfully, of course — was not very long ago: in 1972. Twelve years later, Hillary took her young daughter Chelsea to meet Geraldine Ferraro, the first woman nominated for Vice-President of the US. And in 2016, Hillary made almost 66 million cracks in the glass ceiling with her candidacy of a major party for the White House. That was the number of popular votes Hillary received then. Kamala Harris, the incumbent Vice-President, hopes to shatter that cracked glass ceiling in November and become the first woman President of the US. If Harris wins, she will also break a glass ceiling for South Asian-Americans. Historically, it has been at Republican National Conventions (RNC) that America's past has been celebrated. In part, this has been because some of the great US presidents have

been Republicans — Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt and Dwight D Eisenhower, to mention a few. Lincoln was the first 'red-blooded' Republican to be elected President, to cite the party's preferred colour. Others who embodied Republican ideals were elected as Democratic-Republicans or as Whigs, according to political descriptions during varying periods in the political evolution of the US. The US did not have a Catherine the Great, a Bismarck or a Chanakya. So, it fell on Republicans in the

final decade of the last century and in the new millennium to create an icon of Ronald Reagan. At every RNC I attended through five presidential election seasons from the year 2000, Reagan was the great Republican hero. That changed with the arrival of Donald Trump on the political scene. The RNC in Milwaukee this year was bizarre. First-time voters who attended it could not be blamed if they thought US history began only in 2015 when Trump began his improbable and then unpredictable quest for the White House.

Indians are, unfortunately, familiar with such a catastrophe in their midst. To turn around a memorable description of democracy by Republican Lincoln, the Milwaukee gathering, which renominated Trump as their party's nominee for the November election, was a convention of one family, by one family and for one family: the Trumps.

Only one person and one family by extension matters in the Grand Old Party (GOP) now. The Republican Party has become a cult. By contrast, a hundred flowers bloomed at the DNC in Chicago. Brilliant orators like former presidents Bill Clinton and Barack Obama, who represent diversity, bloomed. So did former First Lady Michelle Obama, who enjoys a phenomenal public acceptance despite never holding an elected office. The first Indian to attend a DNC was a Sikh American, Dalip Singh Saund, in 1952. Indians like Saund were not allowed to embrace US nationality until legislation permitting it was passed in 1946. Saund was the first Indian-American to be elected to the US House of Representatives in 1956. Had he not been felled by a stroke in 1962, Saund may have risen



another Indian-American in either of the chambers of Congress for another 42 years. Today, there are five of them, all Democrats. The GOP has elected ony one Indian-American to the House to date: Piyush 'Bobby' Jindal. A few decades ago, Indian-American Republicans, along with sympathetic White and Hispanic GOP leaders, drew up a road map for getting those like Jindal into statewide public offices in

southern states, known as Dixieland in popular culture. It had some success when Jindal was elected as the first Indian-American Governor in any US state in 2007. Nikki 'Nimrata' Haley was next, in South Carolina, four years later. The plan to put more Indian-Americans in elected offices in Dixie states appears to have fizzled out. Jindal and Haley both made unsuccessful bids to be GOP nominees for the White House in subsequent election cycles.

With ethnic half-Indian origin Harris now a heartbeat away from the White House, Indian-Americans and their former compatriots back home must pay a tribute to her rise to a forgotten former Democratic Party chief, Howard Dean. A three-term Governor of Vermont and a presidential aspirant two decades ago, Dean was the first national-level US politician to predict the rise one day of an ethnic Indian as America's President. Few people remember that in 2008, Dean, as Chair of the Democratic National Committee, wrote an article in a publication of the Indian-American Leadership Initiative. This initiative was created to put US citizens of Indian origin in electable public offices, right down from local school boards, county councils and as city mayors to high up on Capitol Hill. "Indian-Americans are leading the charge to strengthen our (Democratic) Party, elect our candidates and ensure that we build a government that lives up to

the ideals that inspired generations of Indian immigrants to make America their home," Dean wrote. "Perhaps they include a future Democratic President of the US.'

Harris was a local party functionary seeking to grow in public life in her home state of California then. There is no evidence that Dean had Harris in mind when he wrote those lines. Today, they appear prophetic.

Big bucks, bigger stress: Inside the lives of Nvidia's millionaire employees

New Delhi. Global chipmaking giant Nvidia has created a new wave of millionaires among its employees, thanks to a staggering 3,776% increase in its stock value since

However, this financial success comes at a big price.

The chipmaker's employees are enduring long hours and high stress, contributing to a demanding work environment despite their substantial wealth, reported Bloomberg News.The company's intense culture, characterised by extended workweeks and a chaotic management structure, reflects the pressures faced by those reaping the financial rewards. The report highlights how Nvidia employees now own luxury vehicles like Porsches, Corvettes, and Lamborghinis, but are frequently seen at the office rather than enjoying the fruits of their labour.

Big money, big stress

The company's stock surge, driven by its dominance in artificial intelligence chip sales, has led to considerable financial gains for its staff. Nvidia's market cap has increased faster than any other company in history, creating numerous multimillionaires.

Yet, the high-stakes environment comes with a demanding work culture. Employees report long hours, high stress, and a chaotic organizational structure.

CEO Jensen Huang's approach to management highlights rigorous work expectations and a high-pressure atmosphere. Huang is known for his belief in pushing employees hard, stating that he prefers to "torture them into greatness" rather than resort to layoffs. Golden handcuffs'

Current and former employees, quoted in the Bloomberg report, describe a gruelling work environment.

One former technical support worker shared that he was expected to work seven days a week, often late into the night.nother former marketing employee noted attending multiple high-stress meetings daily, despite the lucrative stock options that made it difficult to leave the company. Despite the high-stress environment, the employee had endured it for two years due to the "golden handcuffs"—the promise of substantial financial rewards that made it difficult to leave.

Nvidia's stock grants vest over four years, which has helped retain employees despite the intense work culture. The turnover rate dropped significantly after Nvidia's valuation surpassed \$1 trillion, from 5.3% in 2023 to 2.7%. This starkly contrasts with the semiconductor industry's average turnover rate of

Explained: Why Patym shares surged 3% despite Sebi notice

NEW DELHI. Shares of Paytm's parent company, One 97 Communications, rose by 3.5% to Rs 548.70 on Tuesday despite having received a show-cause notice from the Securities and Exchange Board of India (Sebi). The rise in shares was mainly due to Paytm's clarification on the matter in response to the notice, which seemed to reassure investors. Sebi's notice was related to an alleged violation of rules concerning the employee stock option plans (ESOPs) granted to Vijay Shekhar Sharma, Paytm's founder and Chief Executive.In the financial year 2021-22, Paytm granted 21 million ESOPs to Sharma, which were tied to the achievement of specific milestones. Paytm had already disclosed the matter in its financial results for the quarter and year ending on March 31, 2024, as well as the quarter ending on June 30, 2024. In a filing to the exchanges, Paytm mentioned that they are in regular communication with Sebi and are making the necessary representations to address the situation."With reference to recent media reports, we would like to inform you that this is not a new development, as the Company had already made relevant disclosures on this matter in its financial results for the quarter and year ended March 31, 2024, as well as the quarter ended June 30, 2024. The Company is in regular communication with the Securities Exchange Board of India (SEBI) and making necessary representations regarding this matter. Accordingly, there is no impact on the financial results for previous quarters ended June 30, 2024, and March 31, 2024, respectively," said Paytm in an exchange filing.

Paytm's shares have seen a decline over the past year, dropping by 40%. So far, in 2024, the shares have fallen by 16.3%. However, today's rise suggests that investors might be looking beyond the recent regulatory issues and focusing on the company's ongoing efforts to address them.

JN Port secures Rs 45,000 cr funding from REC for various upcoming projects

MUMBAI. The Maharana public sector non-bank lender REC has signed an agreement with the Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) to finance up to Rs 45,000 crore for the country's largest container port's various upcoming projects, which include the development of the nearby Vadhavan Port. The port handles a little over 50% of the containerised cargo volume in the country. The loan agreement was signed by the port's chairman Unmesh Sharad Wagh and REC executive director Rahul Dwivedi, in the presence of the Union ports and shipping minister Sarbananda Sonowal. For REC, this large funding helps expand its non-power portfolio, the company said in a statement Monday. Currently its Rs 5.3 trillion (`5.3 lakh crore) loan book comprises power generation, transmission, distribution renewables projects and new technologies such as electric vehicles, battery storage, pumped storage, green hydrogen and green ammonia projects. Since recent years it also strayed funding roads, expressways, metro rails and airports etc apart form social infrastructure projects like schools hospitals Hmong others. For the quarter ending June, REC reported as 18 percent jump in revenue to Rs 13,092.44 crore from which it booked a net profit of Rs 3,460 crore, which was 16.6% more than it had booked in the same period of of the past fiscal.

Sensex, Nifty end flat as energy, consumer stocks weigh in on gains

New Delhi. Benchmark stock market indices ended the day nearly unchanged on Tuesday, as gains in financial stocks balanced out declines in the energy and consumer sectors. This came as the global rally, driven by expectations of a possible rate cut in the US in September, took a breather."Weak US market cues and subdued Asian indices prompted local investors to book profit towards the fagend, indicating that intraday volatility will continue amid growing geopolitical tensions and sluggish global growth," said Prashanth Tapse, Senior VP (Research), Mehta Equities Ltd. The S&P BSE Sensex added 13.65 points to end at 81,711.76, while the NSE Nifty50 gained just 7.15 points to close at 25,017.75.

rinod Nair, Head of Research, Geojit Financial Services said that the domestic market witnessed profit-booking near record highs."While the positive expectations regarding a potential rate cut by the Fed in September remain, the recent geopolitical tensions and rising crude oil prices have made investors cautious amid high valuations. IT and financial stocks continued to perform well, whereas FMCG and metal stocks saw declines. Further, the recent shift in FII stance towards the domestic market and the anticipation that the RBI will align with the Fed's actions are expected to foster a positive outlook in the near term," said Nair.Zee's shares surged as much as 15% before settling 11.49% higher on the BSE at Rs 150.90 as it reached a settlement agreement with

Culver Max Entertainment Private Limited (formerly Sony India) and Bangla Entertainment Private Limited, resolving all disputes between the parties. Today's Nifty 50 trading saw a mix of notable gains and losses among top stocks. Leading the gainers was Larsen & Toubro (LT), which rose by 1.48%. Cipla followed closely with a 1.45% increase.



Infosys also performed well, climbing 1.14%. HCLTech and Sun Pharma rounded out the top gainers, rising 0.96% and 0.71% respectively.

BPCL led the declines, dropping 1.68%. JSW Steel followed with a 1.00% decrease. Eicher Motors saw its stock fall by 0.61%, while Grasim Industries dipped 0.60%. Kotak Mahindra Bank completed the list of top losers with a 0.58% decline."The sentiment has

entered an indecisive phase as the Nifty closed with a Doji pattern on the daily chart. The significant presence of both call and put option writers at the 25,000 strike price strengthens the technical setup. As a result, the Nifty is likely to remain range-bound or might experience a slight dip in the near term. On the lower end, 24,800 could act as immediate support, while a rise above 25,100 might push the Nifty towards 25,300," said Rupak

De, Senior Technical Analyst, LKP Securities. The Nifty Smallcap100 index led the gains, rising impressively by 1.05%, while the Nifty Midcap100 index also performed well, increasing by 0.49%, suggesting continued interest in medium-sized firms.

Meanwhile, the India VIX, often referred to as the fear gauge of the market, experienced a notable decline of 1.17%.

Still waiting for your income tax refund Here's what you need to do

New Delhi Filing your income tax return (ITR) on time doesn't always mean you'll receive your refund quickly. The tax refund process involves several steps, and if something goes wrong at any point, the entire process can get delayed.

You may be eligible for a tax refund when the tax you've already paid (through TDS, self-assessment tax, etc.) is more than your actual tax liability. The income tax department calculates this liability after considering all deductions and exemptions during the assessment.In our country, Income Tax Return (ITR) refunds may be delayed for a number of reasons. Vishal Gehrana, Advocate on Record, Supreme Court of India (associated with Karanjawala & Co) said that one common reason is the verification issue. If a taxpayer has not completed the verification process of their ITR either through an Electronic Verification Code (EVC) or by submitting a signed ITR-V to the



Central Processing Center (CPC), the processing of the refund may get delayed."The discrepancies in the ITR details - such as mismatch in the income figures, inaccurate bank account information, or errors in PAN details may also cause delays in the processing of ITR and refund," he added.

In cases where ITR involves complex income sources or multiple deductions, it may require manual processing, which can take much longer time to process and refund the ITR.Furthermore, delays can also arise from backlogs at the CPC, especially during peak filing times, or from a

taxpayer not complying with notices or requests from the tax department. Therefore, a taxpayer should attempt to file his return much before the deadline as helps to prevent the

What to do if ITR refund is delayed? If your refund is delayed, the first thing you should do is check the status on the income tax e-filing portal. This

will give you details on the current stage of processing and any issues that need your attention."If the delay is significant and unexplained, you can raise a grievance through the 'e-Nivaran' section on the e-filing portal or contact the CPC helpline for an update. It's important to respond quickly to any notices or requests from the tax department, as delays in your response can further extend the processing time," said Gehrana. Steps to raise tax refund reissue request

If your refund process is stuck for a long time, you might need to file a refund reissue request. Here's how you can do it:

LG Electronics considers IPO in India amid stock market boom: Report

LG Electronics is exploring the possibility of an initial public offering (IPO) for its Indian operations, aiming to capitalise on India's vibrant stock market to support its ambitious revenue goals. The South Korean electronics giant seeks to achieve \$75 billion in annual revenue by 2030, which is a big leap from its current revenue of approximately \$65 billion, reported Bloomberg.CEO William Cho, who took on the role in 2021 after a long tenure with LG Group, highlights the IPO as one potential strategy to rejuvenate the company's consumer electronics segment. "It is one of many options we can consider," Cho told Bloomberg Television. "I understand there's increased interest among global investors," he added.It's worth noting that this is LG's first public discussion about an Indian market debut, amid ongoing speculation and interest. "As of now, nothing is confirmed," he added. Cho's vision includes growing LG's electronics business to



100 trillion won (\$75 billion) annually by the end of the decade. A key component of this plan is increasing revenue from enterprise clients, aiming for 45% of sales to come from business customers, up from the current 35%. The company's Indian unit has been performing well, with revenue rising 14% to a record 2.87 trillion won in the first half of this year and net income climbing 27% to 198.2 billion won.

Booming Indian stock market

The performance highlights LG's desire to leverage the booming Indian stock market, which is currently experiencing a surge in IPO activity. India's capital markets are bustling, with 189 companies expected to raise \$5.6 billion through IPOs this year alone. The market's dynamism is drawing interest from other major players, such as Hyundai Motor Co., which is preparing its own significant IPO in India.

Cho noted that LG is closely observing the Indian IPO landscape and evaluating similar industry cases.Although LG has not yet determined a valuation for its Indian unit, the company is considering how an IPO could fit into its broader

Hindustan Unilever to appeal Rs 962 crore tax demand linked to GSK deal

NEW DELHI. Ahindustan Unilever Limited (HUL) has been served with a tax demand notice of Rs 962.75 crore by the Income Tax Department. The notice includes Rs 329.33 crore in interest and was issued by the Office of the Deputy Commissioner of Income Tax in Mumbai. The company announced the receipt of this order on August 23 in a regulatory filing on Monday. The tax demand stems from Deducted at Source (TDS) as required under the Income Tax Act, 1961. This issue arose during HUL's Rs 3,045 crore payment to acquire intellectual property rights (IPR) of the India Health Food Drink (HFD) business from GlaxoSmithKline (GSK) Group entities.HUL, in its filing, expressed



confidence in its position and stated that it plans to appeal the tax demand. the alleged non-deduction of Tax The company assured stakeholders that there would be no major financial impact at this stage. It believes it has a strong case based on existing judicial precedents, which suggest that the situs location) of an intangible asset, such as IPR, is tied to the situs of the owner. This precedent could mean that income from the sale of such intangible assets

may not be taxable in India.HUL

further clarified that it intends to take all necessary steps to contest the demand. The company also mentioned its right to indemnification, allowing it to recover the tax demand raised by the Income Tax Department, and that it would take appropriate action in this regard.On the stock market, HUL shares were trading flat at Rs 2,819 during early trading hours on the Bombay Stock Exchange (BSE) today. The company's market capitalisation stood at Rs 6.61 lakh crore, reflecting its significant presence in the FMCG sector.HUL received the ta order on Friday, August 23, and made the required disclosure to the exchanges on the next working day, which was Monday. The company has assured that it will comply with all legal processes as it moves forward with the appeal

against the tax demand

Apple may create 6 lakh jobs in India by end of financial year: Report Wistron (now Tata Electronics), and

The iPhone maker's growing operations in India have contributed significantly to job creation over the years.

NEW DELHI. Apple could create up to 6 lakh jobs in India by the end of the fiscal year 2025, reported The Economic Times. The iPhone maker's increasing operations in the country have contributed significantly to higher job creation, according to sources quoted in the report.

According to estimates shared by the company, Apple's direct workforce in India will reach 200,000 by March 2025, with women constituting about 70% of these positions. The company's three major contract manufacturers, Foxconn, Pegatron, have already generated 80,872 direct jobs, as per officials quoted in the ET report.Additionally, suppliers such as Tata Group, Salcomp, Motherson, Foxlink, Sunwoda, ATL, and Jabil have collectively created around 84,000 direct jobs. Since the launch of the smartphone Production-Linked Incentive (PLI) scheme in 2020, Apple and its partners have created approximately 165,000 direct jobs, said another official quoted in the report. The PLI scheme, initially targeting 200,000 jobs over five years, has seen this target reached in just four years, reflecting Apple's significant role in job creation in India. The government estimates that each direct job in the electronics sector The Tata Group's new facility in Hosur, generates three indirect jobs, suggesting that Apple's expansion could result in 500,000 to 600,000 total jobs by the fiscal year-end. The company has effectively replicated its successful China model in India, establishing a robust supply chain and manufacturing



Tamil Nadu, is expected to hire around 50,000 employees over time. This plant, which will begin iPhone production this October, will increase its capacity in phases.Moreover, Tamil Nadu has become a key hub for Apple's operations, with nearly 90,000 of the 200,000 direct jobs expected to come

from iPhone and component factories in the state.

Apple began manufacturing iPhones in India in 2021, marking its first production outside China. The company's production in India has risen steadily, with iPhone manufacturing reaching Rs 1.20 lakh crore in FY24, including Rs 85,000 crore in exports.

This production growth has positioned India as a critical component of Apple's global supply chain, contributing about 14% to the company's overall production. To support its growing workforce, Apple's vendors and suppliers are investing in housing complexes, particularly in Tamil

A recent facility in Sriperumbudur, built at a cost of Rs 706.5 crore, will house around 18,720 workers, mostly women. Additional housing projects are planned through public-private partnerships to further support Apple's expanding workforce in the region.

Pensions tackled, can government pre-empt the MSP farm fire?

Congress leader Rahul Gandhi referred to India Today's Mood of the Nation survey to double down on his demand for a pan-India caste-census. The survey also showed popular support for a legal guarantee for minimum support price (MSP), an issue the government is grappling with. Like in the case of the New Pension Scheme, will the government be able to pre-empt the MSP issue?

New Delhi: The Leader of Opposition (LoP) in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, referred to India Today's Mood of the Nation survey to double down on his demand for a nationwide caste-census. The survey that showed overwhelming support for the caste-census also showed popular support for another issue that the Narendra Modiled NDA government has been grappling with -- legal guarantee for minimum support price (MSP) of crops. The Mood of the Nation Survey (MOTN) for August, showed 86.6% of the respondents supporting a legal guarantee for MSP, an issue on which the farmers have been agitating even after the three farm laws were withdrawn by the Narendra Modi government in November 2021. The three farm laws saw prolonged agitation, with the farmers sitting on the borders of Delhi for months. They moved back after the laws were withdrawn but are still at the Shambhu border, pressing for their demand for a law seeking a guarantee to MSP for several

crops. This is one issue that has the potential of becoming a forest fire for the government. The question is will the government pre-empt it as it has moved on to address the anger over the New Pension Scheme (NPS)?

HOW THE BJP GOVERNMENT **DOUSED NPS FIRE WITH UPS**

The Congress has been trying to tap into the anger of government employees over the NPS issue. During several state elections, it promised to revert to the Old Pension Scheme (OPS) if voted to power. Not just the Congress governments in Himachal Pradesh, Rajasthan, and Chhattisgarh, the AAP government in Punjab too reinstated the Old Pension Scheme (OPS). The problem with the OPS is that it puts a huge burden of pension dues on the government. In the last few decades, the pension liability of the Centre spiked multifold, making it unsustainable. It was in January 2004, when the BJP government led by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, that the switch from



the OPS to the NPS was made. However, protests and demands for reforms persisted as employees felt that the New Pension Scheme (NPS) didn't guarantee a minimum income. The BJP, in order to navigate the issue, took a proactive approach. The government set up a committee under then finance secretary TV Somanathan to look into the concerns of the employees and made the decision to bring in a Unified Pension Scheme (UPS). The committee's recommendations have now been reflected in the UPS. The UPS assures a minimum

HOW THE MSP ISSUE IS AN ALBATROSS ROUND GOVT'S

The issue of giving a statutory status to the

minimum support price (MSP) has been a

long-standing concern for farmers across

India. The demand for a legal guarantee for MSPs gained momentum during the 2020–2021 farmer's protests, with various opposing political parties and farmer organisations pushing for a change.In fact, the statutory safeguard for MSPs was one of the key demands of the protesting farmers who sat at different border points of Delhi for around 16 months, protesting against three farm laws, which have been taken back now. It was the protests around the farm laws that saw the Shiromani Akali Dal (SAD), one of the BJP's oldest allies, part ways with it in 2020.In 2023, ahead of the Lok Sabha election, another ally, the Harayana-based Jannayak Janta Party (JJP) raised the issue of a legal guarantee for MSP on crops. The

Dushyant Chautala-led party parted ways with the NDA after asking the central government to consider giving a "written assurance of the continuation of Minimum Support Price (MSP) for crops". Support for farmers is a hot-button socio-political issue in Punjab and Haryana, two agriculturebased states. The BJP, which won all 10 of the Lok Sabha seats in Haryana in 2019, had to be content with just five seats in the 2024 election. Even after the protests ended, the MSP issue remained a significant challenge for the government, with farmers' protests and demonstrations becoming increasingly common. Earlier this year, the 'Delhi Chalo' protest saw various farmer's bodies from Punjab, Haryana, and western Uttar Pradesh marching towards Delhi with their demands, including the legal guarantee for MSP.Although the Centre in February said the committee to make MSP 'effective' had held 37 meetings with various stakeholders, a concrete outcome on the same is yet to come.

Jammu And Kashmir Polls: Congress Announces 1st List Of 9 Candidates

New Delhi: The Congress on Monday issued its first list of nine candidates for the three-phase assembly elections in Jammu and Kashmir, fielding party general secretary Ghulam Ahmad Mir from Dooru and former state unit chief Vikar Rasool Wani from Banihal. The announcement came after the Congress clinched a seatsharing deal with ally National Conference (NC).he NC and the Congress agreed to contest 51 and 32 seats respectively for the assembly polls in Jammu and Kashmir.

One seat each has been allotted to the CPI(M) and the Jammu and Kashmir National Panthers Party (JKNPP), the allies announced at a joint press conference at NC president Farooq Abdullah's residence in Srinagar after day-long negotiations. They also said there will be a "friendly contest" on five seats of the Union territory. Hours after the announcement, the Congress put out a list of nine candidates for the polls, fielding Mir from Dooru and Wani from Banihal. The party also fielded Surinder Singh Channi from the Tral seat, Amanullah Mantoo from Devsar, Peerzada Mohammad Syed from Anantnag, Shaikh Zafarullah from Inderwal, Nadeem Sharief from Bhadarwah, Sheikh Riyaz from Doda and Pradeep Kumar Bhagat from Doda West.

'Just Because Woman Is Educated...': Top Court's Rap As K Kavitha Gets Bail

New Delhi: The Supreme Court on Tuesday granted conditional bail to Bharat Rashtra Samithi leader K Kavitha following her arrest - by the Enforcement Directorate in March and the Central Bureau of Investigation a month later - in the Delhi liquor policy scam, in which Chief Minister Arvind Kejriwal and his ex deputy, Manish Sisodia, are also named.

Ms Kavitha is the second big opposition leader to get bail in this case; Mr Sisodia, who was arrested in February last year, was released earlier this month after the Supreme Court noting a delay in trial in his case too, said he could not be jailed for an "unlimited time" as it is a violation of his fundamental rights. Also arrested by both agencies, Mr Kejriwal remains in jail, having got bail in the ED case but not, yet, in that filed by the CBI. The Supreme Court this month refused relief. Today a two-judge bench of Justices BR Gavai and KV Viswanathan pointed Ms Kavitha - like Mr Sisodia - had already spent over five months in jail and that "the trial is not expected soon", even if the investigation has been closed."We find the investigation is complete. As such, custody of appellant is not necessary... she is in jail for five months and, as observed with Sisodia, likelihood of trial be in near future is impossible..." it said.

The court also noted "the law provides special treatment for women while considering bail applications", referring to provisions in Section 45 of the Prevention of Money Laundering Act that "permits certain category of accused, including women, to be released on bail without (satisfying) twin requirements."

On this note the Supreme Court strongly objected to the Delhi High Court rejecting Ms Kavitha's plea - on grounds she is an educated woman. The High Court had said in July that Ms Kavitha could not be given bail despite arguments that it is "normal practice" for women to be released on bail - as her education and status (of a former Member of Parliament) meant she was not a 'vulnerable' woman. Arguing the High Court had "totally misapplied" the relevant section of the law, the Supreme Court said, "... the courts, while deciding such matters, should exercise discretion judicially. The court cannot say that merely because a woman is highly educated, or an MLA, (she) should be denied benefit of bail.""(Then) every arrested woman will get bail..." the

prosecution argued in vain. 'Illegally Imprisoned..."

Shortly after the bail order was passed the BRS posted on X, "She was illegally imprisoned for 166 days... without showing of any evidence. Justice finally won in a politically motivated case." Ms Kavitha's brother, BRS Working President KT Rama Rao, was in court when bail was granted.

'Bail Is 'Normal Practice' For Women"

Earlier senior advocate Mukul Rohatgi argued it is "normal practice" for women to get bail. The plea also identified her as mother to two kids, one of whom is a minor in shock and undergoing medical care.

Jodhpur-bound Vande Bharat hits cement slab placed on tracks, none hurt

Vande Bharat Express hit a cement slab that was placed on the railway track in

Rajasthan's Pali district on August 23.According to railway officials, the cattle guard of the engine hit the cement slab, when the train was running between the Jawai-Biroliya section of Pali district.No one was injured in the incident, North West Railway CPRO Shashi Kiran said in a statement, adding that the train was delayed by eight minutes due to the incident.A case was

also registered against unidentified people on the complaint of the Senior Section Engineer (SSE) of Falna region, Kiran said."The incident He further added that pieces of the



Friday night. A case against an unidentified person has been registered," a police official said.

occurred between Jawai and Biroliya cement slab, used for constructing under the Sumerpur police station on footpaths, were found on the track. The

Ahmedabad-Jodhpur Vande Bharat Express, which runs six days a week except for Tuesdays, departs from Sabarmati Station at 4.45 pm and reaches Jodhpur at 10.50 pm.In October last year, a major incident was averted by the locomotive pilots of the Udaipur-Jaipur Vande Bharat Express when they applied emergency brakes after spotting stones and rods on the tracks. The stones and rods were

placed on the tracks by two children while they were playing, a Rajasthan

Centre's New Guidelines Promise Public Grievance Redressal Within 21 Days

New Delhi: The Centre has issued comprehensive guidelines for a time-bound handling of public grievances filed by citizens on an integrated user-friendly CPGRAMS www.pgportal.gov.in portal which will operate as a single window open platform.

The timelines for effective grievance redressal have been reduced to 21 days from 30 days.In cases where grievance redressal is likely to take longer, citizens shall be given an interim

reply, states the order issued by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG).Feedback on disposed grievances shall be sent to the citizen by SMS and email. For every disposed grievance, feedback shall be collected through the feedback call centre, and if the citizen is not satisfied, he can file an



appeal to the next senior authority, the order further states. The guidelines are aimed to empower citizens in line with the Prime Minister's directions for making grievance redressal timebound, accessible and meaningful, an official statement said.

The guidelines state that Nodal Officers for Public Grievances will be appointed in all Ministries/

grievances promptly, fairly and efficiently. Ministries/ Departments with high grievance loads will have dedicated Nodal Officers."This means that in no case shall a grievance be closed by stating 'Does not pertain to this Ministry/Department/ Office' or its equivalent language. Efforts shall be made to transfer the same to the right authority if the

subject of the grievance does not pertain to the receiving Ministry," according to the (DARPG) order. The role of the Nodal Officer is effective categorisation, monitoring pendency, examining the feedback for process and policy improvements, undertaking root cause analysis, collation of monthly data sets and supervisory oversight of the Grievance.

Supreme Court Stays Centre's Notification On Drugs, Cosmetic Rules

New Delhi: The Supreme Court on Tuesday stayed a notification issued by the Ministry of Ayush, which omitted rule 170 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 that prohibits misleading advertisements of Ayurvedic, Siddha, and Unani drugs.A bench of Justices Hima Kohli and Sandeep Mehta said the notification issued by the ministry was in the teeth of its May 7, 2024 order.Clamping down on misleading advertisements, the apex court on May 7, 2024 had directed that before an advertisement is permitted to be issued, a self-declaration be obtained from the advertisers on the line of the Cable Television Networks Rules, 1994.

Instead of withdrawing the letter dated August 29, 2023, for reasons best known to the ministry, the notification dated July 1 to omit Rule 170 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, has been issued which runs contrary to directions issued by this court..."Till further orders, effect of the notification dated omitting shall stand stayed," the bench said. Additional Solicitor General K M Nataraj, appearing for the Centre, submitted that he will file an affidavit clarifying the position. The Centre had earlier defended its August 2023, letter to states and Union territories asking authorities not to initiate action against any entity for violating Rule 170 of the Drugs and Cosmetics Rules."It is respectfully submitted that as the process of final gazette notification will take further time, in order to avoid confusion among the various State/UT SLAs (state licensing authorities) and to prevent avoidable litigations, Ministry of Ayush vide letter dated August 29, 2023 directed all state/UTs licensing authorities not to take any action under Rule 170 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 as the final notification is under process," the Centre had said in its affidavit. The top court had in May questioned the Centre over an August 29, 2023 letter by the Ministry of Ayush asking the licensing authorities not to initiate or take any action under rule 170 of Drugs and Cosmetics Rules, 1945. The bench had told Nataraj that the ministry shall "forthwith" withdraw the August 29 last year letter. The apex court is hearing a plea filed in 2022 by the Indian Medical Association alleging a smear campaign by Patanjali and yoga guru Ramdev against the Covid vaccination drive and modern systems of medicine.

US Diplomats' Kashmir Visit "Within Boundaries Of Diplomatic Reach": Sources

A three-member delegation of US diplomats visited **Srinagar on Monday** ahead of the Assembly elections in the Union Territory after a gap of 10 years.

New Delhi: A three-member delegation of US diplomats visited Srinagar on Monday ahead of the Assembly elections in the Union Territory after a gap of 10 years.

The visit is well within the boundaries of diplomatic outreach mechanism of the US State Department," a senior government An official said that US and India have

official told .According to the official, the visits are not unusual as similar visits with diplomats were common in the erstwhile state of Jammu and Kashmir. "They get a chance to make on-ground assessments,"

The delegation included Minister-Counselor for Political Affairs Graham Mayer, First Secretary Gary Applegarth, and Political Counselor Abhiram. They met political leaders from Kashmir including former chief minister Omar Abdullah as well as former mayor of Srinagar Junaid Azim Mattu."The presence of CIA station head Graham Mayer in Srinagar is an indication that

US is observing elections minutely, especially in backdrop of US interests in Pakistan and recent reports of Chinese inroads in Ladakh," a source told

increased coordination to ensure security in Ladakh. According to him, Mr Mayer had also visited Srinagar in 2023 and met Lieutenant Governor Manoj Sinha. Interestingly, the visit comes at a time when



terror attacks in the Valley have increased. "India has been insisting that terror is being exported from Pakistan and weapons are being smuggled from Afghanistan. The recovered weapons bear clear US markings. So there is ample

proof to establish connection," an official said. National Conference Chief Spokesperson Tanvir Sadiq said that the delegation's discussions addressed a wide range of issues concerning Jammu and

Kashmir and the broader region. Former chief minister Omar Abdullah also raised the recent travel advisory issued by US for the region. In July, US had asked its nationals not to travel to Manipur, Jammu and Kashmir, the India-Pakistan border, and parts of central and eastern parts of the country where Maoists are active."Some areas have increased risk. Do not travel to the union territory of Jammu and Kashmir (except the eastern Ladakh region and its capital

Leh) due to terrorism and civil unrest," the advisory said.US is among several countries that have issued travel advisories, asking their citizens not to visit Jammu and Kashmir.

Biden administration pressured Meta to censor Covid content: Mark Zuckerberg

World Mark Zuckerberg, in a letter to the US House Judiciary Committee of the Republican Party, claimed that the Biden-Harris administration "repeatedly pressured" his company, Facebook, to censor Covid-related posts. While expressing "regrets" for not being "more outspaled", about it the Mate Clife. outspoken" about it, the Meta Chief Executive Officer (CEO) also alleged that his social media platform had to make certain modifications that "with the benefit of hindsight and new information," they would not make today."There's a lot of talk right now around how the US government interacts with companies like Meta, and I want to be clear about our position," Zuckerberg wrote in a letter addressed to the panel."Our platforms are for everyone we're about promoting speech and helping people connect in a safe and secure way. As part of this, we regularly hear from governments around the world and others with various concerns around public discourse and public safety."He told the panel that in 2021, "senior officials" from the White House "repeatedly pressured our teams for months to censor certain Covid-19 content, including humour and satire."When his company refused to agree with the censorship, the Meta CEO said that the Biden administration expressed a lot of frustration."Ultimately, it was our decision whether or not to take content down, and we own our decisions, including COVID-19related changes we made to our enforcement in the wake of this pressure," he wrote. The US House Judiciary panel posted Zuckerberg's letter on X, with the caption reading, "Mark Zuckerberg just admitted three things: 1. Biden-Harris Admin "pressured" Facebook to censor Americans. Facebook censored Americans. 3. Facebook throttled the Hunter Biden laptop story. Big win for free speech."Taking a veiled dig at the Democrats, Musk, while retweeting Zuckerberg's letter on his official X handle, said, "Sounds like a First Amendment violation." In his letter, Zuckerberg also recounted that before the 2020 election, the Federal Bureau of Investigation (FBI) had alerted Meta to a possible Russian disinformation campaign targeting the Biden family and Burisma. Acting on this warning, Meta decided to down-rank a story that alleged corruption involving the Biden family. However, Zuckerberg clarified that, in hindsight, the decision to demote the story was a mistake, as it was not part of a Russian disinformation effort.

Hezbollah suffered 'crushing blow' but current situation not sustainable: Israel

World Israeli officials and media reacted with satisfaction on Monday after a long-expected missile attack by the Iranian-backed Hezbollah movement appeared to have been largely thwarted by pre-emptive Israeli strikes in southern Lebanon.Both Hezbollah and Israel seemed content to let Sunday's attack, in retaliation for the killing of a senior Hezbollah commander in Beirut last month, count as settled for the moment.

Israeli government spokesperson David Mencer said Hezbollah had suffered a "crushing blow" from the Israeli strikes but that a longer lasting solution was still needed. The current situation is not sustainable," he told a briefing, referring to the tens of thousands evacuated from their homes in northern Israel, a situation mirrored on the other side of the border in southern Lebanon. "Israel will do its duty and return its population to our sovereign territory."

Hopes that children might return for the start of the new school year in September have evaporated, with financial assistance for residents evacuated from their homes extended to September 30. However, there was some optimism that the exchange of fire, which did not cause the kind of extensive damage many in Israel had feared, might help talks aimed at halting the fighting in Gaza and bringing Israeli and foreign hostages home.Palestinian militant group Hamas has said it will not agree to a deal that allows Israeli troops to remain in the band of territory at the southern edge of the Gaza Strip along the border with Egypt. But some commentators said Sunday's exchange of fire might prove that Hamas lacked the kind of support it would need to push the conflict outside Gaza."Maybe - just maybe - Israel's success at foiling Hezbollah's retaliation might pave the way to concessions by Hamas in the negotiations over a hostage deal, given the failed bid to see the war expanded to engulf the entire region," wrote Avi Issacharoff, a commentator in Israel's biggest-selling daily Yedioth Ahronoth.

Early Sunday, around 100 Israeli jets hit dozens of Hezbollah launch sites in southern Lebanon, destroying thousands of rockets the military said were aimed at Israel. Hezbollah did launch hundreds of missiles, but most were intercepted or fell in open

Exchanges of fire continued on Monday, but were muted by comparison.Israel said it struck a Hezbollah military structure in southern Lebanon, and that a number of suspicious aerial targets had entered its territory from Lebanon. Most of the targets were intercepted and there were no injuries.

4 dead as Russia pounds Ukraine with missiles, drones for second day

UPDATED. Russia launched several waves of missile and drone attacks targeting scores of Ukrainian regions and killing at least four people, Ukraine's military said early on Tuesday, a day after Moscow's biggest air attack of the war on its neighbour. Two people were killed when a hotel was "wiped out" in the central Ukraine city of Kryvyi Rih, regional officials said. Two died in drone attacks on the city of Zaporizhzhia, east of Kryvyi Rih.Kyiv region's air defence systems were deployed several times overnight to repel missiles and drones targeting the Ukrainian capital, the region's military administration said on Telegram.Reuters' witnesses reported at least three rounds of explosions overnight in

On Monday, Russia launched more than 200 missiles and drones, killing at least seven and damaging energy infrastructure in an attack condemned by US President Joe Biden as "outrageous". Analysts at the Washington-based think tank Institute for the Study of War, said in their note late on Monday that Moscow "likely lacks the defense-industrial capacity to sustain such



massive strikes at a similar scale with regularity."Several Russian military bloggers, such as the pro-war collective under the name of Rybar, called the Moscow attacks an "act of retaliation" for Ukraine's surprising incursion into Russia's territory the first such action since World War Two. The Kremlin said on Monday there will be a response to Ukraine's action in Kursk, but three weeks into the incursion, Kyiv

claims further advances. Moscow says it keeps pummelling Ukraine troops there - but is still unable to push them out. The size of the Tuesday attacks and their full impact was not immediately known, but Ukraine's air force said it recorded the launch of several groups of drones and the take-off from Russian airfields of strategic Tu-85 strategic bombers and MiG-31 supersonic interceptor aircraft. Reuters could not independently

verify the reports. There was no immediate comment from Russia. The Kremlin denies targeting civilians in the war that President Vladimir Putin launched against Russia's smaller neighbour with a full-scale invasion in February 2022. The Russian defence ministry said that its strikes on Monday hit "all designated targets" in Ukraine's critical energy infrastructure.Kryvyi Rih, Kyiv and central and eastern regions of Ukraine were under air raid alerts for most of the night, starting at around 2000 GMT on Monday. Two civilians may be still under the rubble of the hotel in Kryvyi Rih and five were injured in the attack, Serhiy Lisak, the governor of the Dnipropetrovsk region where Kryvyi Rih is located, said on Telegram. Six shops, four high-rise buildings and eight cars were also damaged there, he added.In Zaporizhzhia, two people were killed and four injured overnight, Ivan Fedorov, governor of the Zaporizhzhia region, said on Telegram."Such are the consequences of the overnight attack by Shaheds on Zaporizhzhia," Fedorov said, referring to the Iranian-made kamikaze drones that Kyiv says Russia uses in its

Nepal maintains friendly ties with India, China in 'balanced' manner: PM Oli

World Nepal maintains friendly relations with both India and China in a "balanced" manner, Nepal Prime Minister KP Sharma Oli said on Monday, underlining that occasional problems between neighbours are "natural" and can be resolved through "open dialogue". Speaking at a book release function here, Oli said, "We don't allow our land to be used against any of our neighbours."He said the Himalayan nation maintains "good and friendly relations with both neighbours in a balanced manner by observing honesty and neutrality."The 72year-old four-time prime minister said it is natural to occasionally have problems

with neighbours. "We can resolve them

through open dialogue," he said."The problem will not arise if we seek



the basis of facts and proofs by maintaining international obligations without elaborating on the matter much," Oli said while speaking as the chief guest at the book release function."We adhere to the principles of the United Nations and seek neutral and peaceful solutions to the problems," he said, asserting that it is not for hiding internal weakness.He also asked the Indian side to accept the report prepared by the Nepal-India Eminent Persons Group (EPG Report) which includes among other things the matter relating to the review of the Peace and Friendship Treaty of 1950. He said it would facilitate dialogue to sort out border issues and other

Recalling the signing of the Trade and Transit Treaty with China during his previous tenure as the prime minister, he said it was indeed a big achievement.Oli, widely regarded as pro-China, saw the signing of the 2016 Transit and Transport Agreement (TTA) which gave the landlocked Himalayan country access to Chinese sea and land ports for its foreign trade.

justifiable and appropriate solutions on appropriate to always blame geopolitics Pacific Ocean rising at alarming rate: **António Guterres's 'SOS' warning**

World United Nations Secretary-General Ant³nio Guterres voiced a global climate "SOS" at a Pacific islands summit on Tuesday, unveiling research that shows the region's seas rising much more swiftly than global averages."I am in Tonga to issue a global SOS -- Save Our Seas -- on rising sea levels. A worldwide catastrophe is putting this Pacific paradise in peril" he said. Sparsely populated and with few heavy industries, the Pacific islands collectively pump out less than 0.02 percent of global emissions every year.But this vast arc of volcanic islands and low-lying coral atolls also inhabits a tropical corridor that is rapidly threatened by encroaching oceans.

The World Meterological Organisation has been monitoring tide gauges installed on the Pacific's famed beaches since the early 1990s. A new report released by the top UN climate monitoring body showed seas had risen by around 15 centimetres in some parts of the Pacific in the last 30 years. The global average was 9.4 centimetres, according to the report.

'It is increasingly evident that we are fast running out of time to turn the tide," said the forecasting agency's top official Celeste Saulo. Some sites, particularly in Kiribati and Cook Islands, measured a rise that matched or was just under the global average.But other sites, such as the capital cities of Samoa and Fiji, were rising almost three times higher.

In low-lying Pacific nation Tuvalu, land is already so scarce that throngs of children use the tarmac at the international airport as their own makeshift playground. Scientists have warned that, even under some moderate scenarios, Tuvalu could be almost entirely wiped off the map within the next 30 years.

"It's disaster after disaster, and we are losing the capacity to rebuild, to withstand another cyclone or another flood," Tuvalu Climate Minister Maina Talia told AFP on the summit's sidelines. "For low-lying island states, it's a matter of survival for us."The plight of Pacific islands has been easily overlooked in the past, given their relative isolation and lack of economic might.But the region is increasingly seen by scientists as a climate canary in the coal mine, hinting at the troubles possibly facing other parts of the planet."This new report confirms what Pacific leaders have been saying for years," Australian climate researcher Wes Morgan told AFP.

Protests across Canada as 70,000 international students face deportation

World More than 70,000 international student graduates in Canada face the risk of being deported due to recent changes in federal immigration policies. The students, who came to Canada with hopes of building a new life, are now protesting across the North American country against the Justin Trudeau government's decision to limit study permits and reduce permanent residency nominations. Demonstrations are taking place from coast-to-coast, with international students setting up encampments and organising rallies in various provinces, including Prince Edward Island (PEI), Ontario, Manitoba, and British Columbia.In PEI, hundreds of students have been protesting outside the legislative assembly for over three months, challenging the changes in immigration rules.Representatives from the Naujawan Support Network, a student advocacy group, have warned that many graduates could face deportation when their work permits expire at the end of the year. The situation has become particularly dire due to new provincial policies that have introduced a 25% reduction in permanent residency nominations, leaving many students unexpectedly vulnerable.

I spent six years taking risks to come to Canada. I studied, worked, paid taxes, and earned enough Comprehensive Ranking System (CRS) points, but the government has taken advantage of us,' Mehakdeep Singh, a former international student facing deportation, told City News Toronto. Singh, who invested his family's life savings in

tuition, is now confronting a daunting deadline with no guarantee of permanent residency. WHY CANADA CÛT STUDY VISAS FOR

INTERNATIONAL STUDENTS

The inflow of international students, who made up 37% of study visa holders in 2023, put significant pressure on Canada's housing, healthcare, and other services. In response, the Canadian government has imposed a can on international student permit applications to manage the growth over the next two years

Texas judge halts Biden programme giving legal status to spouses of US citizens

World A federal judge in Texas on Monday paused a Biden administration policy that would give spouses of U.S. citizens legal status without having to first leave the country, dealing at least a temporary setback to one of the biggest presidential actions to ease a path to citizenship in years. The administrative stay issued by U.S. District Judge J. Campbell Barker comes just days after 16 states, led by Republican attorneys general, challenged the program that could benefit an estimated 500,000 immigrants in the country, plus about 50,000 of their children. The states accused the administration of bypassing Congress for "blatant political purposes." One of the states leading the challenge is Texas, which in the lawsuit claimed the state has had to pay tens of millions of dollars annually from health care to law enforcement because of immigrants living in the state without legal status.President Joe Biden announced the program in June. The court order, which

lasts for two weeks but could be extended. comes one week after the Department of Homeland Security began accepting applications."The claims are substantial and warrant closer consideration than the court has been able to afford to date," Barker wrote.Barker was appointed by former President Donald Trump in 2019 as a judge in Tyler, Texas, which lies in the 5th U.S. Circuit Court of Appeals, a favoured venue for advocates pushing conservative arguments. The judge laid out a timetable that could produce a decision shortly before the presidential election November 5 or before a newly elected president takes office in January. Barker gave both sides until October 10 to file briefs in the case. The policy offers spouses of U.S. citizens without legal status, who meet certain criteria, a path to citizenship by applying for a green card and staying in the U.S. while undergoing the process. Traditionally, the process could include a years-long wait



outside the U.S., causing what advocates equate to "family separation." The Department of Homeland Security did not immediately return an email seeking comment on the order."The court's decision tonight to halt the federal government from providing relief is devastating to the thousands of Texas families that could have benefited from this program," Jessica Cisneros, an attorney for the advocacy organization the Texas Immigration Law Council, said Monday. Several families were notified of the receipt of their applications, according to attorneys advocating for eligible families who filed a motion to intervene earlier Monday."Texas should not be able to decide the fate of hundreds of thousands of U.S. citizens and their immigrant spouses without confronting their reality," Karen Tumlin, the founder and director of Justice Action Center, said during the press conference before the order was issued. The program has been particularly contentious in an election year when immigration is one of the biggest issues, with many Republicans attacking the policy and contending it is essentially a form of amnesty for people who break the law.Republican Texas Attorney General Ken Paxton cheered the order.

This is just the first step. We are going to keep fighting for Texas, our country, and the rule

Israel issues new evacuation orders in central Gaza, forcing more families to flee

Cairo/Gaza Israel issued new evacuation orders for Deir Al-Balah in the central Gaza Strip late on Sunday, forcing more families to flee, saying its forces intended to act against militant group Hamas and others operating in the area.

In recent days, Israel has issued several evacuation orders across Gaza, the most Later on Monday, an Israeli strike on a since the beginning of the 10-month war, prompting an outcry from Palestinians, the United Nations and relief officials over the reduction of humanitarian zones and the absence of safe areas. The Deir Al-Balah municipality says Israeli evacuation orders have so far displaced 250,000 people.In a statement posted on X, the Israeli military urged residents in certain zones to move immediately to the west, as the area they are in is "considered a dangerous combat zone".

Israeli military strikes killed at least seven Palestinians on Monday, medics said. Two were killed in Deir Al-Balah, where around a million people were sheltering, two at a

school in the Al-Nuseirat camp and three in the southern city of Rafah, near the border with Egypt.Seven others were killed in two separate Israeli strikes, five in a car in Khan Younis and two people at a school in Gaza City, medics said.

tent on the coast in Gaza City killed six Palestinians and wounded several other people, medics told Reuters. The new orders forced many families and patients to leave Al-Aqsa Hospital, the main medical facility in Deir Al-Balah, where hundreds of thousands

of residents and displaced people had taken shelter, for fear of bombardments. The hospital is close to the area covered by the evacuation notice. Médecins Sans Frontières (MSF) said in a statement on X on Sunday night that an explosion approximately 250 meters (820 feet) away from the MSFsupported Al-Aqsa Hospital triggered panic.



"As a result, MSF is considering whether to suspend wound care for the time being, while trying to maintain life-saving treatment."From around 650 patients, only 100 remain in the hospital, with seven in the intensive care unit, it said, citing Gaza's health ministry."This situation is unacceptable. Al Aqsa has been operating well beyond capacity for weeks due to the

All warring parties must respect the hospital, as well as patients' access to medical care," it added. The Israeli military said it killed dozens of Palestinian gunmen in the area of Khan Younis and the outskirts of Deir Al-Balah in the past 24 hours and located large quantities of weapons. The armed wings of Hamas and the Islamic Jihad said fighters clashed with Israeli forces with anti-tank rockets, mortar bombs,

lack of alternatives for patients

and sniper fire in several areas across Gaza.Gaza's Ministry of Health called for the 100 patients inside the hospital, and the medical teams who had remained to care for them, to be protected. In a separate statement, it said Israeli military strikes have killed at least 30 Palestinians and wounded 66 others across the enclave in the past 24

Nepal thanks BCCI for NCA training camp, featuring Rahul Dravid, Shami

New Delhi. Cricket Nepal has extended its heartfelt gratitude to the Board of Control for Cricket in India (BCCI) for facilitating a crucial training camp at the National Cricket Academy (NCA) in Bengaluru. The camp was part of Nepal's preparations for the upcoming ICC CWC League 2 series, set to take place in September.

The Cricket Association of Nepal (CAN) expressed its appreciation through social media, highlighting the significant support from BCCI Secretary Jay Shah and the Indian Cricket Board. The CAN acknowledged the role of Indian officials, including Indian External Affairs minister, Dr. S Jaishankar in making the camp possible. The NCA camp provided Nepal's national team with an invaluable opportunity to hone their skills and strategies ahead of their critical matches. The training program also featured interactions with notable Indian cricket figures, including former India head coach Rahul Dravid and pacer Mohammed Shami. Their presence and guidance were acknowledged in the thank you post shared



by CAN, underscoring the collaborative spirit between the two cricketing nations. This camp marks Nepal's second visit to India in 2024, following their previous engagements in Gujarat against Baroda as part of their T20 World Cup preparations. The focus of the Bengaluru camp was to bolster Nepal's readiness for the ICC Men's Cricket World Cup League 2, following a challenging tri-series at home earlier this year. With this enhanced preparation, Nepal is set to face Oman and Canada in their upcoming series, aiming to improve on their recent performances. The support from the BCCI and the experience gained from the NCA camp are expected to play a crucial role in Nepal's quest for success on the international stage.

US Open, Day 2 Schedule of Play: Alcaraz, Sinner, Swiatek in action

New Delhi After a tremendous opening day in the US Open, where a rusty-looking Novak Djokovic banked on his fitness to get through to the next round, the focus shifts on World No. 1 Jannik Sinner, who comes into the competition on the back of a doping controversy. Sinner, who tested positive twice for the banned substance clostebol, escaped a ban from The International Tennis Integrity Agency. There has been much chatter in the tennis world about different standards for different players after the Sinner episode and the Italian will have to shake everything off when he faces Mackenzie McDonald in his Round 1 match at the Arthur Ashe Stadium. Jannik Sinner has the likes of Daniil Medvedev and Carlos Alcaraz in his half of the men's singles draw, but his toughest challenge in New York will be shutting out the noise surrounding his doping case. Apart from Sinner, there are multiple big names who will take the court



on Tuesday, August 27. World No. 1 in women's singles - Iga Swiaktek will take on Kamilla Rakhimova in the first match of the day at the Arthur Ashe.

Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev and Stefanos Tsitsipas are some of the names that will participate on Tuesday. Alcaraz is coming off two frustrating tournaments - the Paris Olympics and the Cincinnati Open where he was beaten by Novak Djokovic and Frances Tiafoe respectively. Alcaraz's mettle will be checked on Tuesday when he takes on Australia Li Tu. Alcaraz will surely look for vengeance once he steps into the court in the United States of America. He has never faced Li Tu in his career but would hope to use this match to get in rhythm.

Harmanpreet, Smriti Mandhana lead India's strong 15-member squad for T20 World Cup

₩omen's T20 World Cup: India have announced a strong squad for the women's T20 World Cup, set to be held in the UAE. Harmanpreet Kaur is set to lead, while Smriti Mandhana will be her deputy as usual.

New Delhi. The Board of Control for Cricket in India announced India's squad for the Women's T20 World Cup on August 27, Tuesday. The Women's Selection Committee picked India's 15-member squad for the upcoming ICC tournament, set to be held in the United Arab Emirates. The ninth



the United Arab Emirates (UAE) from the 3rd to the 20th of October in Dubai and Sharjah. India are in Group A along with Australia, New Zealand, Pakistan, and Sri Lanka.

advertisement

Senior pros Harmanpreet Kaur and Smriti Mandhana have been named in the leadership group of the team. The team also includes the likes of Shafali Verma, Richa

Ghosh, Yastika Bhatiya and Renuka Singh. Spinner Asha Sobhana, who made her name in the Women's Premier League, finds a spot in the 15-member squad. The release further mentions that two key players for India -Yastika Bhatiya and Shreyanka Patil are currently injured and their availability for the tournament will depend on their fitness status.India's squad for the ICC Women's T20 World Cup 2024Harmanpreet Kaur (C),

victorious this time, winning alternate games to claim the match 2-1.Manika

returned to the table for the mixed doubles

round, partnering captain Alvaro Robles.

Puneri Paltan Table Tennis, meanwhile,

sent on Natalia Bajor and Anirban Ghosh,

who stretched the PBG Bengaluru

Smashers right until the end, only to fall to a

2-1 defeat. Robles followed his prolific

doubles display with a similar 2-1 win in

the second men's singles of the tie over

two-time Olympian Joao Monteiro. With

PBG Bengaluru Smashers needing just one

point to win the tie, USA paddler Lily Zhang

beat Puneri Paltan Table Tennis' sixth

different player on the night, Yashini

Sivashankar, to get her team over the

line. For their efforts, Manika and Zhang

were named the Indian and Foreign Player of

the Tie, respectively. Ankur, meanwhile,

claimed the DafaNews Shot of the Tie

honour. Tuesday's only tie will see the U

second win in UTT 2024.

Deepti Sharma, Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh (wk), Yastika Bhatia (wk)*, Pooja Vastrakar, Arundhati Reddy, Renuka Singh Thakur, Dayalan Hemalatha, Asha Sobhana, Radha Yadav, Shreyanka Patil*, Sajana Sajeevan.

*Subject to fitness clearance

Travelling Reserves: Uma Chetry (wk), Tanuja Kanwer, Saima ThakorNon-Travelling Reserves: Raghvi Bist, Priya MishraThe 23 matches in the tournament will take place at the Dubai International Cricket Stadium in Dubai and Sharjah Cricket Stadium in Sharjah. Dubai will host the first semi-final on October 17 followed by the second semis on October 18. There is a reserve day for both semifinals and the final. The grand final will

take place on October 20 in Dubai. Harmanpreet Kaur's India will face Fatima Sana's Pakistan in the marquee clash on October 6 in Dubai. India will also face New Zealand and Sri Lanka in Dubai on October 4 and 9 respectively. India's last and final league match against Australia on October 13 will take place in Sharjah. If India advances to the semis, they will feature in the first semi-final in Dubai.

Imran Khan slams Pakistan Cricket Board chief: 'Bangladesh defeat embarrassing'

New Delhi, Former Pakistan Prime Minister Imran Khan lashed out at the national cricket body, headed by Mohsin Naqvi, while expressing his disappointment with the performances of the senior national men's team. Imran did not mince words as he said the defeat to Bangladesh in a Test match in Rawalpindi was "embarrassing" and accused the Naqvi-led Pakistan Cricket Board (PCB) for "destroying" the sport in the country.

Imran Khan, who spoke to reporters from Adiala Jail - the Central Jail in Rawalpindi, highlighted the string of disappointing performances from Pakistan's senior national men's team in the recent past and pinned the blame on the current crop of administrators."Cricket is the onlysport the entire nation watches with great interest on TV, but even that has been destroyed by powerful quarters who brought in an unqualified, favoured official to maintain their control," Imran Khan said, as quoted by his X account."For the first time, we



(Pakistan) didn't make it to the top four in the World Cup or the top eight in T20. And yesterday, we faced an embarrassing defeat against Bangladesh, setting a new low. Just two-and-a-half years ago, this team had defeated India by 10 wickets. What has happened in these two-and-a-half years that we lost to Bangladesh by 10 wickets? The blame for all of this collapse falls on one institution," he added.Surgery till death: How Pakistan cricket fraternity reacted to Rawalpindi defeatImran Khan, who led Pakistan to their first and only ODI World Cup triumph in 1992, also accused Naqvi of corruption. The PCB chairman, who took control of the board in February 2024, also serves as the Federal Interior Minister of Pakistan.MOHSIN NAQVI FACES THE HEATNaqvi has been facing immense scrutiny from former Pakistan cricketers after Bangladesh stunned Pakistan in the first of a two-Test series in Rawalpindi on Sunday, August 25. The touring side clinched its first-ever Test match win over Pakistan and did it in style by hammering the hosts by

UTT 2024: Manika Batra trumps Ayhika Mukherjee as Bengaluru beat Puneri Paltan

Manika Batra led PBG Bengaluru Smashers to a 10-5 victory against Puneri Paltan Table Tennis in UTT 2024, overcoming Ayhika Mukherjee and securing crucial wins alongside teammates to clinch the match at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium.

New Delhi Star paddler Manika Batra survived the giant-slaying Ayhika Mukherjee to lead her team, PBG Bengaluru Smashers to 10-5 victory against Puneri Paltan Table Tennis in Ultimate Table Tennis 2024 at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium today. Manika lost the first game of her headline clash with Ayhika, falling into similar traps that had caught the league's highest-ranked player, Bernadette Szocs, last time around. However, the Asian and Commonwealth Games medallists retaliated in back-to-back games, winning the match 2-1. The franchise-based league is promoted by Niraj Bajaj and Vita Dani under the

New Delhi All-rounder Ravindra Jadeja will

miss the first round of the Duleep Trophy

2024 along with Mohammed Siraj and

Umran Malik, the Indian cricket board

(BCCI) said on Tuesday, August 27. While

Jadeja has been released from Team B, led

by Abhimanyu Easwaran, Siraj and Umran

Delhi fast bowler Navdeep Saini will replace

Siraj in Team B while Madhya Pradesh's

Gaurav Yadav will replace Umran Malik in

Team C, led by Ruturaj Gaikwad. The BCCI

did not reveal why Jadeja was released from the Team B squad for the first round of the

tournament. The first round of Duleep

Trophy, a premier four-day domestic cricket

tournament, will get underway from

September 5. Shubman Gill-led Team A will face Team B at the M Chinnaswamy

Stadium in Bengaluru while Team C will

take on Shreyas Iyer-led Team D in Rural Development Trust Stadium A in

have been ruled out due to illness.



auspices of the Table Tennis Federation of India (TTFI). Puneri Paltan Table Tennis made UTT history even before the opening serve dropped. The team from Pune became the first ever to name all six of their players in the starting line-up, spread across five matches. The tie started with 17-year-old Jeet Chandra. Both Ankur and Jeet had recorded outstanding sweeping wins in their previous clashes in UTT 2024 - Ankur over

Duleep Trophy 2024: No Jadeja, Siraj and

Ankur Bhattacharjee of Puneri Paltan Table Tennis taking on PBG Bengaluru Smashers' Lilian Bardet and Jeet over Sharath Kamal -

Umran to miss 1st round due to illness two Tests against Bangladesh from September 19 to October 1 to kickstart their

home season. REVISED SQUADS FOR DULEEP TROPHY FIRST ROUND India A: Shubman Gill (C), Mayank Agarwal,

Riyan Parag, Dhruv Jurel (WK), KL Rahul, Tilak Varma, Shivam Dube, Tanush Kotian, Kuldeep Yadav, Akash Deep, Prasidh Krishna, Khaleel Ahmed, Avesh Khan, Vidwath Kaverappa, Kumar Kushagra, Shaswat Rawat.India B: Abhimanyu Easwaran (C), Yashasvi Jaiswal, Sarfaraz Khan, Rishabh Pant (WK), Musheer Khan, Nitish Kumar Reddy*, Washington Sundar, Navdeep Saini, Yash Dayal, Mukesh Kumar, Rahul Chahar, R Sai Kishore, Mohit Kumathi, N. Lacadasan (WK) India Garage (WK) India Gara Awasthi, N Jagadeesan (WK).India C: Ruturaj Gaikwad (C), Sai Sudharsan, Rajat Patidar, Abishek Porel (WK), Suryakumar Yadav, B Indrajith, Hrithik Shokeen, Manav Suthar, Gaurav Yadav, Vyshak Vijaykumar, Anshul Khamboj, Himanshu Chauhan, Mayank Markande, Aryan Juyal (WK),



feature in domestic cricket while not on

international duty. Rohit Sharma, Virat

Kohli, Jasprit Bumrah and R Ashwin were

allowed to miss the first-round matches,

Dabang Delhi TTC and Athlead Goa Challengers face off in a high-stakes IndianOil UTT 2024 clash, with star paddlers Sathiyan Gnanasekaran and Harmeet Desai leading their teams in a crucial battle for playoff contention.

Both Dabang Delhi TTC and Athlead Goa Challengers will have a point to prove when they meet for the first time in ÎndianOil Ultimate Table Tennis 2024 at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium on



Wednesday. Led by Sathiyan Gnanasekaran, the team from Delhi has lost both its ties so far. However, the low margins of their defeats mean Dabang Delhi TTC are one heavy win away from jumping from their

current spot in seventh to one reserved for the playoffs. Harmeet Desai's Athlead Goa Challengers, on the other hand, are heading into their tie against Dabang Delhi TTC on the back of a heavy defeat against

Ahmedabad SG Pipers; they will be looking to make amends quickly and prove their mettle as the reigning champions. Sathiyan's potential bout with Harmeet will headline the clash between Dabang Delhi TTC and Athlead Goa Challengers. The pair are two of India's finest paddlers and have an Olympic appearance each to their name.Further down the pecking order, Dabang Delhi TTC's Diya Chitale will be under the spotlight following her impressive win against Poymantee Baisya of Chennai Lions. She will likely square up against Athlead Goa Challengers' young prodigy looking to make her mark this season: Yashaswini Ghorpade.From the teams' foreign contingent, all eyes will be on Athlead Goa Challengers' Yangzi Liu and her sensational unbeaten streak that has not left her company since the start of the previous season. Liu has won both her singles matches in IndianOil UTT 2024 and will look to prolong that run in a potential clash against Dabang Delhi TTC's Orawan

Wednesday, 28 August 2024



hangalaan actress Parvathy Thiruvothu, during a press event in Mumbai, fondly remembered late actor Irrfan Khan, with whom she shared screen space in Qarib Qarib Singlle. Looking back on her time working with Irrfan and filmmaker Tanuja Chandra on the 2017 film, Parvathy expressed her deep connection with Mumbai, a city she said she had shifted to before Covid-19 hit. Drawing analogy between Vikram and Irrfan, Parvathy said it's their generosity that she finds heartwarming.Parvathy said, "I guess it's the generosity, for sure, that I see in both of them. Irrfan sir used to help me out with things because Hindi is not my native language. So he used to help me get into that space and made sure that everyone knew you are as good as the other person on set. And I saw that generosity in him [Vikram]. And when I worked with him... it expands further away from even actors. It's everybody on set."

Parvathy also shared an interesting anecdote from the sets of Thangalaan. She said, "I miss getting all the toffees! Like, there is a particular native toffee that we get there and it's called Kamarkat. It's like this jaggery, palm sugar, kind of a thing. And he'd just be walking around and he'd shake hands. Suddenly you have a toffee in your hand! He just brightens the mood for everybody. Not just me, the kids obviously and others as well. But, the way he asks everybody, 'Have you eaten?' It's not for show. Genuinely, there's a concern how everyone is doing.

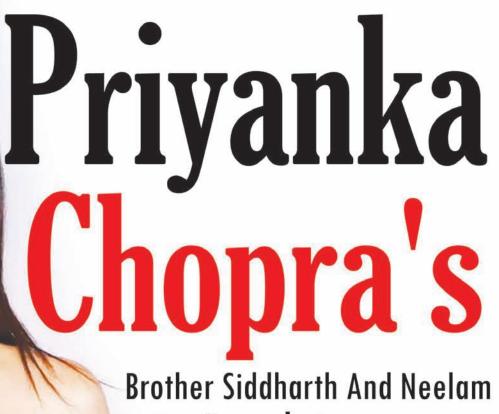
Mira Rajput's Birthday Post For Her 'Darling Girl' Misha Is Love



hahid Kapoor's wife, entrepreneur and influencer, Mira Rajput is a hands-on mother to her kids Misha And Zain. Today, Mira is super excited. Reason? It's Misha's birthday. She turns 8. Mira, on her daughter's special day, made sure to proudly express her love for her little bundle of joy. In a post on Instagram, she attached a set of endearing pictures with Misha. The photos captured Misha all smiling in an all-white coord set with a pink jacket tied around her waist. The final image featured the birthday girl with Mira as they posed happily for the camera.Sharing the album, Mira Rajput wrote, "I will spend my whole life loving you. Happy 8th Birthday our darling girl. Sunshine, sparkles and the best of everything for the light of our lives. Smile forever my baby girl, Misha."

Hours before the birthday, Mira Rajput and Misha were spotted by paparazzi. The duo was seen stepping out after their salon visit. The clip that surfaced on social media captured Misha running ahead of her mother, quickly boarding the car as Mira followed her. Mira, for her salon visit, wore a plain black T-shirt with blue bell-bottom jeans. On the other hand, her daughter looked cute in a simple white dress. Misha is a constant on Mira Rajput's Instagram. Not long ago, the mother-daughter attended Taylor Swift's Eras Tour concert in Munich. The mommydaughter took a selfie at the concert and even rooted for the pop star as she performed on some of her chartbusters. "Core memory with my sunshine swiftie. We couldn't believe it! Mother-daughter trip of dreams," Mira wrote. Shahid Kapoor and Mira Rajput got married in 2015. The couple welcomed Misha in 2016. In 2018, they were blessed with a son, Zain.

In terms of career, Mira Rajput recently launched her skincare line, Akind.As for Shahid Kapoor, he is preparing for Deva opposite Pooja Hedge. Directed by Rosshan Andrrews, the film is set to release on October 1. Additionally, he also has Vashu Bhagnani's mythological epic, Ashwatthama: The Saga Continues.



Upadhyaya's Engagement **Photos Scream Love**

opular chef and producer Siddharth Chopra, who is also Priyanka Chopra's brother, recently tied the knot with his fiancee and actress Neelam Upadhyaya. On Monday, the couple gave their followers a glimpse into their "hastakshar ceremony" with a joint post featuring stunning photos from the joyous occasion. The photo album, filled with affectionate shots of the newlyweds and scenes from the ceremony, shows the couple's special moments. In the photos, Neelam looked stunning in a pink lehenga adorned with intricate golden designs, while Siddharth complemented her perfectly in a golden sherwani paired with a coordinating half coat. In the first picture, Siddharth gently kisses Neelam, who beams with joy. The second image captures the couple posing gracefully for the cameras. They proudly show off their engagement rings in the following shot, leading to a series of romantic photos, including one where they embrace each other. The final two pictures highlight moments from their hastakshar or registry ceremony.

Following the post, Siddharth's younger brother, Sahaj Chopra, extended a warm welcome to Neelam with a heartfelt message saying, "Congratulations both welcome to the family Neelam Upadhyaya." Fans and celebrities quickly joined in to congratulate the couple in comments section.Priyanka Chopra also travelled to Mumbai to attend the special event.A fan page also shared an exclusive video from the ceremony, showing Siddharth and Neelam exchanging rings and touching Priyanka's feet for blessings. The video also features some family moments with Madhu Chopra, Mannara and others.



Earlier this year, in April, Siddharth and Neelam had their roka ceremony, which they announced with beautiful pictures. The album included some cosy shots of the couple, individual pictures and a special cake inscribed with "just rokafied." They captioned the post "Sooo we did a thing." Previously, Siddharth was engaged to Ishita Kumar. Their roka ceremony took place in New Delhi in February 2019 and was attended by Priyanka Chopra and her husband, Nick Jonas. However, the engagement was reportedly called off in June. Soon after, Siddharth and Neelam made their first public appearance together at the Ambani's Ganesh Puja in 2019.

Neena Gupta

Is The Cutest Nani-To-Be And This Video From Masaba Gupta's Baby Shower Is Proof

asaba Gupta's baby shower took place on Sunday. The biscuit-themed ceremony was hosted by Sonam Kapoor. Rhea Kapoor, Soni Razdan, Shaheen Bhatt, Akansha Ranjan -Kapoor, chef Pooja Dhingra, Neena Gupta and Masaba's husband Satyadeep Misra were also part of it. While many pictures and videos from the event are making rounds on the Internet, one clip in particular is sure to leave you in awe. It has Neena humorously schooling the younger generation about their sartorial choices. The video was originally posted by one of Masaba Gupta's friends Nimish. Later, Neena Gupta also shared it on Instagram Stories. Standing amid the guests seated on comfy couches, the veteran star is seen giving a speech. The nani-to-be, while advising the younger ones to dress up as per the occasion, had



everyone laughing as she cutely scolded her son-in-law Satyadeep Misra for wearing jeans instead of white pants to the party. "I told him not to wear jeans. White pant pehen leta (He could have worn white pants)," Neena said.

Masaba Gupta also gave a speech at her baby shower a snap of which was shared by her friend and renowned stylist Tanya Ghavri. Dropping the picture, she wrote, "To the cutest mama to be at her baby shower! (sic)."Masaba Gupta also shared a bunch of pictures from her special day. Taking to her Instagram stories, she posted a picture with

Sonam Kapoor and Rhea Kapoor. While Rhea is hugging the expectant mother in the image, Sonam is leaning on her sister for an endearing click. Masaba chose to make heads turn in a brown full-length gown, complemented by a few dainty pieces of jewellery for her baby shower

Masaba Gupta announced her pregnancy in April this year. In a joint Instagram post with husband Satyadeep Misra, she wrote, "In other news - Two little feet are on their way to us! Please send love, blessings and banana chips (plain salted ONLY) #babyonboard #mom&dad (sic)."